हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक बुधवार, दिनांक 14 मार्च, 2018 को अध्यक्ष, डॉ0 राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

14.03.2018/1100/जेके/एचके / 1

प्रश्न संख्याः 79

श्री बलबीर सिंह वर्माः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के अन्दर पाइपों का जो क्रय होता है उसकी क्या प्रक्रिया है? मैंने प्रश्न किया था उसका विस्तार से उत्तर नहीं आया है। मैं जानना चाहता हूं कि 2012 से 2018 तक कुल कितनी पाइपें क्रय की गई? सभी प्रकार की पाइपों का ब्यौरा कृपया मंत्री जी दें। रेट कांट्रेक्ट में जो एच0डी0पी0ई0 पाइपें ली जाती हैं क्या यह रेट ओपन मार्किट से ज्यादा होता है? क्या कारण है कि 40mm की पाइपें ज्यादा क्रय की जाती है? जबकि हर लाइनों के लिए ज्यादा जरूरत 15mm,20mm,25mm और 32mm की होती है?

अध्यक्षः माननीय सदस्य तीन प्रश्न हो गए। इसके बाद और पूछ लेना।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जी ने जानना चाहा है कि पाइप को क्रय करने की क्या प्रक्रिया है? बजट में जितना भी प्रोविज़न किसी भी कार्य के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा रखा जाता है और दूसरे बहुत ऐसी परियोजनाएं होती हैं जो कि भारत सरकार से स्वीकृत हो करके आती हैं। तीसरा ऐसे बहुत डिपोजिट्स हैं, चाहे बैकवर्ड एरिया सब प्लान की तरफ से आएं एम0पी0 लैड की तरफ से आएं, एम0एल0ए0 फंड की तरफ से आए या ऐसे बड़े-बड़े प्रोजैक्ट्स जो भारत सरकार से स्वीकृत हो करके आते हैं और वे सारे प्रोजैक्ट्स क्योंकि विभाग की कार्यशाली पूर्ण रूप से पाइप के ऊपर निर्भर करती है तो जितना टोटल अमाउंट होता है, उसका 35 परसेंट पाइपों की परचेजिंग के लिए रखा जाता है। पाइप परचेज़ करती बार हर मण्डल में पाइप परचेज़ कमेटी बनी होती है। मण्डल की कमेटी से रिकमैंड हो करके फिर सर्कल लैवल पर पाइप परचेज कमेटी होती है। फिर सर्कल लैवल से ज़ोन स्तर की पाइप परचेज़ कमेटी होती है और फिर जोन से सारा इकट्ठा हो करके जैसे कि हिमाचल प्रदेश के अन्दर चार जोन हैं, चारों जोन्ज़ से जो रिक्वायरमैंट है, वह फिर प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

14.03.2018/1100/जेके/एचके / 2

के पास पहुंचती है। उनके पास पहुंचने के उपरान्त फिर प्रदेश स्तर की स्क्रीनिंग कमेटी बनी होती है और सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में उसकी मीटिंग होती है । उसकी मीटिंग होने के उपरान्त फिर हमने कितनी पाइपें वित्तीय वर्ष के लिए क्रय करनी है, उन पाइपों को क्रय करती बार जब स्क्रीनिंग कमेटी क्लीयर कर देती है फिर ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। जैसे ही ई-टेंडरिंग होती है और ई-टेंडरिंग में उसकी दो बिड़ज़ ली जाती है। एक टैक्निकल बिड होती है और दूसरी फाईनैंशियल बिड होती है। जैसे ही टेंडर खुलता है सबसे पहले टैक्निकल बिड खोली जाती है। जब टैक्निकल बिड खोली जाती है तो उसकी जो गाइड लाइन हैं, उसमें कौन-कौन सी कम्पनीज़ क्वालिफाई करती है। जो-जो कम्पनीज़ उसमें क्वालिफाई करती है

14.03.2018/1105/SS-HK/1

प्रश्न संख्याः 79 क्रमागत

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री क्रमागतः

फिर उन्हीं की फाइनेंशियल बिड खोली जाती है और जब फाइनेंशियल बिड खोली जाती है तो उसके उपरांत उसका जायजा लिया जाता है। जायजा लेने के साथ-साथ फिर उसमें देखा जाता है, जैसे कि मैंने कहा कि एक टेक्निकल बिड है, उसमें टर्नऑवर 50 करोड़ का है या नहीं। किसी भी फर्म का तीन साल में 50 करोड़ का टर्नऑवर होना चाहिए। दूसरी उसमें तकनीकी बात यह है कि एक वर्ष में उस कम्पनी ने 10 करोड़ की पाइपें बेची होनी चाहिए। तीसरा, उसमें अर्नैस्ट मनी 25 लाख रुपये होगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, इन तीनों चीज़ों को पूरा करने के उपरांत फिर अगली प्रक्रिया शुरू होती है। जब फाइनेंशियल बिड खुलती है तो उसके उपरांत हम देखते हैं कि इसमें एल-। कौन आ रहा है। जो एल-। होगा उसके पास कितनी कैपेसिटी है कि वह कितनी पाइप्स किस-किस डाया की जो हमारे प्रदेश की रिक्वायरमैंट है, हमारे यहां से रिक्विजिशन गई हुई है, क्या वह उस सारी रिक्वायरमैंट को पूरा कर सकती है या नहीं कर सकती है। अगर वह पूरा कर सकती है तो

उसी का ऑर्डर बनेगा। अगर नहीं कर सकती है तो फिर एल-। के ही रेट्स पर जो एल-2, एल-3 है फिर उनको भी उस मात्रा में ऑर्डर दिए जाते हैं। ऑर्डर देने से पहले, मैं थोड़ा-सा इससे पीछे जाना चाहूंगा कि एक नेगोशियेशन कमेटी होती है और प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य के द्वारा नेगोशियेशन की जाती है। नेगोशियेशन होने के बाद फिर फ्रदर ऑर्डर दिये जाते हैं। यह तो प्रक्रिया है कि कैसे पाइपें क्रय की जाती हैं। माननीय सदस्य ने दूसरी बात एच0डी0पी0ई0 के बारे में की है। जो हमारी जी0आई0 पाइप है वह हम इस प्रकिया से परचेज करते हैं लेकिन जो हमारी एच0डी0पी0ई0 पाइप है उस पाइप के रेट कंट्रैक्ट कुछ फर्मों के रजिस्टर्ड हैं, उस रेट कंट्रैक्ट के मुताबिक हम उनसे पाइपें लेते हैं। आपने एक शंका जाहिर की है कि रेट कंट्रैक्ट का रेट और ओपन मार्किट के रेट में कोई अन्तर हो सकता है। <u>निश्चित तौर पर इस पर विचार किया जायेगा, सोचा जायेगा कि अगर ओपन मार्किट में रेट कम है और रेट कंट्रैक्ट ज्यादा है तो इस पर विचार किया जायेगा।</u> <u>अगर ऐसी स्थिति होगी, क्योंकि रेट कंट्रैक्ट आई0पी0एच0 विभाग नहीं करता है, डी0जी0 एंड एस0डी0 के द्वारा रेट कंट्रैक्ट किये जाते हैं इस करके इस पर मैं सदस्य जी को आश्वासन देना चाहता हूं कि इस पर हम विचार करेंगे।</u>

14.03.2018/1105/SS-HK/2

श्री बलबीर सिंह वर्माः सर, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि डिपार्टमैंट सबसे ज्यादा परचेजिंग 40 एम0एम0 की पाइपों की करता है। जबकि ग्राऊंड लेवल पर 15 एम0एम0, 20 एम0एम0, 25 एम0एम0 और 32 एम0एम0 की ज़रूरत होती है और क्वांटिटी में सबसे ज्यादा आप 40 एम0एम0 की पाइपें लेते हैं।

दूसरा, मैं माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि पाइप भी परचेज कर दी और आ भी गई लेकिन पाइपों का जो डिस्ट्रिब्यूशन है वह इतना डिफैक्टिव है कि सबसे पहले वहां दी जाती है जो पावरफुल लोग होते हैं। जहां इंटीरियर है, दूर-दराज के क्षेत्र हैं जैसे कि मेरा चौपाल है वहां पर पाइपें बहुत कम पहुंचती हैं। क्या माननीय मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि जो दूर-दराज के क्षेत्र हैं, इंटीरियर क्षेत्र हैं सबसे पहले पाइपों का डिस्ट्रिब्यूशन उस क्षेत्र में किया जायेगा?

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष जी, इन्होंने एक बात कही है कि जो छोटे डाया की पाइपें हैं वे कम क्रय की जाती हैं। जब भी कोई स्कीम प्रदेश के अंदर बनती है, किसी

योजना का काम शुरू होता है तो बाकायदा उसका डिटेल्ड एस्टीमेट बनता है। उसकी डिजाइनिंग होती है। उसकी ड्राइंग होती है। उसमें डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम अलग होता है। उसका राइजिंग मेन सिस्टम अलग होता है। उसमें जिस-जिस डाया की पाइप की रिक्वायरमैंट आती है उस-उस रिक्वायरमैंट के मुताबिक पाइप क्रय की जाती है। लेकिन आपने एक बात कही है कि छोटे डाया की पाइपों की रिक्वायरमैंट ज्यादा है निश्चित तौर पर जब हम फील्ड में जाते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि हमारा नलका लगा दो, हमारी छोटी लाइन हाफ इंच डाया की है इसको पौने इंच कर दो। पौना इंच वाला कहता है कि एक इंच कर दो। एक इंच वाला कहता है कि सवा या डेढ़ इंच कर दो।

14.03.2018/ 1110/केएस/वाईके/1

प्रश्न संख्याः79 जारी----

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री जारी-----

वैसे इस वित्तीय वर्ष 2017-18 की पाईप क्रय करने की परचेज़ कमेटी की लास्ट मीटिंग कल ही होने वाली है उसमें आपका जो सुझाव है कि छोटे डाया की पाइपें ज्यादा ली जाए, उसको ध्यान में रखा जाएगा और साथ में आपने दूर-दराज के क्षेत्रों की बात की तो दूर-दराज और नज़दीक का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, हमने कहा है कि जो स्क्रीनिंग कमेटी है, वह मण्डल लैवल की बनी हुई है । मण्डल लैवल, जोन लैवल, सर्कल लैवल से सारी रिक्वायरमैंट्स आ कर फिर प्रमुख अभियंता के पास पहुंचती है फिर उसके मुताबिक ही हम पाइप परचेज़ करते हैं।

श्री सुरेश कुमार कश्यपः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या कारण है कि वर्ष 2015-16 में 3,42,191 मीटर पाइप 106 करोड़ रुपये में खरीदी गई? अगले वर्ष 2016-17 में 01,07,131 मीटर पाइप 312 करोड़ रुपये में खरीदी गई और 2017-18 में 72,327 मीटर पाइप 21 करोड़ रुपये में क्रय की गई? मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि वर्ष 2016-17 में क्यों कम लम्बाई की पाइपों को 312 करोड़ रुपये में क्रय किया गया? साथ ही मंत्री महोदय मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या यह सत्य है कि जो

Providing & Laying में सी.वी.सी. की गाईड लाइन्ज़ थी उनको भी बदला गया है? क्या मात्र दो कम्पनियों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया है और क्या मंत्री महोदय इसकी जांच करवाएंगें?

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जी ने जो जानना चाहा है कि 2015-16 में जो पाइप 3,42,191 रनिंग मीटर खरीदी गई और जिसकी कास्ट 105,52,90,668 थी। 2016-17 में क्वांटिटी क्रय की गई वह 1,07,131 थी जिस पर अमाउंट आया 312,18,07,785 और जो 2017-18 में क्वांटिटी खरीदी गई यह थी 72,327 रनिंग मीटर और इस पर अमाऊंट 20,78,53,399 है ।

14.03.2018/ 1110/केएस/वाईके/2

अध्यक्षः मंत्री जी, अगर आपको इसमें कोई शंका है तो इसको आप फरदर चैक कर लें ।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, इसमें कुछ शंका मुझे भी है और वह इसलिए है कि जब हम 3,42,191 मीटर पाइप खरीदते हैं तो उसकी कीमत 105 करोड़ बनती है । जब हम एक लाख सात हजार रनिंग मीटर खरीदते हैं, इससे तीन गुणा कम खरीदते हैं तो उसकी कीमत 312 करोड़ होती है। वैसे मुझे भी लग रहा है कि यह गलत है और जब 2017-18 में 72,327 रनिंग मीटर खरीदी जाती है तो उसकी कीमत 20 करोड़ है। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित तौर पर इसकी छानबीन करवाएंगें कि इतना बड़ा गैप क्यों है?

14.3.2018/1115/av/yk/1

प्रश्न संख्या : 79---------- क्रमागत

श्री सुरेश कुमार कश्यप : माननीय मंत्री जी, क्या प्रोवाइडिंग एण्ड लेईंग में सी0वी0सी0 की गाइडलाइन्स को चेन्ज किया गया है?

सिंचाई एंव जन स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष जी, निश्चित तौर पर सैंटर विजिलैंस कमीशन की गाइडलाइन्स भारत सरकार से आती है और इस गाइडलाइन्स को वर्ष 2015-16 में चेन्ज किया गया है। सैन्टर विजिलैंस कमीशन की गाइडलाइन्स के अनुसार इसमें ज्वाईंट वैंचर का प्रावधान था कि दो-तीन फर्में इकट्ठी हो करके किसी काम को कर सकती है। हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा राज्य होने के नाते हमारे लोगों की फाइनैंशियली इतनी केपेसिटी नहीं है कि वह अकेले तौर पर बड़े-बड़े काम ले सके इसलिए सी0वी0सी0 गाइडलाइन्स के तहत पूरे देश को अलाऊ किया गया था। लेकिन यहां पर इसके साथ छेड़छाड़ हुई है जिसके कारण हिमाचल प्रदेश में बाहर की कुछेक कम्पनियां ही रह गई हैं और यहां बाहर की कम्पनियां ही बड़ी-बड़ी स्कीमों का काम करती रहीं। यह जांच योग्य है कि सी0वी0सी0 गाइडलाइन्स के साथ क्यों छेड़छाड़ की गई और हम इस बारे में निश्चित तौर पर छानबीन करेंगे कि सी0वी0सी0 की गाइडलाइन्स के साथ छेड़छाड़ करने की आवश्यकता क्यों पड़ी?

श्री नरेन्द्र ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने यहां पर पाइप क्रय करने का जो मापदण्ड बताया है वह बड़ा कोम्पलिकेटिड लग रहा है। क्या मंत्री जी भविष्य में इसके सरलीकरण के बारे में कुछ सोचेंगे? दूसरा, जैसे यहां पर बताया गया कि हर साल करोड़ों रुपये की पाइप्स खरीदी जाती हैं और इन पाइप्स की खरीद में बहुत भारी बजट लगता है। क्या हम यह आशा कर सकते हैं कि भविष्य में विभाग या सरकार अपने यहां पर ही कोई फैक्ट्री लगाकर के पाइप्स तैयार करें क्योंकि ऐसा करने से प्रदेश का बहुत सारा बजट बच सकता है। तीसरा, इसमें तीन सालों में 50 करोड़ रुपये का टर्नओवर और एक साल के अन्दर कम-से-कम 10 करोड़ रुपये की पाइप्स बेचने की जो शर्त रखी गई है क्या मंत्री महोदय इसको भी कम करने का विचार रखते हैं?

14.3.2018/1115/av/yk/2

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैंने पहले कहा है कि जो कम्पनीज तकनीकी बिड में क्वालीफाई करती है और उसके बाद जब वह फाइनैंशियल बिड के लिए

जाती है तो उसमें उनका टर्नओवर 50 करोड़ रुपए का रखा गया है। उसमें दूसरी शर्त जैसे मैंने पहले भी कहा है कि उन्होंने एक साल के अन्दर 10 करोड़ रुपये की पाइप्स बेची होनी चाहिए। माननीय सदस्य का सुझाव है और मुझे भी लगता है कि हमें इसमें थोड़ी रिलेक्सेशन देनी चाहिए और रिलेक्सेशन इसलिए देनी चाहिए क्योंकि हो सकता है कि हमारे प्रदेश के अन्दर भी ऐसे कई छोटे-छोटे उद्योग हो सकते हैं जिनका टर्नओवर इतना ज्यादा नहीं होता होगा। कल हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है जिसमें हम इस विषय को भी ले जायेंगे ताकि वहां पर इस बारे में कुछ रिलेक्सेशन दी जा सके।

अध्यक्ष : अगला अनुपूरक प्रश्न मुकेश अग्निहोत्री जी करेंगे और इस प्रश्न की लास्ट सप्लीमैंटरी श्री बलबीर जी करेंगे जिन्होंने यह प्रश्न किया है।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, पूर्व शासन में जो पाइप्स खरीदी गईं क्या यह सारी रेट कॉंट्रैक्ट के मुताबिक खरीदी गई? यहां पर जैसे कि माननीय सदस्य श्री बलबीर जी ने कहा कि रेट कॉंट्रैक्ट ज्यादा है और बाजार में रेट सस्ता है। इसलिए क्या आप सदन में आश्वासन देंगे कि रेट कॉंट्रैक्ट एजैंसी को इस तरह के निर्देश दिए जायेंगे कि अगर बाजारी रेट सस्ता है तो जिन लोगों ने रेट डाला है उनसे यह आग्रह किया जाए कि बाजारी रेट पर ही रेट कॉंट्रैक्ट हो।

14.3.2018/1120/TCV/AG-1

प्रश्न संख्याः 79 .. क्रमागत्

माननीय सिंचाई एंव जन स्वास्थ्य मंत्रीः आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अग्निहोत्री जी ने जो रेट कांट्रेक्ट की बात कही है, मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट किया है कि रेट कांट्रेक्ट आई0पी0एच0 विभाग तय नहीं करता है। लेकिन ऐसी शिकायतें आई हैं। माननीय अध्यक्ष जी रेट कांट्रेक्ट में हम जो पाईपें लेते हैं, वह हम एच0डी0पी0 की पाइपें लेते हैं, लेकिन कुछेक और पाइपें भी लेते हैं। इसलिए निश्चित तौर पर इस पर विचार किया जाएगा। यदि ओपन मार्किट में कोई आइटम सस्ती मिल रही है और रेट कांट्रेक्ट में वह महंगी है, तो हम रेट कांट्रेक्ट के अंदर इसको लेने के लिए बाध्य नहीं होने चाहिए। हम ओपन मार्किट से ई-

टैंडरिंग के माध्यम से जो सस्ता और बढ़िया क्वालिटी का सामान देगा, हम उसको वहां से लेंगे।

श्री बलबीर सिंह वर्माः माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि ये जो पाइप, पम्प और अन्य मशीनरिज़ हैं, कुछ स्कीमें पिछले 10 सालों से चल रही है, जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई हैं। इनमें से कुछ में पाईपें बिछ गई, पम्पिंग मशीनें 10 साल पहले आ गई और पाईपें अब बिछ रही हैं।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, पाईपों और पम्पिंग मशीनों का जवाब आ गया था।

श्री बलबीर सिंह वर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि चौपाल में जो नेरवा डिवीज़न है, पिछले एक साल के अंदर कोई भी पाइप वहां पर नहीं पहुंची है। क्या आने वाले सालों में वहां के लिए पाईपें दी जाएगी?

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछली सालों के बारे में तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, माननीय सदस्य श्री अग्निहोत्री जी सामने बैठें है। पीछे इनको पाईपें नहीं मिली, तो उसके लिए तो हमारी सरकार जिम्मेवार नहीं है, लेकिन भविष्य में नेरवा के साथ या किसी भी मण्डल के साथ, किसी भी विधान सभा क्षेत्र के साथ, किसी भी प्रकार का भेदभाव आदरणीय जय राम ठाकुर जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं करेगी। जो-जो, जहां-जहां की रिक्वा.जिशन होगी, वहां पर वह मटिरीयल पहुंचा दिया जाएगा।

14.3.2018/1120/TCV/AG-2

प्रश्न संख्याः 80

श्री हर्षवर्धन चौहान (प्राधिकृत)ः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ये जो 2 डिग्री कॉलेज तेलका और भलेई हैं, ये फंक्शनल भी हो चुकें हैं और इसमें 50-60 विद्यार्थी भी हैं। इसके लिए जो लैंड ट्रांसफर होनी है, वह किस स्टेज पर हैं? कुछ प्राइवेट लैंड भी डूनेट की गई है और कुछ सरकारी लैंड भी हैं। मैं मंत्री जी से जाना चाहूंगा कि जो गवर्नमैंट लैंड है जिसकी वन विभाग से क्लीयरेंस होनी है, वह किस स्टेज पर हैं?

क्या आप आश्वासन देंगे कि एफ0सी0ए0 का केस जल्दी-से-जल्दी परस्यू करके इसकी सैंक्शन दी जाएगी, ताकि एक सुन्दर भवन इन दोनों डिग्री कॉलेज में बनकर तैयार हो सकें।

शिक्षा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, 2 कॉलेज़िज डलहौजी विधान सभा क्षेत्र में 4 मई, 2017 को नोटिफाई किए गए हैं। उनमें से एक भलेई कॉलेज है, इसके लिए 12 बीघा फॉरेस्ट लैंड़ है, जो आईडैंटीफाई की गई है और इस कॉलेज के साथ ही 8 बीघा ज़मीन प्राइवेट लैंड हैं। जिसके लिए ज़मीन देने के एफिडेविट ही अभी तक विभाग को प्राप्त हुए हैं। यदि लैंड कम हो तो डी0एफ0ओ0 को पॉवर है कि वह उसको सैंक्शन कर सकता है, क्योंकि यह ज़मीन ज्यादा है, इसलिए इसको देहरादून फॉरेस्ट क्लीयरेंस के लिए भेज दिया जाएगा। जो दूसरा कॉलेज है, वह तक्कीपुर में है, वहां पर प्राइवेट लैंड अभी तक नहीं है।

14-03-2018/1125/NS/AG/1

प्रश्न संख्याः 80-----क्रमागत।

शिक्षा मंत्री ------जारी

फोरेस्ट लैंड की इंस्पैक्शन एस0डी0एम0 की अध्यक्षता में जो कमेटी है, उसने कर दी है। एफ0आर0ए0 का केस बनाया जा रहा है। क्योंकि ज्यादा ज़मीन है इसलिए एफ0आर0ए0 की परमिशन के लिए देहरादून भेजी जा रही है। इस पर कार्य चल रहा है। लेकिन वास्तव में जब ये कॉलेज नोटिफाई किये गये थे, उसमें लगभग 5 करोड़ रुपये की राशि की एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दे रखी है। एक्चुअल में राशि केवल एक लाख रुपये तक दी गई है। दोनों कॉलेजों को एक-एक लाख रुपये की राशि दी गई है। एक कॉलेज में स्टूडैंट्स की संख्या 70 है और दूसरे कॉलेज में 58 है। सरकार को जब लैंड अवलेवल हो जायेगी और इसकी एफ0आर0ए0 की परमिशन मिल जायेगी तो इस पर आगामी कार्रवाई की जायेगी।

14-03-2018/1125/NS/AG/2

प्रश्न संख्याः 81

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़ा हुआ है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। अभी उनका चयन हिमाचल प्रदेश विधान सभा से राज्यसभा के लिए सर्वसम्मति से हो रहा है। परम्पराओं के मुताबिक, जब आनंद शर्मा जी वाणिज्य मंत्री थे तो उनके मुकाबले में आपने कोई उम्मीदवार नहीं दिया था, उसी तरह से कांग्रेस विधायक दल ने भी इसी तर्ज़ पर चलते हुए कोई उम्मीदवार नहीं दिया है। लेकिन हमारी मंशा है कि एम्ज़ उनसे जुड़ा हुआ है, यह बनना चाहिए। केंद्र की सरकार का चार वर्ष का कार्यकाल हो गया है। हालांकि उस तरफ (सत्ता पक्ष) जो लोग बैठे हैं, ये इस बात को ले करके काफी क्रिटिक्स हैं कि चुनाव के आसपास बहुत शिलान्यास हुए हैं और स्टोन भी रखे गये हैं। एम्ज़ का शिलान्यास भी माननीय प्रधान मंत्री जी ने किया है और यह शिलान्यास 03 अक्तूबर, 2017 को किया गया है जबकि 12 अक्तूबर, 2017 को कोड ऑफ कंडक्ट लग रहा था। आप हमें लगातार नसीयत तो दिये जा रहे हैं, "औरों को नसीयत खुद मियां फज़ीयत।" आपने भी एक हफ्ता पहले फाउंडेशन स्टोन रखा है। लेकिन अब माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी ने इसमें कहा है कि यह केंद्र से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है और इसके बारे में केंद्र सरकार ही बता पायेगी। अध्यक्ष महोदय, बड़ा मसला यह है कि आर0टी0आई0 और अखबारों में जबाव आ जाते हैं। लेकिन इस माननीय सदन में जबाव नहीं आते हैं। एम्ज़ को ले करके लगातार अखबारों में छप रहा है कि लगभग 1385 करोड़ रुपये की राशि केंद्र सरकार ने दे दी है। इसके बारे में सरकारी पक्ष से जिम्मेदार लोगों के बयान भी आ रहे हैं। लेकिन जब हम पूछते हैं तो ये कहते हैं कि इसके बारे में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री या केंद्र सरकार ही बात पायेगी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, चाहे यह राजनीतिक कारणों से रखा गया है, इसके लिए हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में एम्ज़ बने और इसके लिए कितनी धनराशि का प्रावधान हुआ है तथा क्या केंद्रीय मंत्री से आपकी कोई बातचीत से हुई है? अगर बातचीत हुई है तो हमें भी बतायें कि इसके लिए कितनी धनराशि सैंक्शन हुई है? इसके लिए टैंडर कब हो रहे हैं या हो गये हैं, ये काम कब शुरू होगा? क्योंकि आपकी केंद्र सरकार का कार्यकाल भी अब 10 महीने का ही बचा है।

14.03.2018/1130/RKS/DC-1

प्रश्न संख्याः 81...जारी

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने चाहा है उसका उत्तर बहुत संक्षेप में भी है और बहुत विस्तार में भी है। जो हमारी परिधि में है उसके मुताबिक इसका शिलान्यास माननीय प्रधान मंत्री जी ने किया। इस प्रोजैक्ट की अधिकृत स्वीकृति के बारे में भी विस्तार से उत्तर दे दिया गया है। परन्तु माननीय सदस्य जी ने कुछ और विषय इसमें जोड़ दिए कि केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को वहां से प्रोत्साहन दिया गया। उसके लिए मैं इस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। वैसे तो माननीय मुख्य मंत्री जी इस उत्तर को देने के लिए अधिकृत हैं परन्तु मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। जहां तक धन और टैंडर प्रक्रिया की बात है, यह भारत सरकार से जुड़ा हुआ विषय है। जैसे ही हमारे पास इसकी जानकारी उपलब्ध होगी, मैं आपको यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि हम सारी जानकारियां आने वाले दिनों में दे देंगे। भारत सरकार इसके लिए वचनबद्ध है और हिमाचल प्रदेश सरकार भी इसके लिए कटिबद्ध है कि AIIMS Pioneer संस्थान, ज़िला बिलासपुर में खुल रहा है। इसकी सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद इसका काम शुरू किया जाएगा, इसके लिए मैं आपको और इस माननीय सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं।

श्री राम लाल ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, जो AIIMS खोलने की बात है, इस प्रोजैक्ट के लिए मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र के कोठीपुरा में जगह चिन्हित की गई है। यह फैसला प्रदेश सरकार ने किया और केंद्र सरकार ने उसके मुताबिक इसकी आधाशिला रखी। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जब आधारशिला रखी गई थी तो उसके 10 दिनों के अंदर-अंदर भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री का बयान आया कि इसकी ड्राइंग्स वगैरह बनाने के लिए कम-से-कम एक वर्ष लगेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रोजैक्ट का कार्य वही कम्पनियां करेगी, जिनका 1000-1500 करोड़ रुपये से ज्यादा का काम पहले हुआ हो। उन कम्पनियों को ही यह काम मिलेगा। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या एक

वर्ष वाली प्रक्रिया शुरू हो गई है? दूसरा, मैं यह भी जानना चाहूंगा और जैसा कि उत्तर में भी दर्शाया गया है कि 'केंद्र सरकार के पास सही जानकारी है' क्योंकि AIIMS को केंद्र

14.03.2018/1130/RKS/DC-2

सरकार ने ही बनाना है। केंद्र सरकार ने ही इसके लिए पैसे का आबंटन करना है। एक तरफ हमारे मैंम्बर पार्लियामैंट कह रहे हैं कि एक भी पैसा स्वीकृत नहीं हुआ है। दूसरी तरफ माननीय स्वास्थ्य मंत्री, केंद्र सरकार कह रहे हैं कि 1351 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। इस बात को बड़ी प्रमुखता से बजट में भी छापा गया है कि AIIMS के लिए इतना पैसा मिल गया। बजट बुक में भी इसके लिए स्थान दिया गया है। जब प्रदेश सरकार को जमीन आबंटन करने के अलावा कुछ भी नहीं करना है तो बजट बुक में इसे प्राथमिकता के आधार पर छापने का क्या औचित्य है?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री राम लाल ठाकुर जी ने इस संस्थान को शुरू करने के लिए या इसकी जो औपचारिकताएं हैं विशेषकर ड्रॉइंग्स के बारे में इन्होंने कहा। मैं इनको कहना चाहता हूं कि जो प्रारम्भिक छानबीन या इन्वैस्टिगेशन होती है उसमें किसी भी संस्था या सिस्टम को खड़ा करने के लिए हमारी जो HSCC है, उसने इसकी प्रारम्भिक छानबीन शुरू कर दी हैं। यह बहुत बड़ा संस्थान है इसलिए इसमें कुछेक समय तो लग सकता है। सरकार की नीयत, श्रद्धेय प्रधान मंत्री जी और हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी इस बात को लेकर वचनबद्ध है कि सारी औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद यहां पर संस्थान का काम शुरू किया जाएगा। यह मैं माननीय सदस्य को अवगत करवाना चाहूंगा।

14.03.2018/1135/बी0एस0/डी0सी0-1

प्रश्न संख्याः 81......... क्रमागत

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि हमारे विपक्ष के मित्रों की चिंता बेवजह है। आरदणीय मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र में सरकार है, बिलासपुर में AIIMS का फाऊंडेशन स्टोन रखा गया और उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट उसकी कैबिनेट से स्वीकृति की बात थी, वह भी हुई। इनप्रिंसिपल जो उसका अमाउंट है उसकी स्वीकृति की भी बात हुई। उसके बाद माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से जवाब दिया है। कुछ औपचारिकताएं रहती हैं। इतना बड़ा संस्थान हिमाचल को मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, इसका हमें स्वागत करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए। दूसरी बात इतना बड़ा संस्थान हिमाचल प्रदेश को मिलने के साथ-साथ कुछ तो वक्त लगेगा। विपक्ष के लोग क्यों इतनी जल्दी में हैं? जो औपचारिकताएं हैं वह बहुत एडवांस स्टेज पर हैं। जैसे माननीय मंत्री जी ने बात कही कि लैंड हमारी ट्रांस्फर कर दी गई है, उसके साथ-साथ भारत सरकार का जो एच.एस.सी.सी. का जो इन्होंने जिक्र किया है, उसके माध्यम से जो बाकी की औपचारिकताएं पूरी करने की दृष्टि से जैसे लैंड कितनी है, बाऊंडरी वॉल कितनी लगानी है? उन सारी औपचारिकताओं को पूर्ण कर हम बहुत आगे बढ़े हैं। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह संस्थान हिमाचल प्रदेश की जमीन पर जितनी जल्दी खड़ा हो उतना हिमाचल प्रदेश को लाभ होगा। इसकी चिंता निश्चित रूप से सरकार को है। हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी यह संस्थान हिमाचल प्रदेश के लोगों की सेवा में बन कर तैयार हो। यह मैं कहना चाहता हूं।

अध्यक्षः यह मुख्य मंत्री जी की Suo moto स्टेटमैंट है । प्रश्न हमारा खत्म हो चुका था उसका उत्तर आ गया था। अगला प्रश्न श्री अनुरूद्ध सिंह जी।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार पैसे को बजट बुक में दिखा देती है और प्रश्न के उत्तर में नहीं देती है तो इसका कोई कारण तो रहा होगा।

14.03.2018/1135/बी0एस0/डी0सी0-2

अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी के जवाब से जो शंकाए पैदा हुई, प्रश्न पैदा हुआ उसका जवाब मिलना चाहिए।

अध्यक्षः माननीय सदस्य कृपया ध्यान दें, स्वास्थ्य मंत्री जी ने स्पष्ट उत्तर दे दिया है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसके ऊपर एक सुओ मोटो स्टेटमैंट दी, जिसके अन्दर उन्होंने पूरी तरह से सारी स्थिति को स्पष्ट कर दिया। अब इसके ऊपर अगर आपको चर्चा चाहिए तो आप प्रश्न के ऊपर चर्चा मांग लें। मैं इसपर चर्चा देने को तैयार हूं। इस प्रश्न का जवाब हो गया है मुकेश जी आप बैठिए। कृपया आप बैठिए।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, हमने कहा कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद 1351 करोड़ रुपये इनप्रिंसिपल इसकी स्वीकृति के रूप में है और उसके बाद डी.पी.आर. जब बन करके तैयार होगी, जो औपचारिकता का हिस्सा है। जैसे मैंने कहा जब वह पूर्ण होगा तो पैसे का प्रावधान हो जाएगा। आप यह सोचें कि एक साथ 1351 करोड़ रुपये हिमाचल प्रदेश को भेज देंगे यह सही नहीं है। जैसे ही डी.पी.आर.तैयार होती है उसके बाद फेज्ड मैनर पर पैसा आना शुरू हो जाएगा और काम शुरू होने के बाद इसको हम पूरा कर देंगे। यह कोई पेचिदा विषय नहीं है, यह बड़ा सरल और सीधा है।

14-03-2018/1140/DT/HK/1

प्रश्न संख्याः 81......... क्रमागत

अध्यक्षः माननीय मुकेश जी, आप क्या जानना चाहते हैं?

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः अध्यक्ष महोदय, हम कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं और हमारा कन्सर्न कोई बेवज़ह नहीं है। लेकिन हम यह कहना चाहते हैं कि जैसा मुख्य मंत्री महोदय ने कहा कि लगभग 1351 करोड़ रुपये की राशि की सैद्धांतिक तौर पर अप्रूवल हो गई है, आपने यही बात प्रश्न के उत्तर में कह देनी थी। हम तो सिर्फ आपसे यह कह रहे हैं कि इस

प्रश्न के जवाब में जो आपने अभी कहा है और जो बज़ट बुक में कहा है, वह आना चाहिए था।

अध्यक्षः ठीक है, यह सप्लीमैंटरी में आ गया है। माननीय मुख्य मंत्री जी की इंटरवैन्शन में आ गया।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः सप्लीमैंटरी में नहीं, अध्यक्ष महोदय, आपको सरकार को डायरैक्ट करना पड़ेगा कि जवाब सही आने चाहिए।

14-03-2018/1140/DT/HK/2

प्रश्न संख्याः 82

श्री अनिरूद्ध सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री और माननीय मंत्री महोदया को अवगत करवाना चाहूंगा कि विधायक बन कर हमारा काम यह है कि हम यहां पर कानून बनायें और कोर्ट उस कानून का पालन करे और उसके अनुसार चले। परन्तु मुझे ऐसा लगता है कि चाहे कोई भी सरकार रही हो, उसे कोर्ट चला रही है। यह बहुत सीरियस मैटर है। आप इस पर संज्ञान ले सकते हैं और आपके पास इतनी पॉवर है कि आप चीफ जस्टिस को भी अपने कक्ष में बुला सकते हैं। पहले भी विधान सभा अध्यक्ष ने हाई कोर्ट के ज़ज को बुलाया था। अब बात ऐसी है कि शिमला प्लानिंग एरिया पिछली बार आप लोगों के सहयोग से जब माननीय वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी, उस समय रिटैंशन पॉलिसी आई तथा उस पर स्टे लग गया। यह बहुत ही अहम मुद्दा है। क्योंकि न केवल शिमला प्लानिंग एरिया इससे अफैक्ट्डि है बल्कि पूरा प्रदेश, धर्मशाला, कुल्लू, मनाली, मण्डी या कोई और अन्य क्षेत्र हैं, वे सारे अफैक्ट्डि हैं। यहां पर यह पास हुआ लेकिन उस पर किसी ने स्टे ले लिया। उसी दौरान एन0जी0टी0 ने चाहे वह प्लानिंग एरिया, चाहे वह ग्रीन और कोर एरिया है, उसको टोटली बैन कर दिया है। सरकार ने माननीय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी अपील के लिए बनाई है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह अपील दायर कर दी गई है और यह अपील कहां दायर की गई है?

क्योंकि माता वैष्णो देवी के संदर्भ में भी वहां पर उसी समय एक आदेश पारित हुआ है जिसमें ऑलरेडी स्टे मिल चुका है। क्या यह अपील सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में दायर की गई है? अगर अपील कर दी गई है तो क्या सरकार को इसमें स्टे मिल चुका है या नहीं मिला है? अगर नहीं मिला है तो मैं अध्यक्ष महोदय, के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि इस मसले पर सरकार गम्भीर हो और स्टे ले ताकि प्रदेश के लाखों लोग, जो इससे प्रभावित हो रहे हैं, उनको कहीं-न-कहीं राहत मिल सके। हमारा काम लोगों की जो समस्या है उसको विधान सभा में पेश करना है और अगर कानून नहीं है तो उसके लिए कानून बनाना है।

14-03-2018/1140/DT/HK/3

शहरी विकास मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, रिटैंशन पॉलिसी के बजाए पिछली सरकार ने एक्ट में अमैंडमैंट की थी। जो राजपत्र में आने के पश्चात 27-01-2017 से लागू हो गई है। इसमें दो महीने का समय एप्लीकेशन देने के लिए दिया गया था। इसमें 2782 एप्लीकेशन्ज़ आईं थी। लेकिन अभिमन्यु राठौर ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट पेटीशन दायर की है और जिसमें कोर्ट ने 03.04.2017 को स्टे दिया है।

14.03.2018/1145/SLS-YK-1

प्रश्न संख्या : 82 .....जारी

माननीय शहरी विकास मंत्री ... जारी

फिर कोर्ट ने ही उसको 22.12.2017 को निरस्त कर दिया। अब सरकार ने इस मामले में रिवियु या अपील करने का फ़ैसला लिया है जिसके लिए हमने कानूनी सलाह भी ले ली है। इसको हम हाईकोर्ट में दायर करेंगे। लेकिन बीच में मैं आपकी मंशा को और क्लीयर करते हुए यहां पर यह कहना चाहूंगी कि इस सरकार ने 20 फरवरी, 2018 को एन.जी.टी. में रिवियु पैटिशन दायर की है और यह मामला 13 मार्च यानि पिछले कल सुनावाई के लिए लगा भी था। एन.जी.टी. के जो 4 मैंबर्ज़ थे, उनमें से 2 रिटायर हो गए हैं। एक स्वतंत्र कुमार, चेयर पर्सन और उनके साथ बी.एस. सांझवान; यह दो व्यक्ति रिटायर हो गए हैं।

इसलिए फुल बैंच उपलब्ध नहीं था। मैं इसमें आगे यह कहना चाहती हूं कि इस मामले में हम आगे सुप्रीम कोर्ट में इसकी याचिका दायर करेंगे ताकि वह जो फ़ैसला लेंगे; या तो वे इन दो मैंबर्ज़ को ही अधिकृत कर दें या सुप्रीम कोर्ट अपने स्तर पर जो भी फ़ैसला लेगा वह सरकार को मान्य है। सरकार पूरी तरह से इस मामले में संवेदनशील है और इसमें जो भी फर्दर स्टैप्स हाईकोर्ट में लेने हैं, उसमें हम अपना काम कर रहे हैं।

श्री विक्रमादित्य सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौक़ा दिया।

जो यह प्रश्न माननीय अनिरूद्ध सिंह जी ने लगाया है, मैं इसके बारे में आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि पीछे जो टी.सी.पी. एक्ट प्रदेश सरकार द्वारा लाया गया था, इसमें यह संशय है कि जो एन.जी.टी.का आदेश आया है, this is in direct contradiction to various provisions that were enacted in the TCP Act. इसमें जैसे अभी मंत्री महोदय ने कहा है कि इसको हम स्टिपुलेटिड टाईम फ्रेम में सुप्रीम कोर्ट में चैलैंज करेंगे। ...(व्यवधान)... यह सुप्रीम कोर्ट में ही होगा since it has been passed by the NGT. मैं इस सदन के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि पूर्व में मैंने ऐसा देखा है, अख़बारों में भी यह पढ़ा है कि the attitude of the State Government for

14.03.2018/1145/SLS-HK-2

various cases that have been taken up in the Supreme Court has been non-serious. There have also been instances where the Chief Secretary has been personally called by the Supreme Court. और उनको वहां पर सीरियसनैस के साथ गवर्नमैंट के मुद्दों को लेने के लिए कहा गया है। इसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि जल्दी-से-जल्दी इस पर निर्णय लिया जाए ताकि इसमें जो एन.जी.टी. की कंट्राडिक्शन्ज हैं, उनको हम देखें। शिमला को जो अभी स्मार्ट सिटी प्रोजैक्ट मिला है, जिसके लिए मैं केंद्र सरकार का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, उसमें भी एन.जी.टी. के ऑर्डर के कारण बहुत-सी

बाधाएं आ रही हैं whether it is in the non-core area or in the green belt. इसमें जो हर एरिया में two storey plus attic की एक लिमिटेशन लगाई गई है, I think that is something which needs to be seen on very important basis. इस पर आगे हमने किस तरह से इसका व्यु लेना है, इसके बारे में मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इसको जल्दी-से-जल्दी सुप्रीम कोर्ट में टेक अप किया जाए।

शहर विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो बात यहां विक्रमादित्य जी ने कही, हम तो केवल माननीय कोर्ट का सम्मान करते हुए उनके पास अपनी याचिका दायर कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं परंतु फ़ैसला कोर्ट ने ही लेना है। लेकिन मैं पिछली सरकार से यह प्रश्न करना चाहूंगी कि जहां तक एन.जी.टी. का प्रश्न है, इसमें पिनाकी मिश्रा एडवोकेट कौन थे? आपने वह एन.जी.टी. में अपने एडवोकेट किए। पिछली सरकार ने एन.जी.टी. में सीरियस होकर इस मामले की पैरवी नहीं की। ...(व्यवधान)... आप इसमें मेरा उत्तर आने दो। सैक्रेटरी (लॉ) और आपके एडवोकेट जनरल को इसकी ठीक से पैरवी करनी चाहिए थी। अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात पर हैरानी हुई कि इन्होंने जो वकील पिनाकी मिश्रा एन.जी.टी. के लिए किया, उसको 36 लाख रुपये दिया जबकि उसने 36 शब्द भी कोर्ट में नहीं बोले। वह वहां बिल्कुल मौन रहे। उन्होंने केवल अपनी फीस ली।

14/03/2018/1150/RG/YK/1

प्रश्न सं. 82---क्रमागत

शहरी विकास मंत्री-----जारी

और इस विषय में कुछ नहीं कहा। पुराना रिकॉर्ड इसमें देख सकते हैं। हैरानी इस बात की है कि पिछली सरकार के ऐडवोकेट जनरल एवं सैक्रेट्री(लॉ) ने उनको क्या सलाह दी? उसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं किया। हमने इस मामले में दिनांक 20 फरवरी, 2018 को रिव्यू पिटीशन दायर की है और पिछले कल ही यह केस लगा था, लेकिन बैंच पूरा नहीं था क्योंकि दो मेम्बर्ज रिटायर हो गए हैं। इसलिए हम इसको आगे हायर कोर्ट में ले जा रहे हैं ताकि जो फैसला माननीय उच्चतम न्यायालय देगा, हम माननीय उच्चतम न्यायालय का

सम्मान करते हैं। मुझे लगता है कि कोट्र्स बहुत गंभीरता के साथ अपना निर्णय देते हैं। जैसा आपने कहा कि नॉन-सीरियस है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है और हमारी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ इस पर आगे कार्रवाई कर रही है।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री महोदया राजनीतिक उत्तर ज्यादा दे रही हैं। पिछली सरकार ने क्या किया या नहीं किया। आज यह सवाल पैदा होता है कि ऑथोराइज्ड और अनऑथोराइज्ड। ---(व्यवधान)----मैं अभी बोल तो लूं, माननीय किशन कपूर जी, आप भी मंत्री हैं। तो सवाल ऑथोराइज्ड और अनअथॉराइज्ड का पैदा होता है। दो प्रकार की बात है। एन.जी.टी. ने एक ऑर्डर पास किया कि जो भी अवैध निर्माण हैं उनको बैन कर दिया जाए और जो शिमला डवलपमेंट प्लान है, उसमें अढ़ाई स्टोरी से ऊपर निर्माण की अनुमति न दी जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश सचिवालय----(व्यवधान)---हाईकोर्ट तो आज लेटेस्ट टैक्नॉलॉजी से बना है। वर्ष 1903 में सचिवालय आठ मंज़िल का बना, सेसिल होटल वर्ष 1917 में नौ मंज़िल का बना। हमारी सौयल की लोड बियरिंग कैपेसिटी अच्छी है। तो क्या आप यह भी अपील करेंगे कि चार या पांच मंजिल या हाईट के हिसाब से वर्टिकल बनाए जाने की परमीशन अलॉऊ की जाए। हौरीजोन्टल में आप शोघी से लेकर ढली तक पहुंच गए। मेरा प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री जी को थोड़ा बताना पड़ेगा कि अढ़ाई स्टोरी के बाद पांच मंज़िल बनाने के लिए जिन लोगों ने प्लाट यूज किया है, क्या उसको अपील करेंगे?

अध्यक्ष : आपका प्रश्न आ गया।

14/03/2018/1150/RG/YK/2

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु : दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि एक अथॉराइज्ड है। एक यह है कि टी.सी.पी. ने या शिमला प्लानिंग एरिया में कहीं भी चार स्टोरी का नक्शा पास हो गया, चार स्टोरी उसने पास कर दी। रिटेन्शन क्यों लाई गई थी? तो चार स्टोरी उसने पास कर दी और एक स्टोरी उसकी और ऐक्स्ट्रा बन गई। तो वह अनअथौराइज कंस्ट्रक्शन में आया, इलीगल कंस्ट्रक्शन में नहीं आया। क्योंकि चार स्टोरी का आपने नक्शा पास किया है और पांचवीं स्टोरी उसने पार्किंग में बनाई है। तो अनअथौराइज्ड को आप रिप्रिजेन्ट इस

ढंग से करेंगे। यह लीगल या इलीगल की बात नहीं है। यह अथौराइज्ड और अनअथौराइज्ड की बात है। एन.जी.टी. के आदेश में हमारी सरकार ने जो किया, वह किया। लेकिन मैं इस मामले में आपसे यह जानना चाहूंगा कि क्या आने वाले समय में इन दो मुद्दों को आप एन.जी.टी. के पास एवं माननीय उच्चतम न्यायालय में क्या इसकी पैरवी करेंगे?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, यदि आपके पास उत्तर है, तो दे दीजिए।

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सुक्खु जी जी ने जो स्टोरीज की चिन्ता व्यक्त की है। यह बात बिल्कुल सत्य है कि यह बिल्डिंग बहुत पुरानी बनी हुई है, लेकिन हमने तो माननीय कोर्ट का सम्मान करना है और हमने जो रिव्यू पिटीशन की है, उसमें चार फ्लोर के लिए पहले ही हमने निवेदन किया है। यह पहले ही हमने इस प्रोवीजन में रखा है ताकि हिमाचल के लोगों को राहत मिले। बाकी माननीय कोर्ट जो आदेश देगा, उसका हम पालन करेंगे।

श्री इन्द्र सिंह(सरकाघाट) : अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा स्पष्टीकरण न चाहते हुए सीधे अपने प्रश्न पर आता हूं और आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि एन.जी.टी. के आदेशानुसार जिन-जिन होटलों का बिजली और पानी बन्द कर दिया गया था क्या सरकार उनको किसी प्रकार की फौरी राहत देने का विचार रखती है?

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने फौरी राहत की जो बात कही है, उसको हाल ही में ठाकुर जयराम जी की सरकार ने इस सारे मुद्दे को बहुत संवेदनशीलता से लेते हुए एच.पी.टी.सी.पी. रूल्स के रूल-34 में संशोधन करने के लिए अधिसूचना

14/03/2018/1155/MS/DC/1

प्रश्न संख्याः 82 क्रमागत---
शहरी विकास मंत्री जारी----

23 फरवरी, 2018 को जारी हुई है और इसमें हमने जिन-जिन लोगों ने अन-ऑथोराइज्ड, जैसे हम कह सकते हैं कि होटल हों या घर हों, सभी बिल्डिंग्ज के लिए एक माह की समयावधि के दौरान ऑब्जेक्शन और सुझाव इन्वाइट किए हैं। जिसके लिए लोगों को 24

मार्च तक का समय दिया गया है। वास्तव में यदि किसी भी रूल में अमैंडमैंट लानी है तो एक महीने का समय देना पड़ता है। जब 24 मार्च तक लोगों से सुझाव और ऑब्जेक्शन्ज आ जाएंगे तो इसमें अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी। इसको मैं थोड़ा और स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि इसमें जो संशोधन सरकार द्वारा रखा गया है, उसमें ऐसा है कि जो ऑथोराइज्ड हैं वे लोग यूज कर सकते हैं लेकिन जो अन-ऑथोराइज्ड हैं उनको हमें कोर्ट के आदेश के मुताबिक सील करना पड़ेगा। उनसे हम लिखित में अण्डरटेकिंग लेंगे ताकि जो बहुत सारे लोगों ने अपना पैसा लगाकर होटल्ज या बाकी कन्स्ट्रक्शन की है उसमें ऑथोराइज्ड पोर्शन के लिए श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार संवेदनशीलता के साथ कदम बढ़ा रही है और बाकी अन-ऑथोराइज्ड जो हैं उसमें फिर कोर्ट के अनुसार हमें आगे चलना पड़ेगा।

14/03/2018/1155/MS/DC/2

प्रश्न संख्याः 83

श्री सुखविन्द सिंह सुक्खुः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये जो मेडिकल कॉलेज है जिसकी नोटिफिकेशन बाद में हुई, यह स्वीकृत कब हुआ था और कितना अमाऊंट इसके लिए स्वीकृत हुआ था? मैं नोटिफिकेशन के बारे में नहीं बल्कि इसकी स्वीकृति के बारे में जानना चाहता हूं? दूसरे, क्या इसमें पैरा-मेडिकल स्टाफ की भर्ती कर ली गई है? तीसरा, इसकी कन्स्ट्रक्शन किसके द्वारा करवाई जा रही है?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि माननीय सदस्य ने प्रश्न का उत्तर ध्यान से पढ़ा नहीं है। मैं माननीय सदस्य के ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो हमीरपुर मेडिकल कॉलेज है या नाहन और चम्बा के मेडिकल कॉलेजिज हैं ये सेंट्रल इन्टरवेंशन स्कीम 90:10 के अनुपात से हिमाचल प्रदेश में शुरू हुए। दूसरे, जब कोई भी भवन या संस्थान बनना होता है तो सबसे पहले जमीन की बात आती है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि शायद आपके ही विधान सभा क्षेत्र में एक जगह गांव-थाई, नजदीक जोलसापर -(व्यवधान)- सुनो तो सही, मैं बता रहा हूं। माननीय सदस्य, आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? आपकी जो मंशा है वह मुझे पता है। मैं यह बता रहा हूं कि लगभग

सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और जो एच0एस0सी0सी0 है उसके साथ हमारी बातचीत हुई है। जो एक मेडिकल कॉलेज को बनाने के लिए नॉर्म्ज हैं उसकी प्रि-इन्वेस्टिगेशन वहां पर चल रही है। इसका इन्तकाल आने वाले दिनों में होगा और यह लगभग 6.56 हैक्टेयर जमीन हैल्थ संस्थान.., -(व्यवधान)-

अध्यक्षः सुक्खु जी, एक मिनट माननीय मंत्री जी को बताने तो दो।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः माननीय सदस्य, सुनिए तो सही।

श्री सुखविन्द सिंह सुक्खुः आप केवल सैंक्शन बताइए कि कब हुई?

14/03/2018/1155/MS/DC/3

अध्यक्षः माननीय सदस्य, मंत्री जी को उत्तर तो पूरा देने दो।

श्री सुखविन्द सिंह सुक्खुः मंत्री जी आप सिर्फ दो बातों का उत्तर दीजिए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेडिकल कॉलेज को चलाने की बात है तो फैकल्टी की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। जो माननीय सदस्य पैरा-मेडिकल स्टाफ की बात कर रहे हैं, उसके बारे में हमने डायरेक्टर, हैल्थ सर्विसिज को कहा है कि उनकी ऑप्शन ली जाए और वहां पर पैरा-मेडिकल स्टाफ को एप्वॉयंटमैंट दी जाए।

14.03.2018/1200/जेके/एजी / 1

प्रश्न संख्याः 83....जारी...

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः-----जारी----

तीसरी बात इन्होंने कही है कि कब इसकी स्वीकृति हुई है? मैं कहना चाहता हूं कि लगभग वर्ष 2013 में इस प्रकार के कॉलेज़िज चलाने के लिए अनुमति दी गई थी और उसके उपरान्त एम0ओ0यू0 आदि साइन हुए। अब वर्तमान सरकार की यह नियत है और

माननीय मुख्य मंत्री जी भी चाहते हैं कि यह मैडिकल कॉलेज चलना चाहिए इसलिए हमारी प्राथमिकता है और यह मैडिकल कालेज चलेगा उसके लिए विभाग प्रयासरत्त है।

प्रश्नकाल समाप्त

14.03.2018/1200/जेके/एजी /2

कागज़ात सभा पटल पर

अध्यक्षः अब सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम अधिनियम, 1979 की धारा 23(6) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम, हमीरपुर की 36वीं वार्षिक प्रशासनिक विवरणिका, वर्ष 2016-17 की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

14.03.2018/1200/जेके/एजी /3

सदन की समितियों के प्रतिवेदन :

अध्यक्षः अब श्री रमेश चन्द ध्वाला, सभापति, प्राक्कलन समिति, (वर्ष 2017-18), समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री रमेश चंद ध्वालाः अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से प्राक्कलन समिति, (वर्ष 2017-18), समिति का प्रथम कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 18वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2015-16) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा महिला एवं बाल विकास विभाग से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

अध्यक्षः अब श्री सुख राम, सभापति, कल्याण समिति, (वर्ष 2017-18), समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगेः-

श्री सुख रामः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कल्याण समिति, (वर्ष 2017-18), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूंः-

i. समिति का प्रथम कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 31वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित है;

14.03.2018/1200/जेके/एजी /4

ii. समिति का द्वितीय कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 27वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित है; और

iii. समिति का तृतीय कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 35वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा जनजातीय विकास विभाग से सम्बन्धित है ।

14.03.2018/1200/जेके/एजी /5

<u>वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा</u>ः

अध्यक्षः अब वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट अनुमानों /वार्षिक वित्तीय विवरण पर आगे चर्चा प्रारम्भ होगी । अब इस चर्चा में सर्वप्रथम श्री नरेन्द्र ठाकुर जी भाग लेंगे।

श्री नरेन्द्र ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष का जो बजट माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन में पेश किया इस पर बोलने का आपने मुझे समय दिया इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं, मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा और साथ में धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि इस बार का जो इन्होंने बजट पेश किया और मेरी उपस्थिति में यह चौथा बजट है। तीन बजट पिछली सरकार के पेश हुए। जब मैंने कम्पेरिज़न किया तो पूर्व कांग्रेस सरकार के जो बजट पेश हुए और इस बजट में रात-दिन का फ़र्क है। यह बहुत ही फार साइटिड बजट है। इसके बड़े दूरगामी परिणाम हिमाचल प्रदेश को मिलने वाले हैं। हर वर्ग द्वारा इस बजट की प्रशंसा की गई है। इस बजट में हर वर्ग, हर क्षेत्र का ख्याल रखा गया है। इसके लिए मैं, माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। लेकिन चर्चा के दौरान विपक्ष की ओर से इस बजट के ऊपर बहस की गई जिसकी मुझे बड़ी हैरानी है। ये एक तरफ तो कह रहे हैं कि इस बजट में नया कुछ नहीं है, वही पेपर,वही पैंसिल। यहां पर हमारे दोस्त आदरणीय रामलाल जी ने कहा कि कलर भी वही है लेकिन इसका कलर थोड़ा फेड है और जो तीन साल पहले बजट पेश हुए हैं वही डायरैक्टर, वही प्रोड्युसर थे और जो हमने प्वाइंट रेज़ किए वही बजट माननीय मुख्य मंत्री जी ने यहां पर पेश किया। विपक्ष के नेता, माननीय सदस्य श्री मुकेश अग्निहोत्री जी जब इस बजट पर चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने हर प्वाईंट पर इसकी आलोचना की। इनकी अपनी ही स्टेटमैंट सैल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक तरफ ये कह रहे हैं कि पुराने बजट और नए बजट में कोई फ़र्क नहीं है और इन्होंने इस बजट को क्रिटिसाइज़ किया है।

14.03.2018/1205/SS-AG/1

श्री नरेन्द्र ठाकुर क्रमागतः

मुझे यह समझ नहीं आ पा रहा है कि जो प्रिवीअस बजट कांग्रेस सरकार ने पेश किये, क्या वे सही थे या गलत थे। मैं माननीय मुकेश जी से यह जानना चाहूंगा, दूसरे इन्होंने कहा कि

वही प्रोड्यूसर और वही डायरेक्टर हैं लेकिन यह भूल गए कि फिल्म जो बनती है उसमें पुराने प्रोड्यूसर/डायरेक्टर तो होते हैं, यह बात मान ली लेकिन जब फिल्म सक्सैस होती है तो उसमें ऐक्टर का ज्यादा रोल होता है। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर तो वही हैं लेकिन इस बार ऐक्टर बदल गया है। ऐक्टर नौजवान और खूबसूरत है तथा स्टोरी भी बदल गई है। नयी स्टोरी और नया ऐक्टर है। मैं आपको दावे से कह देता हूं कि यह फिल्म हिट ही नहीं बल्कि डायमंड जुबली होगी क्योंकि जो पुराने ऐक्टर थे वे बहुत पुराने हो चुके थे और लोग उनको देख-देखकर ऊब चुके थे तथा स्टोरी भी घिसी-पिटी थी। इसलिए मैंने आपके जो तीनों बजट पीछे देखे, आपकी पिछली स्टोरी पूर्णतः फ्लॉप रही है। जहां तक माननीय मुकेश जी ने चिन्ता जाहिर की है और मुझे बड़ी हैरानी है कि जब ये इस तरफ (सत्तापक्ष में) बैठे थे तब इनकी सोच कुछ और थी और जब यहां (विपक्ष) से बोलने लगते हैं तो इनकी सोच कम्प्लीटली बदल चुकी है। इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के बारे में चिन्ता जाहिर की है। हमारी सरकार को बने हुए दो ढाई महीने हुए हैं और इन्होंने अपनी बात को इस ढंग से पेश किया कि लॉ एंड ऑर्डर की बुरी हालत है। चारों तरफ आग लगी हुई है। अफरा-तफरी मची हुई है। लॉ एंड ऑर्डर सरकार के कंट्रोल से बाहर चला गया है। मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि दो महीने में लॉ एंड ऑर्डर क्या है यह सब को पता है। लेकिन जाते-जाते पिछली सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर की जो धज्जियां उड़ाई हैं, जो दो ब्लैक सपोट्स हैं - एक गुडिया प्रकरण और दूसरा होशियार सिंह प्रकारण - वे ऐसे ब्लैक सपोट्स अपने माथे पर लगाकर गए हैं इससे उन्हीं को नहीं बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश को शर्मसार होना पड़ा है। ये जो दो ब्लैक सपोट्स हैं ये ताउम्र पूर्व सरकार से धुलने वाले नहीं हैं। मुझे तो यह भी समझ नहीं आया कि किस लॉ एंड ऑर्डर की बात ये कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इतने रेप, मर्डर और तलाक के केस इन दो महीनों में हो गए हैं मैं उनको एक सुझाव देना चाहूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर की परिभाषा क्या है। सरकार को या इंवैस्टीगेशन एजेंसी को या पुलिस को यह पता नहीं होता है कि कब क्राइम होने वाला है। यह तभी एक्टिव होती हैं जब क्राइम हो जाता है। ऐसा कोई इंस्ट्रूमैंट पूरी दुनिया में नहीं बना है कि क्राइम करने से पहले ही

14.03.2018/1205/SS-AG/2

मुलजिम को पकड़ लो। मुलजिम को तभी पकड़ा जाता है जब वह क्राइम करता है। दो महीने में जितने भी हिमाचल प्रदेश में क्राइम हुए हैं मैं समझता हूं कि कोई मुलजिम नहीं बचा है। वह या तो जेल में है या उसके ऊपर कार्रवाई हमारी सरकार ने की है। लेकिन जो

गुड़िया प्रकरण में हुआ, होशियार सिंह कांड में हुआ, वह देखने वाली चीज़ है। दोषी को फॉरेन में भेज दिया गया, निर्दोषों को जेल में डाला गया, उनका मर्डर भी जेल के अंदर हुआ और पुलिस को प्रेसराइज करके सारी इंवैस्टीगेशन को खत्म किया। बेचारे पुलिस वाले भी जेल में हैं इससे यह साफ जाहिर है कि यह जो गुड़िया प्रकरण केस है जिसमें आज तक सही दोषी पकड़े नहीं गए, यह सरकार की डायरेक्ट इंटरफियरैंस थी और इस वजह से दोषी बचाए गए हैं। --(व्यवधान)-- यह पिछली सरकार में हुआ था और आप भी उस टाइम वहीं थे। जो होशियार सिंह कांड है उसको क्या किया, उसकी बॉडी पेड़ पर लटकी हुई मिली। सरकार ने क्या कहा, इंवैस्टीगेशन एजैंसी ने क्या कहा कि उसने सुसाइड कर लिया है। जिस ढंग से बॉडी लटकी हुई पाई गई और बाद में इंक्वायरी हुई तो कहा कि यह सुसाइड नहीं है यह मर्डर केस है। लेकिन आज तक जिन्होंने मर्डर किया, जिन्होंने सारी इंवैस्टीगेशन बनाई, उनके ऊपर कोई ऐक्शन पिछली सरकार ने नहीं लिया। मैं माननीय मुकेश जी को यह बता देना चाहूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां पिछली सरकार ने किस ढंग से उड़ाई हुई हैं,

14.03.2018/ 1210/केएस/डीसी/1

श्री नरेन्द्र ठाकुर जारी-----

ये इन दो जो प्रकरण हुए हैं, गुड़िया कांड और होशियार सिंह कांड इनसे साफ ज़ाहिर है कि पिछली सरकार लॉ एण्ड ऑर्डर के मामले में कितनी संवेदनशील थी।

अध्यक्ष जी, जब सदन में चर्चा हो रही थी तो माननीय सदस्य श्री मुकेश जी, श्री राम लाल ठाकुर जी और श्रीमती आशा कुमारी जी अपनी चर्चा के दौरान प्रदेश की वित्तीय स्थिति के बारे में बहुत चिन्तित नज़र आ रहे थे कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है और लगता है कि इस बार का जो बजट आया है इससे प्रदेश की वित्तीय स्थिति और खराब होगी। अध्यक्ष जी, मैं यह बता देना चाहूंगा कि इस प्रदेश की फाइनैंशियल पोज़िशन मौजूदा समय में क्या है और इस पोज़िशन तक पहुंचने के लिए पूर्व कांग्रेस सरकार का कितना ज्यादा रोल है। वर्ष 2007 में जब बी.जे.पी. की सरकार हिमाचल प्रदेश में आई थी तो 19,970 करोड़ रु0 का इस प्रदेश पर कर्ज था। 2012 में जब कांग्रेस की सरकार आई,

माननीय वीरभद्र सिंह जी उस समय मुख्य मंत्री थे तो टोटल लोन 27,598 करोड़ रुपये था। उससे पहले पांच साल जब बी.जे.पी. की सरकार थी तो 7,621 करोड़ रु0 का कर्ज लिया लेकिन 2012 से 2017 तक कांग्रेस सरकार ने लगभग 18,787 करोड़ रुपये का लोन लिया जो कि 246 परसेंट पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा था। टोटल कर्ज प्रदेश में 46,385 करोड़ रुपये, टोटल प्लान में से लगभग 3500 करोड़ रु0 बतौर ब्याज के रूप में इस सरकार को देना पड़ेगा। जो वर्तमान में माली हालत है इसका जिम्मेवार कौन है? मैं यह कहता हूं कि आज जो इस प्रदेश की दयनीय वित्तीय स्थिति है, यह सारी की सारी जो पूर्व सरकार है, जिसने आजादी के बाद ज्यादा इस प्रदेश पर रूल किया, उसकी जिम्मेदारी है। पिछले 50 वर्षों में हिमाचल प्रदेश में वित्तीय स्थिति से निपटने के लिए पिछली सरकार ने कोई रिसोर्सिज़ जेनरेट नहीं किए। किसी रिसोर्स की प्रॉपर युटिलाइजेशन नहीं की। न तो प्रॉपर सड़कें बनाई, न पीने के पानी का प्रबन्ध किया, न रोज़गार दिया, न इंडस्ट्री लगाई न टूरिज्म को बढ़ावा दिया और इनकी कार-गुजारी की वजह से आज प्रदेश भारी फाइनैंशियल क्राइसिज़ के दौर से गुजर

14.03.2018/ 1210/केएस/डीसी/2

रहा है लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इतनी पतली वित्तीय स्थिति के बावजूद जिस ढंग से इन्होंने यह बजट पेश किया और आने वाले एक साल के लिए जो इन्होंने प्रोजैक्ट प्लान इस प्रदेश में रखी है, मैं कहता हूं कि इन हालात में इससे बढ़िया बजट और कोई नहीं हो सकता।

अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के साथी एग्रिकल्चर के बारे में बार-बार यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एग्रिकल्चर का बुरा हाल है। मैं बता देना चाहूंगा कि स्वतंत्रता के बाद 50 और 60 के दशक में हमारी जो टोटल बजट प्लान होती थी, टोटल जो हिमाचल प्रदेश की आय थी उसमें से लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा एग्रिकल्चर और एग्रिकल्चर पर आधारित जो भी क्षेत्र थे, उनसे प्रदेश को आय थी । लेकिन अब जो लेटैस्ट आंकड़े यहां पर मिले हैं , अब पोजीशन क्या है कि जो टोटल हमारा घरेलू उत्पाद है उसमें

एग्रिकल्चर की इन्कम 9 परसेंट से कम रह गई है। यह बहुत ही चिन्ता का विषय है। पिछले पांच साल स्वतंत्रता के पश्चात जो भी सरकार इस प्रदेश में रही है उन्होंने कृषि के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। आज हिमाचल प्रदेश में लगभग 90 प्रतिशत पॉपुलेशन गांव में रहती है और सबसे दयनीय स्थिति हमारे किसानों की है।

14.3.2018/1215/av/dc/1

श्री नरेन्द्र ठाकुर------- जारी

इस ओर प्रीवियस सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। कृषि क्षेत्र में हमारे प्रदेश में तब तक सुधार नहीं हो सकता जब तक हमारे खेत को पानी नहीं मिलेगा। पिछली सरकार ने सिंचाई के ऊपर एक भी पैसा खर्च नहीं किया। मैं यहां पर अपने हमीरपुर निर्वाचन क्षेत्र की बात करता हूं। हमारे वहां पर 8-10 सिंचाई की स्कीमें हैं लेकिन उसमें से एक भी स्कीम ओपरेट नहीं होती है और वे सारी-की-सारी स्कीमें डिफंक्ट पड़ी हुई है। कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए प्रीवियस सरकार ने मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं किया है और आज हमारे किसान की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। पूर्व में, कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में डिपो में भी घटिया किस्म का राशन दिया जाता रहा है और किसानों की खराब हालत के कारण आज हिमाचल प्रदेश का बच्चा-बच्चा पूरी तरह से डिपो के राशन पर निर्भर हो चुका है। मैं वर्तमान सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा कि किसानों की इनकम दोगुनी करने के लिए बजट में जो सिंचाई और कृषि के ऊपर आपने जो फोकस किया है मुझे लगता है कि आने वाले समय में इससे हर खेत को पानी मिलेगा तथा हमारे किसानों की दशा भी ठीक होगी। फील्ड चैनल के माध्यम से जो हर खेत को पानी पहुंचायेंगे उसके लिए पांच वर्ष में 500 करोड़ रुपये निवेश करने की जरुरत है जिसके लिए वर्तमान सरकार ने 130 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है और मैं इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। इसके अतिरिक्त लघु सिंचाई के लिए 49 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं और जीरो बजट योजना शुरू की गई है। जब ये स्कीमें फील्ड में प्रोपर ढंग से काम करने लगेगी तो इनसे हमारे कृषि क्षेत्र में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। मैं यह भी कहना चाहूंगा

कि जब यहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में आती है तो (---घण्टी---) एक मिनट, सर। तो पूरी स्टेट को ऐसे समझती है कि यह हमारी पर्सनल प्रोपर्टी है और मनमाने ढंग से इस प्रदेश में राज करती है। अपने पिछले कार्यकाल में इन्होंने एक ऐक्साइज पॉलिसी बनाई। ऐक्साइज पॉलिसी ऐसी बनाई गई कि सारी-की-सारी

14.3.2018/1215/av/dc/2

वाइन पर खुद ही कंट्रोल कर लिया। अपने आदमी बैठा दिए और अपनी मर्जी से कहां शराब देनी है, कैसी देनी है, घटिया देनी है या बढ़िया देनी है; पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। इन्होंने ऐक्साइज पॉलिसी बनाकर अपना रैवन्यू बढ़ा दिया लेकिन प्रदेश का रैवन्यू कम कर दिया। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने जो इस बार ऐक्साइज पॉलिसी बनाई है इसमें हर वर्ग/हर आम आदमी हिस्सा ले सकता है। इसमें रैवन्यू तो बढ़ेगा ही, हमारे बेरोजगार लोगों को आय के साधन के साथ-साथ रोजगार भी मिलेगा।

अध्यक्ष जी, मैं यहां पर लोक निर्माण विभाग के रोड्स की बात भी करना चाहता हूं। जहां तक मेरे निर्वाचन क्षेत्र की बात है तो वहां पर पिछले पांच साल में किसी भी लिंक रोड पर न तो टारिंग हुई है और न ही खड्डे भरे गये हैं। मुझे हाल ही में एक जगह जाने का मौका मिला जहां कुछ काम हुआ है और उसकी क्वालिटी इतनी बढ़िया है कि देखकर हैरानी होती है। एक दूसरी जगह की बात बताता हूं जहां लोक निर्माण विभाग द्वारा 300-400 मीटर सड़क को सीमेंट से पक्का किया गया है। उस सड़क को पक्का किए हुए अभी 6 महीने ही हुए हैं। जब मैं वहां पर गया तो (---घण्टी---) अध्यक्ष जी, दो मिनट और दे दीजिए। हम जब वहां पर गये तो वह सारी सड़क उखड़ी हुई थी और जिस एस0डी0ओ0 व जे0ई0 ने वह सड़क बनाई थी वे भी वहां पर ही थे। मैंने पूछा कि क्या कारण है कि यह सड़क 6 महीने पहले ही बनी थी और आज सारा पत्थर और सीमेंट बाहर आ गया। उस पर उन्होंने बताया कि इसमें क्योरिंग कम हुई है। मैंने कहा कि इसमें क्योरिंग कम नहीं हुई है बल्कि इसमें सब कुछ ही कम हुआ है। इसमें न तो सीमेंट प्रोपर लगा है और न ही दूसरी

चीजें ढंग से लगी हैं। इनके ठेकेदार भी अपने, सरकार भी अपनी और काम करने वाले लोग भी अपने होते हैं। इतनी ज्यादा पूअर क्वालिटी का काम और उस पर कोई चैक नहीं रखा जाता था। लोक निर्माण विभाग के घटिया कार्यों के कारण आज हमारे वहां सड़कों की यह हालत है।

14.3.2018/1220/TCV/HK-1

श्री नरेन्द्र ठाकुर.... जारी

जहां तक माइनिंग की बात है, मैं तो सर इतना कहूंगा कि इलीगल माइनिंग बिल्कुल बंद होनी चाहिए। मैं माननीय कंसर्न मंत्री से भी जानना चाहूंगा कि प्रदेश में कितने इलीगल माइनिंग के क्रशर हैं और उन क्रशरों के मालिक कौन हैं? इनमें 90 प्रतिशत् क्रशर मालिक ऐसे हैं, जो या तो वह मंत्री रहे हैं या एम0एल0ए0 रहे हैं या चेयरमैन रहे हैं। सारे-के-सारे माइनिंग क्रशर तो बड़े-बड़े राजनेताओं व बड़े-बड़े आदमियों ने कंट्रोल कर रखें हैं और उनके ऊपर इंक्वायरी भी कोई नहीं होती है। ---(व्यवधान)--- मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जो इलीगल माइनिंग है, वह टोटली बंद होनी चाहिए। सुजानपुर में जो खड्डे माइनिंग पर दी हुई थी, वहां पर भी इलीगल माइनिंग हो रही थी। क्योंकि दो-दो सालें उनको ऑक्शन पर दिए हुए हो गई थीं, परन्तु अभी तक उनको 'M Form' ही जारी नहीं हुआ था और जब तक 'M Form' जारी नहीं होता है, तब तक खड्डों से माइनिंग नहीं की जा सकती है। ये बड़ा क्लीयर है। जब हम उनसे पूछते थे कि आपको 'M Form' जारी नहीं हुआ है, फिर ये माइनिंग कैसे हो रही हैं, तो कहते थे कि हमें ऑक्शन हो गई है और 'M Form' हमें मिल जाएगा। जबकि उनको 'M Form' जारी होने के बाद ही उनका एक साल का पीरियड कांउट होता है। जो गरीब आदमी ट्रैक्टरों या खच्चरों के ऊपर बज़री ले जा रहा है, उसके ऊपर 3100-3100 रुपये का जुर्माना लग रहा है, लेकिन जो इलीगल माइनिंग कर रहे थे, उनके ऊपर सरकार कोई एक्शन नहीं कर रही थी।

अंत में, मैं इतना कहना चाहूंगा, जहां तक हमीरपुर चुनाव क्षेत्र की बात है, वहां पर वर्ष 1977 में बस स्टैंड बना था, वह छोटा पड़ गया है, उसकी वज़ह से हमीरपुर में लगातार ट्रैफिक जाम रहता है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और कंर्सन मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि 70 कनाल जगह बस स्टैंड़ के लिए गवर्नमैंट से ले ली गई है और उसकी फॉरेस्ट से क्लीयरेंस भी आ चुकी है। उस जगह में जितने पेड़ कटने थे, वे भी कट चुके हैं। 5 साल पहले वहां पर इसका फॉउंडेशन स्टोन रखा गया था, लेकिन आज तक उस बस स्टैंड के लिए एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ है।

14.3.2018/1220/TCV/HK-2

मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि उस बस स्टैंड़ के लिए जल्दी-से-जल्दी बजट का प्रावधान करके उसका काम शुरू किया जाये। यदि उसे बी0ओ0डी0 के तहत बनाना है तो उसके तहत बनायें। लेकिन वह बस स्टैंड बनना चाहिए।

दूसरे, वहां पर पार्किगं की बहुत समस्या है। एक पार्किगं वहां पर बन रही है। उसकी एक मंजिल बन गई है, अभी 2 मज़िलें और बननी हैं। मेरा मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि जल्दी-से-जल्दी उस पार्किगं का बाकी बचा काम शुरू किया जाये।

अंत में, मैं मैडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूं, मेरा यह निवेदन है कि उस मैडिकल कॉलेज की सभी औपचारिकतायें पूरी हो चुकी हैं। इसमें फर्स्ट ईयर की क्लासिज़ इसी सत्र से शुरू करें तथा जो भी वहां पर अप्वाईंटमैंट्स होनी है, वह भी की जायें। मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि उन्होंने वहां पर कुछ डॉक्टर्ज़ और स्टॉफ की अप्वाईंटमैंट कर दी हैं। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आने वाले सत्र में वहां पर क्लासिज़ शुरू हो जाएंगी।

अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश के 92 परसेंट घरों में गैस के कनैक्शन लग चुके हैं, मैं उसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। जो 8 परसेंट घर बच्चे हुए हैं, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो 'गृहिणी योजना' शुरू की है, उससे आने वाले समय में

100 परसेंट घरों को गैस का चूल्हा मिलेगा। आपने मुझे समय दिया, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। जयहिन्द।

14.3.2018/1220/TCV/HK-3

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री लखविन्द्र सिंह जी। ---(व्यवधान)---

व्यवस्था का प्रश्न

श्री हर्षवर्धन चौहानः अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे सीनियर मैंबर बोलने वाले हैं। यह हमारा prerogative है कि कौन बोलेगा और कौन नहीं बोलेगा। ये हम निर्धारित करेंगे। ---(व्यवधान)---

अध्यक्षः एक मिनट, प्लीज़, प्लीज़ जो आप निर्धारित करेंगे, हम वही करेंगे। परन्तु प्रश्न सिर्फ इतना है, कल सांयकाल मेरे पास 4 मैंबरान थे, जिनके सूची में नाम थे और उनसे आग्रह किया गया था कि कल प्रातः हम आपको बुलवाएंगे। उसमें लखविन्द्र सिंह राणा जी का नाम आपकी ओर से टॉप सूची में था।

14-03-2018/1225/NS/HK/1

अध्यक्ष ------जारी

फिर भी अगर आप बदलना चाहते हैं तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है।

श्री जगत सिंह नेगीः अध्यक्ष महोदय, जो लिस्ट आपको आज सबमिट की गई है, आप उसके हिसाब से बुलायें।

अध्यक्षः आपकी कल शाम वाली लिस्ट में कुछ चेंज है। लखविन्द्र राणा जी मुझे कह रहे हैं कि मैंने बोलना है।

श्री जगत सिंह नेगीः सर, माननीय सदस्य सीनयोरिटी के हिसाब से ही बोलेंगे और माननीय हर्षवर्धन चौहान जी सीनियर हैं।

अध्यक्षः ठीक है, आप बैठिये। माननीय सदस्य हर्षवर्धन चौहान जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री हर्षवर्धन चौहानः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने 09 मार्च, 2018 को इस माननीय सदन में वित्तीय वर्ष 2018-19 का बज़ट पेश किया है, मैं उस पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्षः प्लीज़, माननीय हर्षवर्धन जी बोल रहे हैं कृपया आपस में बात न करें।

श्री हर्षवर्धन चौहानः अध्यक्ष महोदय, इस सदन में मेरे से पूर्व कई वक्ताओं ने इस बज़ट के बारे में बहुत चर्चा की है। मुझे कई बार बड़ी हैरानी होती है, जब हमारे सत्ता पक्ष के विधायक कहते हैं कि हम तो सत्ता पक्ष में 15 या 20 साल के लिए आ गये हैं। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि डेमोक्रेसी जो है, इसमें एक सरकार का टेन्योर पांच वर्ष का होता है। कोई भी सरकार जब सत्ता में आती है तो यह ज़नादेश है, कोई लीज़ नहीं है, जो आपको 15 या 20 सालों के लिए दे दी गई है। आपको जो ज़नादेश मिला है, वह पांच साल का है। ---(व्यवधान)--- मुख्य मंत्री महोदय, जो लोग यह बात कहते हैं, यह उनकी फूलिशनैस या इग्नोरैंस हैं। आपको पांच साल के लिए ज़नादेश दिया गया है और अगर आप पांच साल तक ज़नता की अपेक्षाओं के मुताबिक चलेंगे तो भी बड़ी बात होगी। पांच साल बाद चुनाव होगा और ज़नता क्या फैसला करेगी, वह भविष्य के गर्भ में

14-03-2018/1225/NS/HK/2

छिपा हुआ है। ---(व्यवधान)--- अध्यक्ष महोदय, जब भी कोई नई सरकार बज़ट पेश करती है तो पहला और आखिरी बज़ट उस सरकार का महत्वपूर्ण होता है। पहला बज़ट इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि लोगों को सरकार से उम्मीदें होती हैं कि कोई नई चीज़ आएगी, कोई नया फैसला होगा, नई स्कीम्ज़ चलाई जायेंगी और आखिरी बज़ट इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि चुनावी वर्ष होता है और लोगों को उम्मीद होती है कि सरकार जाते-जाते बहुत कुछ देगी। मगर मैं कहना चाहूंग कि जो यह बज़ट है, यह एक साधारण बज़ट है। यह ऐवरेज़ बिलो बज़ट है और इसमें कुछ भी विशेष प्रदेश की ज़नता के लिए नहीं है। पुरानी स्कीम्ज़ चाहे वे किसी भी क्षेत्र में चल रहीं थी, उनके नाम बदल करके पेश की गई हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस बज़ट भाषण में कहा गया है कि केंद्र की सरकार यानि मोदी जी की सरकार बनने के बाद हिमाचल प्रदेश में पिछले तीन वर्षों में 46,793 करोड़ रुपये की राशि आई और जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय दो वर्षों में 28,592 करोड़ रुपये की राशि आई थी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आंकड़ों को तोड़-मरोड़ कर पेश न करें। हिमाचल प्रदेश में पैसे का जो फ्लो ऑफ फंड्ज़ ज्यादा हुआ है, वह 14वें वित्तायोग के अवार्ड की वज़ह से हुआ है। 14वें वित्तायोग का अवार्ड 13वें वित्तायोग की तुलना में लगभग 200 प्रतिशत ज्यादा है। मैं हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री जी को बधाई दूंगा कि इन्होंने 14वें वित्तायोग के समक्ष हिमाचल प्रदेश के केस को बहुत अच्छे ढंग से पेश किया है। इसकी वज़ह से ही फ्लो ऑफ फंड्ज़ ज्यादा है, मोदी सरकार की वज़ह से नहीं है। मोदी जी वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बने। हिमाचल प्रदेश में मोदी जी कितनी बार आये, कितनी ज़नसभायें की? आप मुझे बताईये कि मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश के किस मंच या स्थान से हिमाचल प्रदेश को एक नये पैसे की घोषणा भी की हो? उन्होंने एक भी नये पैसे की घोषणा नहीं की है। ---(व्यवधान)---

14.03.2018/1230/RKS/YK-1

श्री हर्षवर्धन चौहान...जारी

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री जय राम ठाकुर जी का धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने माननीय अटल जी को याद किया। इन्होंने बजट भाषण के आखिरी पेज में अटल जी को जोड़ दिया। हम श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का धन्यवाद करते हैं। जब वे हिन्दुस्तान के प्रधानमंत्री थे तो वे हिमाचल प्रदेश आते-रहते थे। हजारों-करोड़ों रुपये का पैकेज वे हिमाचल प्रदेश को देते थे। मुझे याद है कि जब भी वे मनाली आते थे तो 1000-1000 करोड़ रुपये का पैकेज हिमाचल प्रदेश को दिया करते थे। जब इस सदन में इसके लिए धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाता था तो उसमें कांग्रेस के विधायक और यह सारा सदन शामिल होकर उन्हें धन्यवाद देता था। आप कहते हैं कि पिछले 4 वर्षों में हिमाचल प्रदेश के अंदर क्या आया? लेकिन यह हम आपसे पूछते हैं। आप कहते हैं कि हमें आए हुए तो अभी 2 महीने ही हुए हैं। हमने तो अभी कुछ नहीं किया। हम आपकी बात से सहमत हैं क्योंकि आपने अभी तक कुछ

भी नहीं किया है। जब हम केंद्र सरकार या माननीय सांसदों से पूछते हैं कि आपकी इस प्रदेश के प्रति क्या उपलब्धि है तो उसमें भी आपको समस्या है। हमारा कार्यक्रम 'हिसाब दे सांसद, जवाब दे सांसद' उसमें भी आपको तकलीफ होती है। सांसद हमारे प्रतिनिधि हैं, हम विपक्ष में हैं और उनसे पूछना हमारा अधिकार है। आपका तो अभी हनीमून पीरियड चल रहा है परन्तु उनके तो सवा चार साल हो गए हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में रेलवे लाइन की क्या स्थिति है? आपने बजट भाषण में कहा कि केंद्र सरकार ने रेल बजट में 4 सौ कुछ करोड़ रुपये हिमाचल प्रदेश के लिए रखे हैं। परन्तु आपने रेलवे के लिए कितना पैसा रखा है? आप इस बारे में चुप क्यों हैं?

आपने इंडस्ट्रियल पैकेज की बात की। आज रोज़गार के साधन कहां से पैदा होंगे? इंडस्ट्री से होंगे। केंद्र में आपकी सरकार है। आज जितने भी पहाड़ी राज्य हैं, चाहे वे जम्मू-कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश हो या नार्थ ईस्ट के राज्य हैं, वहां आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। आप इंडस्ट्रियल पैकेज लाओ, फाइनैंशियल

14.03.2018/1230/RKS/YK-2

पैकेज लाओ । हिमाचल प्रदेश में उद्योग बढ़ें, हम आपका साथ देंगे। आप । अभी श्री मुकेश जी ने अपने भाषण में कहा कि माननीय मुख्य मंत्री जी हर शनिवार, रविवार को दिल्ली जाते हैं। यह अच्छी बात है, जाना चाहिए। मगर उपलब्धि क्या है? आप फाइनैंशियल पैकेज लाओ, इंडस्ट्रियल पैकेज लाओ, रेलवे पैकेज लाओ हम आपका साथ देंगे और इसके लिए धन्यवाद भी करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री नरेन्द्र ठाकुर जी कह रहे थे कि कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया। जब वर्ष 2012 में कांग्रेस की सरकार बनी तो उस समय हिमाचल प्रदेश का ग्रोथ रेट 6.4% था। उसके बाद इस प्रदेश का ग्रोथ रेट वर्ष 2013-14 में 7.1%, वर्ष 2014-15 में 7.5%, वर्ष 2015-16 में 8.1% और वर्ष 2017-18 में यह गिरकर

6.9% रहा। फिर वह वर्ष 2017-18 में गिरकर 6.3 % रहा। हमारे समय में ग्रोथ रेट 8.1% से ऊपर चला गया और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार ने विकास नहीं किया।

मुख्य मंत्रीः वर्ष 2017-18 में कितना ग्रोथ रेट रहा?

श्री हर्षवर्धन चौहानः सर, अभी 6.3 % है।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि वर्ष 2017-18 में किसकी सरकार थी? आप किसकी सरकार का हिसाब-किताब दे रहे हैं? हमारी सरकार को आए हुए तो अभी अढाई महीने हुए हैं। यह आपके ही समय में हुआ है। कहां था, कहां पहुंचा, क्यों पहुंचा इस बात पर आपको जाना चाहिए।

श्री हर्षवर्धन चौहानः अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत अच्छा जवाब था। वर्ष 2017-18 में ग्रोथ रेट 6.9%था। अब आप कह रहे हैं कि यह ग्रोथ रेट क्यों गिरा? माननीय मुख्य मंत्री जी आप उस समय मुख्य मंत्री नहीं थे। मैं यह आपको नहीं कह रहा हूं। यह ग्रोथ रेट नैशनल लैवल पर गिरा है और स्टेटों में भी गिरा है। इसके लिए मोदी सरकार जिम्मेवार है। (...व्यवधान...) ।

14.03.2018/1235/बी0एस0/वाई0के-1

श्री हर्षवर्धन चौहान द्वारा ....जारी

हिन्दुस्तान में जो नोटबन्दी आई, जी.एस.टी आया उससे हिन्दुस्तान की अर्थव्यवस्था ठहर गई है, रूक गई है और सिकुड़ गई है। उसके लिए आपकी केन्द्र सरकार जिम्मेवार है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक और बात आपको कहना चाहता हूं, इस हिमाचल प्रदेश में पूर्व मुख्य मंत्री वीरभद्र सिंह जी का एक सराहनीय योगदान इस प्रदेश के लिए रहा है। हिमाचल प्रदेश में जब-जब भी ये मुख्य मंत्री रहे Annual growth rate सबसे ज्यादा रहा है। पहली बार जब ये मुख्य मंत्री बने उस वक्त ग्रोथ रेट 8.8 प्रतिशत था। हिमाचल प्रदेश में कभी भी किसी भी सरकार का ग्रोथ रेट 8.8 प्रतिशत नहीं रहा है। अध्यक्ष महोदय, एक और बात मैं

कहना चाहूंगा। हमारे कुछ सदस्य कहते हैं कि मोदी सरकार ने 90/10 की फंडिंग रेशो शुरू की है। You are mistaken. यह तो जब पूर्व में हिमाचल प्रदेश बना था, श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने उस वक्त 90/10 की रेशो शुरू की थी। यह कभी भी बंद नहीं हुई। You are mistaken. मैं अन्दर बाहर रहा हूं, मुझे सब पता है। यह जरूर है कि जो सैन्ट्रल एडिड प्रोजैक्ट्स हैं उसमें अब 90/10 की रेशो हो गई है। मगर पहले से लेकर ये रेशो चली है।

अध्यक्ष महोदय, एक और बात में कहना चाहता हूं। मेरे माननीय सदस्य कह रहे थे कि Annual Plan में 600 करोड़ का इंक्रीज हो गया, यह कौन सी बड़ी बात है? यह तो हर बार होता है। 600 करोड़ का मतलब है कि यह 11 प्रतिशत इंक्रीज है। यहां तो 14-14 प्रतिशत Annual Plan इंक्रीज हुआ है और जो नॉर्मल एनवल प्लान है वह पिछले 20 सालों से ले करके 10 ,11, 12 और 13 प्रतिशत एनवल प्लान इंक्रीज हुआ है। यह आपकी उपलब्धि नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से एक एक और बात में कहना चाहूंगा, बजट की किताब में पैरा 5 में लिखा है I Congress Government in the State went on reckless unproductive expenditure without raising State Government resources. जिन्होंने यह बजट छापा है वह लिख रहे हैं पिछली सरकार ने अनप्रोडक्टिव एक्सपैंडिचर रेज किया है। क्या ए.जी. ने इस पर कोई पैरा लिखा है?

14.03.2018/1235/बी0एस0/वाई0के-2

फाइनाँस ने इस बारे में कोई इस पर प्रश्न चिन्ह लगाया है? कहीं भी नहीं है। आप कैसे लिख रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आता आप कैसे ऐसे शब्द पिछली सरकार के बारे में आप लिख रहे हैं। बहुत सारे सदस्यों ने कहा 2007-12 के बीच हमने 7000 करोड़ लोन रेज किया। आपने 19000 करोड़ रेज किया। अगर कांग्रेस सरकार ने किया है तो वह पैसा हमने अपने घर में इस्तेमाल नहीं किया है। कोई निजी कार्य के लिए नहीं किया है।

मुख्य मंत्री : माननीय सदस्य सीधी-सीधी बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि सीधी-सीधी बात का उत्तर भी सीधा-सीधा देना जरूरी है I अध्यक्ष महोदय, हमने नहीं कहा कि आपने

घर में लगाया। लोन लिया, बड़ी मात्रा में लोन लिया, आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा लोन लिया, यह सत्य है। पिछले दो-तीन दिनों से जबसे चर्चा चली हुई है और चर्चा से पहले भी अगर हम पूरे प्रदेश की आर्थिक चर्चा के बारे में कुछ कहते हैं तो विपक्ष कहता है कि वर्तमान सरकार भी लोन ले रही है। अगर हमारी सरकार लोन लेगी तो क्या हम अपने घर के लिए लेंगे? जो लोन आपने लिया वह प्रदेश के हित में इस्तेमाल के लिए लिया, विकास के लिए लिया, अगर हम भी लोन लेंगे तो वह भी प्रदेश के विकास के लिए लेंगे, इतना दृष्टिकोण तो रखिए।

श्री हर्षवर्धन चौहानः अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी की बात से हम सहमत हैं। आप लोन लो प्रदेश के विकास के लिए लो। कांग्रेस सरकार ने जो लोन लिया वह प्रदेश के विकास के लिए लिया है।

14.03.2018/1240/AG-DT/1

श्री हर्षवर्धन चौहान... जारी

कोई भी मुख्य मंत्री जब लोन लेता है तो व विकास के लिए ही लेता है। मगर जो बातें आप बजट में लिख रहें हैं हमको इससे ऑब्जैक्शन है। व्यवधान... मैं भी आपको वही आंकड़े दे रहा हूं जो किताब आपने पेश की है। यह किताब मैंने तो नहीं लाई है। ____(व्यवधान)....

अध्यक्षः कृपया आप चुप बैठिए। मत बोलिए, समय अधिक लगेगा। माननीय सदस्य को अपनी बात कहने दीजिए।

श्री हर्षवर्धन चौहानः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहूंगा कि लॉन लेने में कोई आपति नहीं है। हिन्दुस्तान के हर प्रदेश की सरकारें लॉन पर चल रही हैं। जनता की आशाओं और आकाक्षाओं को हर प्रदेश सरकार को लॉन लेना पड़ता है। हमारे मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि विकास के मामले में कांग्रेस पार्टी थोक के व्यापारी हैं। क्या आप प्रचून के व्यापारी हैं? हम लोन लेते हैं, काम करते हैं और विकास करते हैं। ____(व्यवधान)....अध्यक्ष महोदय, मैं एक और बात कहना चाहूंगा। मेरे कुछ मित्रों को

हिमाचल प्रदेश में शिक्षा संस्थान खोलने का विरोध है। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा का स्तर हिन्दुस्तान में दूसरे नम्बर पर है। ____(व्यवधान)....

अध्यक्षः आप सभी माननीय सदस्य आपस में बात न करें। माननीय सदस्य आप अपनी बात करें।

श्री हर्षवर्धन चौहानः आज प्रदेश में दूर-दराज के क्षेत्रों में स्कूल और कॉलेज खुले हुए हैं। उनमें बच्चों को शिक्षा मिलती है। मेरे चुनाव क्षेत्र शिलाई में जो कॉलेज खुला है उसमें 900 बच्चों में से पौने सात सौ लड़कियां हैं। दूसरा कॉलेज जो राजा वीरभद्र सिंह जी ने खोला है उसमें सवा दो सौ बच्चों में से 170 लड़कियां है। जिन लड़कियों को उनके मां-बाप नाहन, पौंटा और शिमला पढ़ने नहीं भेज सकते थे, वे यहां पढ़ रही हैं। हमारा समाज भेदभाव करता था कि लड़कियों को प्लस टू के बाद घर बैठने के लिए बोला जाता था। आज उन्हें घर पर ही ग्रेजूऐशन करने का मोका मिला है। आपका तो शिक्षा का निजीकरण करने का इतिहास रहा है। आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज प्रदेश में लाई और अब आप कह रहे हैं कि स्कूल बंद कर दो।

14032018/1240/AG-DT/2

आप स्कूल बंद करो। अभी सुक्खु जी ने मैडिकल कॉलेज का जिक्र किया। आपने अपनी उपलध्यिों में चम्बा, नाहन, और हमीरपुर का मैडिकल कॉलेज भी डाल दिया। यह मैडिकल कॉलेज गुलाम नवी आजाद ने जब वे यू.पी.ए. सरकार में स्वाथ्य मंत्री थे, उस वक्त की इनकी नोटिफिकेशन हुई है। आप आगे बढ़ो We are with you. आप रिसोर्सिज रेज करो। हम आपके साथ हैं। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हम रिसोर्सिज मोबेलाइज करेंगे। यह अच्छी बात है। प्रदेश को अगर अपने पैरों पर खड़ा होना है तो इस प्रदेश को अपने रिसोर्जि मोबेलाइज करने होंगे। मगर जो आपका बजट रिसोर्सिज मोबेलाइज करने में साइलेंट है। There is nothing in it. बहुत सारे सदस्य कहते थे कि रिसोर्स मोबेलाइज पर कमेटी बनी थी। वह कैबिनेट सब कमेटी होगी। जिसने काम नहीं किया होगा। मैं Resource Mobilization Generation Committee में चेयरमैन था। मैंने एक रिपोर्ट दी थी और मैं मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि आप उस रिपोर्ट को पढ़ें। जिसमें मैंने दिया है कि प्रदेश में सीमित साधन हों। अगर हमको संसाधनों के ऊपर काम करना है तो हमें अपने खर्चे कम करना पड़ेंगे।

कहते हैं Vice and virtue start from the top. मुख्य मंत्री , मंत्री, विधायक और अधिकारी अगर हर चीज में कटौती करेंगे तो यह हो सकता है। हिमाचल भवन जो दिल्ली और चंडीगढ़ में है वे आराम करने के अड्डे हैं।

14.03.2018/1245/SLS-AG-1

श्री हर्षवर्धन चौहान... जारी

चाहे राजनीतिज्ञों के हैं चाहे अधिकारियों के हैं। वहां बहुत सस्ता खाना और बहुत सस्ता कमरा मिलता है। आप उसको नो प्रॉफिट नो लॉस के स्तर पर लाओ। ऐसी बहुत सी छोटी-छोटी बातें हैं जिनको एड्रैस करने की आवश्यता है।

अध्यक्ष महोदय, हमें रिसोर्स जनरेट करने हैं। सुखराम चौधरी जी ने कल माइनिंग के बारे में ज़िक्र किया। हमारे पास प्रदेश में बहुत-सी माइन्ज हैं, मिनरल्ज हैं जिन्हें हमें निकालना है। अगर हम एक ही नज़रिए से किसी भी व्यक्ति को देखें, चाहें वह उद्योगपति है चाहे वह माइनिंग लैसी है कि वह तो चोर है, टैक्स की चोरी करता है, यह ठीक बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में यह एक मानसिकता बन गई है कि हम हर व्यक्ति को उसी एंगल से देखते हैं। अब हमें बाहर के लोगों के लिए भी प्रदेश के दरवाजे खोलने पड़ेंगे। हमें अपना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मज़बूत करने की ज़रूरत है।

आपने टूरिज्म के लिए 50 करोड़ रुपया रखा है। मैं कहता हूं कि यह एक अच्छी शुरुआत है मगर इसको और बढ़ाया जाना चाहिए। आपको प्राईवेट प्लेयर्ज़ को टूरिज्म में लाना पड़ेगा। अगर हमें हाई एंड टूरिस्ट प्रदेश में लाने हैं तो हमें यहां पर एक बड़ा एयरपोर्ट स्थापित करना पड़ेगा। हमारे शिमला एयरपोर्ट पर केवल छोटा जहाज उतरता है लेकिन एयर फेयर 12000-15000 रुपये तक है। कभी 22000 रुपये भी लगता है। इससे आम व्यक्ति या मिडल क्लास के व्यक्ति को बाई एयर आने में बड़ी दिक्कत पेश आ रही है।

अध्यक्ष महोदय, इंप्लायमैंट के बारे में यह बजट साईलैंट है। इस प्रदेश में लोगों को सबसे बड़ा रोज़गार का साधन सरकारी क्षेत्र में नौकरी है। मगर यह बजट सरकारी क्षेत्र को

लेकर साईलैंट है। मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो आपने प्रदेश के बेरोज़गारों के साथ वायदा किया था कि हम सत्ता में आते ही सरकारी क्षेत्र में रोज़गार के दरवाजे खोलेंगे, उसके बारे में बजट में कोई ब्योरा क्यों

14.03.2018/1245/SLS-AG-1

नहीं है। आप कह रहे हैं कि हम सिर्फ़ फंक्शनल पद ही भरेंगे। जब आप बजट पर हुई चर्चा का उत्तर देंगे तो मुख्य मंत्री जी, आप इस बारे में अवश्य खुलासा करें। अब आप कह रहे हैं कि हम स्वरोज़गार के साधन बढ़ाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश में पी.डब्ल्यु.डी., आई.पी.एच. आदि विभागों में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत विकास हुआ है; बहुत काम हुआ है। मुख्य मंत्री जी ने अपने मुख्य मंत्री कार्यालय में एक सैल स्थापित करने की घोषणा की है जो क्वालिटी कंट्रोल पर नज़र रखेगा। यह बहुत अच्छी बात है। हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं; चम्बा, कांगड़ा, शिमला, मण्डी आदि जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में क्वालिटी ऑफ वर्क इतना अच्छा नहीं है क्योंकि उसके ऊपर चैक नहीं है। यह अच्छी बात है कि आप यह शुरुआत कर रहे हैं और इसको चैक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा न हो कि क्वालिटी कंट्रोल में भी आप अपने RSS के लोग बिठा दें। ऐसा न हो कि फिर वह RSS के लोग केवल कांग्रेस के ठेकेदारों की ही चैकिंग करें और आपके लोगों की चैकिंग न हो। ऐसा नहीं होना चाहिए।

मुझसे पूर्व वक्ताओं ने यहां पर मुख्य मंत्री जी के दफ्तर के बारे में भी ज़िक्र किया। मैं यह कहना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री किसी भी अधिकारी को अपने दफ्तर में रख सकता है। मगर मुख्य मंत्री कार्यालय का एक ऐसा मैसेज बाहर नहीं जाना चाहिए कि वह केवल एक पार्टी का दफ्तर है या किसी एक विचारधारा के लोगों का दफ्तर है। मुख्य मंत्री का दफ्तर, it is a public office. वह लोगों का दफ्तर है। वहां से एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए, चाहे वह किसी भी वर्ग का आदमी है; छोटा है, बड़ा है या किसी भी दल का व्यक्ति है, उसको

न्याय मिलना चाहिए। मुख्य मंत्री जी, आपके कार्यालय के बारे में जो मैसेज बाहर जा रहा है, आप उसको थोड़ा-सा करैक्ट करने की कोशिश करें।

आप नौजवान हैं, ईमानदार हैं, आपसे लोगों ने बहुत-सी आशाएं, आकांक्षाएं और उम्मीदें रखी हैं और जैसे आपने बजट में गौसदन के बारे में जो ज़िक्र किया है, वह बहुत अच्छी शुरुआत है। गऊ माता हम हिंदुओं के लिए पूजनीय है। यह आपका

14.03.2018/1245/SLS-AG-3

बहुत अच्छा स्टैप है। मगर आप अलग से जो एक गौ-सेवा आयोग खड़ा करने जा रहे हैं, मुझे लगता है कि यह आप एक सफेद हाथी खड़ा कर रहे हैं। अभी भी हमारे बहुत से बोर्ड और कार्पोरेशन सफेद हाथी की तरह हैं। या आयोग बनाकर आप एक और नया हाथी खड़ा कर देंगे। (घंटी)

14/03/2018/1250/RG/DC/1
श्री हर्षवर्धन चौहान-----जारी

अध्यक्ष महोदय, मैं अभी समाप्त कर रहा हूं। अभी भी जो हमारे नाहन में गौ-सदन हैं वह अध्यक्ष महोदय के चुनाव क्षेत्र में है। उसका संचालन एवं देख-रेख जिला प्रशासन, उपायुक्त या एस.डी.एम. करते हैं। यदि आप एक नया आयोग खड़ा कर देंगे, तो शिमला से उन गौ-सदनों की मॉनीटरिंग नहीं होने वाली है। इसके अलावा इनफ्रास्ट्रक्चर, हैड ऑफिस, गाड़ी, टेलीफोन एवं अन्य खर्चे भी होंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी कृपया इस पर भी पुनर्विचार करें।

अध्यक्ष महोदय, आज इस सरकार को बने हुए लगभग दो महीने हो गए हैं। यह कोई बहुत लंबा अरसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम इतने से समय में आपकी कोई बहुत आलोचना करेंगे या नुक्ताचीनी करेंगे। लेकिन आने वाले समय में देखा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश की 65 लाख जनता की नजर आपके ऊपर होगी। आप मुख्य मंत्री बन गए हैं, लेकिन आज आप प्रदेश के लोकप्रिय नेता नहीं हैं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करिए।

श्री हर्षवर्धन चौहान : मैं समाप्त कर रहा हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी, आपको लोकप्रिय बनने के लिए जो आशाएं एवं आकांक्षाएं हिमाचल प्रदेश की जनता ने ज़ाहिर की हैं, उस पर आपको खरा उतरना पड़ेगा। कि आप कैसे चलेंगे, जनता को कैसे न्याय देंगे और आप पूरे 68 विधान सभा क्षेत्रों का विकास कैसे करेंगे? यह इस पर निर्भर करेगा और हम उम्मीद करेंगे कि आप जनता की आशाओं एवं आकांक्षाओं को पूरा करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने यहां बजट पेश किया है, यह खोखला एवं दिशाहीन है और इसमें हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए कुछ विशेष नहीं है इसलिए मैं इस बजट का समर्थन करने में असमर्थ हूं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

14/03/2018/1250/RG/DC/2

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य, श्री राकेश कुमार जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री राकेश कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री आदरणीय श्री जय राम ठाकुर जी ने जो वर्ष 2018-19 का बजट यहां प्रस्तुत किया है, उस पर लगातार यहां चर्चा चल रही है। हमारे विपक्ष के मित्र लगातार उस पर अनेक प्रकार की बातें कर रहे हैं। 'कभी पुरानी बोतल, नई शराब, कभी नई शराब, पुरानी बोतल।' इस प्रकार की चर्चा यहां हो रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने 9 मार्च, 2018 को जो बजट यहां प्रस्तुत किया है यह एक ऐतिहासिक बजट है। बजट के पश्चात जब हम लोग अपने क्षेत्रों में गए, तो लोगों के फोन आए और लोग हमसे मिले और अनेक प्रकार से हर वर्ग ने इस बजट को सराहा। इसके अतिरिक्त इस सदन के सबसे वरिष्ठ नेता माननीय श्री वीरभद्र सिंह जी जो 6 बार इस प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे हैं जिनका हम बहुत मान-सम्मान करते हैं और हमारे मुख्य मंत्री जी भी इनका मान-सम्मान करते हैं। इस तरफ बैठे हुए सभी लोग भी इनका बहुत मान-सम्मान करते हैं और जब हमें ये मिलते हैं, तो हम भी इनके पैर छूते हैं। जिस दिन मुख्य मंत्री जी बजट प्रस्तुत कर रहे थे, मैं देख रहा था कि मान्यवर श्री वीरभद्र

सिंह जी भी मेज थपाथपा कर इस बजट की तारीफ कर रहे थे। इसलिए मैं उधर बैठे हुए माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग माननीय वीरभद्र सिंह जी जो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, अनेक बातों में जब उनकी हां में हां मिलाते हैं और जब उन्होंने इस बजट को सराहा है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी इस बजट की तारीफ करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, यहां अनेक प्रकार की चर्चा की गई। श्री मुकेश अग्निहोत्री जी सदन के बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। पूर्व में मंत्री भी रहे हैं और वर्तमान में अपने दल के नेता हैं। इन्होंने कहा कि कि यह बजट खोखला, दिशाहीन है और साथ में यह भी कहा कि हमारी सरकार की योजनाओं को ही इस बजट में शामिल किया गया है। मान्यवर अग्निहोत्री जी, जो आपका बजट पांच वर्ष लगातार आता रहा, क्या आप उसकी तारीफ कर रहे हैं या उसकी आप आलोचना कर रहे हैं? मान्यवर मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में जिस प्रकार से हर वर्ग का ध्यान रखा है। सदन में चर्चा करते हुए आज मैं बताना चाहता हूं कि कुछ लोग

14/03/2018/1250/RG/DC/3

कह रहे हैं कि इस प्रकार का बजट और सरकार यदि इस प्रकार से काम करेगी, तो पांच वर्ष के पश्चात आपका क्या हश्र होगा? हम जानते हैं कि सिराज विधान सभा क्षेत्र वर्ष 1998 तक कांग्रेस का गढ़ रहा है, कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता वहां का प्रतिनिधित्व करते थे। ठाकुर कर्म सिंह जी एवं ठाकुर मोती राम जी ने वहां का नेतृत्व किया है।

14/03/2018/1255/MS/DC/1

श्री राकेश कुमार जारी------

लेकिन वर्ष 1998 में जब से माननीय जय राम ठाकुर जी ने उस सिराज विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना शुरू किया, लगातार 20 वर्ष हो गए, कांग्रेस का व्यक्ति वहां पर खड़ा नहीं हो पाया, टिक नहीं पाया। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जिस लगन और

ईमानदारी के साथ माननीय मुख्य मंत्री जी काम कर रहे हैं जैसे सिराज में पिछले 20 वर्षों से विकास हो रहा है, हिमाचल प्रदेश में भी आने वाले 20 वर्षों में जय राम ठाकुर जी की नेतृत्व वाली सरकार वैसे ही काम करेगी। -(व्यवधान)-

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आप कन्टीन्यू रखिए।

श्री राकेश कुमारः सुखविन्द्र जी, जब नये लोगों को मौका देंगे तभी तो कभी आपकी भी बारी आएगी।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आप चेयर की ओर रेफर कीजिए।

श्री राकेश कुमारः अध्यक्ष जी, विपक्ष के साथियों ने कहा कि हमारी सरकार को आर0एस0एस0 चला रहा है और आर0एस0एस0 का बहुत हस्तक्षेप है। मैं माननीय सदन को बताना चाहता हूं कि आर0एस0एस0 सरकार को नहीं चला रहा है बल्कि सरकार आदरणीय जय राम ठाकुर जी चला रहे हैं और बड़ी ईमानदारी और लगन से ये काम कर रहे हैं। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जय राम ठाकुर जी आर0एस0एस0 के स्वयंसेवक हैं और हम भी आर0एस0एस0 के स्वयंसेवक हैं। ये स्वयंसेवक सरकार चला रहे हैं और जनता के लिए चला रहे हैं। इसमें किसी को कोई अतिश्योक्ति नहीं होनी चाहिए।

अध्यक्ष जी, इसके साथ-साथ बजट में जिन चीजों का जिक्र आया, उनमें वृद्धावस्था पैंशन की आयु सीमा 80 वर्ष से 70 वर्ष कर दी गई। इसमें क्या बुरा किया गया? उसके साथ-साथ मजदूरों की दिहाड़ी 210/-रुपये से बढ़ाकर 225/-रुपये कर दी गई और फिर भी मेरे विपक्ष के सहयोगी विरोध कर रहे हैं कि बजट अच्छा नहीं है। इसमें मजदूरों के लिए क्या बुरा किया गया?

14/03/2018/1255/MS/DC/2

इसके साथ-साथ "केन्द्र सरकार की उज्ज्वला योजना" के बारे में भी हम सब जानते हैं। माननीय मोदी जी ने गृहिणियों के लिए क्योंकि उन्हें चूल्हा जलाते-जलाते कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, उनकी आंखें तक खराब हो जाती हैं और उन्हें सांस की समस्या हो जाती है तो उनके लिए "केन्द्र सरकार की उज्ज्वला योजना" की शुरुआत

की। जो परिवार इसमें से बच गए थे माननीय मुख्य मंत्री जी ने उनको कवर करने के लिए यह "हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना" की शुरुआत की है। इस योजना के बाद हिमाचल प्रदेश पूरे देश का पहला राज्य बन जाएगा जिसमें सभी परिवारों को गैस की सुविधा मिलेगी और इसके लिए वर्ष 2018-19 के लिए 12 करोड़ रुपये के बजट का भी प्रावधान किया गया है।

इसके साथ ही इस बजट में पार्ट टाइम वाटर कैरियर, मिड-डे मील वर्कर, एस0एम0सी0 टीचर, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता और जल रक्षकों के मानदेय बढ़ाए गए, इसमें क्या बुरा किया गया?

माननीय अध्यक्ष जी, शराब की एक बोतल पर जो एक रुपया गौवंश विकास के लिए माननीय मुख्य मत्री जी ने बजट में कहा है, उस पर भी उधर बैठे लोगों ने आपत्ति जाहिर की है। गौमाता की बात आदरणीय हर्षवर्धन चौहान जी भी कर रहे थे। पिछली सरकार में क्या हुआ और शराब की बिक्री किस प्रकार हुई, मैं उसकी चर्चा में नहीं जाना चाहता। लेकिन हमारे मान्यवर मुख्य मंत्री जी की और सरकार की नीति और नीयत स्पष्ट है जिसके चलते हम समाज के हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं।

इसके साथ ही बेसहारा पशुओं के कारण हम देख रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में लोग अपनी फसलें नहीं बीज रहे हैं क्योंकि बेसहारा पशु उन फसलों को खा जाते हैं। जिसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है कि गौ-सदन स्थापित करने के लिए एक रुपये पट्टे पर भूमि दी जाएगी। क्या यह बुरा काम किया गया? उसके साथ-साथ बेसहारा पशु-रहित पंचायत को 10 लाख रुपये देने की बात कही है, क्या यह बुरा काम है? सूखे की मार को देखते हुए मनरेगा की दिहाड़ी 100 दिन की बजाए 120 दिन कर दी गई, क्या यह बुरा काम किया गया?

14.03.2018/1300/जेके/एचके/1

श्री राकेश कुमारः------जारी---------

हमारे गरीब लोग, दूध उत्पादक उनके दूध खरीद मूल्य को एक रूपए प्रति लीटर बढ़ाने की बात बजट में कही गई है। क्या आप इसका भी विरोध कर रहे हैं? इसके साथ-साथ

सदन में चर्चा की गई कि विधायक निधि, ऐच्छिक निधि कम बढ़ाई गई। हम मान्यवर मुख्य मंत्री जी के धन्यवादी है, पक्ष या विपक्ष से किसी भी विधायक ने मांग नहीं की थी लेकिन फिर भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने विधायक निधि को 1.10 से 1.25 करोड़ रुपये किया है और ऐच्छिक निधि को पांच से सात लाख किया है। यह अभी ढाई महीने की बात है, चिन्ता न करें इसको और बढ़ाएंगें।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर कहा गया कि ये सारी योजनाएं हमारी सरकार की है। हम सभी जानते हैं कि अटल वर्दी योजना भारतीय जनता पार्टी की 2007 से 2012 की सरकार ने शुरू की थी। आपने उस योजना का नाम बदल दिया। क्या बुरा किया कि मान्यवर मुख्य मंत्री जी ने उस अटल वर्दी योजना में वर्ष में दो बार वर्दी के साथ-साथ पहली, तीसरी, छठी और 9वीं के बच्चों को स्कूल बैग देने की बात कही है? क्या आप इसका विरोध कर रहे हैं?

हमारे विपक्ष के साथियों ने लॉ एण्ड ऑर्डर की भी बात की और मुकेश अग्निहोत्री जी ने कहा कि मात्र आठ लाइनें कानून व्यवस्था पर बजट में लिखी गई है। मुकेश जी, ज्यादा लाइनें लिखने से कुछ नहीं होता। सरकार की नीयत और नीति ठीक होनी चाहिए। पूर्व सरकार में क्या हुआ था? आज सब लोग जानते हैं कि एस.आई.टी. गठित की गई उसके आई.जी., एस.पी.,डी.एस.पी. से लेकर एस.एच.ओ. तक को आज सी.बी.आई. ने जेल के अंदर डाला हुआ है। हमारी सरकार की मन्शा बिल्कुल साफ है। यह सरकार कानून व्यवस्था के ऊपर पूरा नियंत्रण रखेगी। आपके समय में जिस प्रकार हुआ वह चाहे होशियार सिंह कांड हो या गुड़िया कांड हो, मैं उसमें ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता लेकिन जो अच्छा हुआ है, अगर आप लोग उसकी तारीफ करते तो अच्छा होता । आपके

14.03.2018/1300/जेके/एचके/2

और सुझाव आते तो हम जैसे सदन में नये आए सदस्यों को भी सीखने को बहुत कुछ मिलता लेकिन राजनीति के लिए राजनीति करें, यह अच्छा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से माननीय जय राम ठाकुर जी की सरकार काम कर रही है, शहीदों के आश्रितों को, हमारा जवान जो बॉर्डर पर इस देश की रक्षा करता है, जब वह शहीद हो जाता है तो उसके परिवार को मात्र पांच लाख रुपये दिए जाते थे लेकिन माननीय जय राम ठाकुर जी की सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उनके परिवार के आश्रितों को पांच लाख की बजाय बीस लाख रुपये दिए जाएंगें। इसके साथ-साथ पैरा मिलिटरी को भी इसमें जोड़ा गया है ।

अध्यक्ष महोदय, बच्चे हमारा भविष्य है और उनका स्वास्थ्य सर्वोपरि है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने मुख्य मंत्री आशीर्वाद योजना के अंतर्गत सभी नवजात शिशुओं को 1500 रुपये मूल्य की नव आगन्तुक किट देने का बजट में प्रावधान किया है, हम उसकी सराहना करते हैं। इसके साथ-साथ जो उनकी माताओं को 700 रुपये दिए जाते थे, वह भी वैसे ही दिए जाएंगें और इसके लिए भी बजट में 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के साथी अनेकों प्रकार से यहां पर चर्चा कर रहे थे लेकिन हम सभी जानते हैं कि आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार केन्द्र में किस प्रकार काम कर रही है। यहां पर नोटबन्दी का जिक्र किया गया तथा अन्य बातों का भी जिक्र किया गया लेकिन कांग्रेस के मित्र यह भूल गए हैं कि आज नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में यह देश आगे बढ़ रहा है।

14.03.2018/1305/SS-HK/1

श्री राकेश कुमार क्रमागतः

अगर आप देश के नक्शे पर देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश से चलकर उत्तरांचल, जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा, छतीसगढ़, झारखंड से लेकर नॉर्थ-ईस्ट में त्रिपुरा तक आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सत्तासीन है। देश के नक्शे पर आप देखेंगे तो 80 प्रतिशत हिस्से में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें विभिन्न प्रदेशों में हैं। निश्चित तौर पर जिस प्रकार अभी मात्र ढाई महीने का कार्यकाल हमारी सरकार का हुआ है और इस ढाई महीने के कार्यकाल में अनेकों प्रकार के माननीय मुख्य मंत्री जी ने

हिमाचल प्रदेश के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी पिछली सरकार ने क्या किया हुआ है मैं उसका थोड़ा-सा ज़िक्र करना चाहता हूं। मेरे सुन्दरनगर में जो सिविल हॉस्पिटल है पिछली सरकार ने उस हॉस्पिटल का दर्जा 100 बैडिड से 150 बैडिड कर दिया था। लेकिन उसकी मात्र घोषणा ही हुई, धरातल पर कुछ नहीं हुआ। उसके साथ-साथ वहां पर पूर्व की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने एक टूरिस्ट इंफोरमेशन सैंटर के साथ-साथ एक रैस्टोरेंट का भी फाउंडेशन किया था जो बन कर तैयार हो गया था। लेकिन आज उसमें टूरिस्ट इंफोरमेशन सैंटर और रैस्टोरेंट की बजाय एशियन डिवैल्पमैंट बैंक का एक दफ्तर चल रहा है। इस प्रकार के काम वहां पर हुए हैं। बिना जमीन के प्राइमरी हैल्थ सैंटर के फाउंडेशन हो गए। यहां तक कि सदन में चर्चा भी आई कि पिछली सरकार में एक ऐसी पी0एच0सी0 की एनाउंसमैंट/नोटिफिकेशन हो गई जो स्थान हिमाचल तो हिमाचल बल्कि देश में भी नहीं है। बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान में है। इस प्रकार के काम आपकी सरकार में हुए हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश में मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक पायलट प्रोजैक्ट के रूप में अंडर ग्राउंड डस्टबीन बनाने का काम आपकी सरकार में शुरू हुआ था। मेरे सुन्दरनगर विधान सभा क्षेत्र में 40 अंडर ग्राउंड डस्टबीन लगने थे लेकिन मात्र 20 अंडर ग्राउंड डस्टबीन ही लगे थे, उसी का उद्घाटन करवा दिया गया। ऐसे काम आपकी सरकार में हुए हैं। निश्चित तौर पर जो यह बजट मान्यवर मुख्य मंत्री, जय राम ठाकुर जी ने प्रस्तुत किया है, बहुत सराहनीय बजट है। इसी प्रकार मान्यवर मुख्य मंत्री, जय राम ठाकुर जी के नेतृत्व में हमारी सरकार काम करेगी। जिस प्रकार से आज गुजरात, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ में लगातार 15-20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आ रही हैं हिमाचल प्रदेश भी आदरणीय जय राम ठाकुर जी के नेतृत्व में

14.03.2018/1305/SS-HK/2

एक इतिहास रचेगा। अब यह बारी वाली बात चली गई, अब लगातार हिमाचल प्रदेश में जय राम ठाकुर जी के नेतृत्व की सरकार आने वाले 20 वर्षों तक हिमाचल की जनता की सेवा करेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद।

अध्यक्षः अब इस माननीय सदन की बैठक दोपहर के भोजन अवकाश के लिए 2 बजकर 15 मिनट तक स्थगित की जाती है।

14.03.2018/ 1420/केएस/वाईके/1

सदन की बैठक दोपहर के भोजनोपरांत अपराह्न 2.20 बजे पुनः आरम्भ हुई।

अध्यक्षः अब इस चर्चा में श्री लखविन्द्र सिंह राणा जी भाग लेंगे।

श्री लखविन्द्र सिंह राणाः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं सर्व प्रथम माननीय जय राम ठाकुर जी की सरकार को पहला बजट अनुमान 2018-19 को विधान सभा में पेश करने के लिए बधाई देता हूं। हिमाचल प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया है और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हिमाचल प्रदेश की रक्षा करना और लोगों के कार्य करना अब इस युवा सरकार का कर्तव्य है।

अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में कहा है कि हिमाचल प्रदेश में सड़कों के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा और यह भी कहा कि केन्द्र सरकार ने 69 नेशनल हाईवेज़ स्वीकृत किए हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में सड़कों की हालत बड़ी खराब है और जो एन.एच. की बात यहां पर की गई है, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी तीन एन.एच. स्वीकृत हुए हैं। नालागढ़ से लेकर वाया राम शहर-शिमला नेशनल हाईवे, दूसरा, बद्दी से वाया पट्टा-बरोटीवाला-शिमला नेशनल हाईवे और एक अभी नये एन.एच. की घोषण हुई है । वह है घनोली-नालागढ़ वाया राम शहर । एक और नेशनल हाईवे भरतगढ़- दभोटा-पंजयारा-वघेरी है। मगर बड़े दुख की बात है कि तीन नेशनल हाईवेज़ काफी लम्बे समय से स्वीकृत हुए हैं लेकिन इनके ऊपर आज तक एक भी पैसा नहीं लगा है न ही उनका कार्य शुरू हुआ है । एन.एच. 21-ए जो कि नालागढ़ से स्वारघाट का रोड़ है, काफी लम्बे समय से उसका कार्य चल रहा है। दो सरकारें बदल चुकी है । पूर्व सरकार के समय में भी कई लोगों ने उस रोड़ को ले कर धरने प्रदर्शन किए और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय सरदार हरि नारायण सिंह जी ने भी उस सड़क को लेकर धरने व प्रदर्शन किए थे लेकिन उस सड़क की स्थिति ज्यों

14.03.2018/ 1420/केएस/वाईके/2

की त्यों बनी हुई है जबकि वह बहुत महत्वपूर्ण सड़क है क्योंकि मण्डी और कुल्लू मनाली के लिए पर्यटक पंजाब, चण्डीगढ़, हरियाणा, यू.पी. व बिहार से उसी सड़क के माध्यम से जाते हैं लेकिन इतना लम्बा समय बीत जाने के पश्चात भी आज तक उस सड़क का कार्य नहीं हुआ है।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे निर्वाचन क्षेत्र का आधा क्षेत्र पहाड़ी है और आधा मैदानी है । पहाड़ी क्षेत्र में सड़कें पंचायत के माध्यम से बनी हुई है लेकिन जब बरसात का समय होता है वे सड़कें बिल्कुल बन्द हो जाती है और किसानों को अपनी सब्जी बाज़ार तक पहुंचाने में बड़ी दिक्कत होती है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि उन सड़कों को पी.डब्ल्यू.डी. के अंतर्गत किया जाए ताकि वे सड़कें हर मौसम में चलती रहे।

दूसरा, आदरणीय अध्यक्ष जी, बजट में शिक्षा के बारे में बात कही गई

14.3.2018/1425/av/yk/1

श्री लखविन्द्र सिंह राणा ---- जारी

लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि राजा वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में पूर्व सरकार के समय में अनेकों प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, जमा दो स्कूल और कालेज खोले गए। यदि इन स्कूलों/कालेजों को सरकार राजनैतिक द्वेश की भावना से बंद करने का प्रयास करेगी तो यह हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। मैं इनको यह कहना चाहता हूं कि जहां पर स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं वहां अध्यापकों का इंतजाम किया जाए। जहां पर स्कूलों में भवन नहीं है वहां भवनों का निर्माण किया जाए। जहां कालेजों में प्रोफैसर नहीं हैं वहां प्रोफैसरों का इंतजाम किया जाए। मगर राजनैतिक द्वेश की भावना से इन स्कूलों/कालेजों को बंद करना बहुत गलत होगा। मैं राजा वीरभद्र सिंह जी का धन्यवाद

करना चाहता हूं क्योंकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पहले केवल नालागढ़ में एक कालेज हुआ करता था। मगर आज इनकी बदौलत वहां पर 5 कालेज हैं जो कि जयनगर, दीघर, रामबुशैहर और बरोटीवाला में स्थित है। मगर यहां पर मेरे कुछ मित्र इन शिक्षण संस्थानों को बंद करने की बात करते हैं। मैं अपने मित्रों से कहना चाहता हूं कि अगर हम नालागढ़ कालेज की बात करें तो यह 50 वर्ष पहले बना था। यदि उस समय की नालागढ़ हलके या दून की आबादी का जिक्र करें तो कुल मिलाकर वहां की आबादी मेरे ख्याल से 45 हजार से भी अधिक नहीं थी। अगर आज की आबादी की बात की जाए तो वहां पर 7-8 लाख के करीब आबादी है। उसको देखते हुए वहां पर कालेज/शिक्षण संस्थान खोलना स्वाभाविक है। इसके लिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इन संस्थानों को बंद नहीं किया जाना चाहिए।

मैं यहां पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कुछ बातें कहना चाहूंगा। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट में कहा है कि स्वास्थ्य क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा। यहां पर किडनी ट्रांसप्लांट की बात कही गई कि यह सुविधा आई0जी0एम0सी0 में मिलेगी और यह एक बहुत अच्छा निर्णय है तथा इसके लिए

14.3.2018/1425/av/yk/2

हम सरकार का स्वागत करते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर ढंग से चलें। हमने देखा है जब अल्ट्रासांउड या सी0टी0 स्कैन की मशीनें खराब होती है तो उनको ठीक करने के लिए कई-कई महीने लग जाते हैं तो इस ओर सरकार को विशेष ध्यान देना होगा। हमारे नालागढ़ निर्वाचन क्षेत्र में पी0एच0सी गुल्लरवाला, पी0एच0सी0 कालीबड़ी, पी0एच0सी0 जोगो, सी0एच0सी0 रामबुशैहर में डॉक्टरों की कमी है। इन स्वास्थ्य संस्थानों में जहां डॉक्टरों की कमी है उसको पूरा किया जाना चाहिए। हमारे नालागढ़ में सी0एच0सी0 होस्पिटल में हड्डी रोक विशेषज्ञ, रेडियोलोजिस्ट और चाइल्ड स्पैशेलिस्ट की कमी है। अगर नालागढ़ होस्पिटल की बात की जाए तो यह 50-60 साल

पहले राजा सुरेन्द्र सिंह जी जब पैप्सू में डवलैप्मैंट मिनिस्टर हुआ करते थे यह उस समय का बना हुआ है। अगर हम अपने हलके की उस समय की आबादी देंखे तो यह 15-20 हजार से ज्यादा नहीं थी। लेकिन अब उस हलके की आबादी देखी जाए तो कम-से-कम वहां पर 85 हजार तो वोट हैं, तीन लाख हलके की आबादी है और इण्डस्ट्री के कारण वहां पर जो आबादी आई है तो यह कुल मिलाकर लगभग 7-8 लाख बनती है। इसी के दृष्टिगत पी0एच0सी0 जोगो को सी0एच0सी0 किया जाए। हमारे वहां एक पंजियारा सब सैंटर है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आप जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो आपने भी वहां जाकर उसका निरीक्षण किया था और कहा था कि हम इसको पी0एच0सी0 बनायेंगे। उस सब सेंटर के नाम चार बीघा जमीन है लेकिन अभी तक वह पी0एच0सी0 नहीं बना। इसी तरह हमारे यहां एक अत्यंत दुर्गम क्षेत्र डोली पड़ता है, वहां पर भी लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही है। वहां पर भी एक पी0एच0सी0 बनाने की आवश्यकता है। आपको पता है कि ई0एस0आई0 बद्दी जो कि इण्डस्ट्री की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होस्टिपल है।

TCV द्वारा जारी....

14.3.2018/1430/TCV/AG-1

श्री लखविन्द्र सिंह राणा..... जारी

जो हमारे वर्कर्ज़ इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, उनके लिए ई0एस0आई0 अस्पताल, बद्दी बनाया गया है। वहां भी डॉक्टरों की कमी हैं। कृपया उस कमी को भी पूरा किया जाना चाहिए। यहां पर रोज़गार की बात की गई है। रोजगारों के बारे में भी सरकार ने बजट भाषण में उल्लेख किया है। यह सच है, हिमाचल प्रदेश में हर माता-पिता ये सोचता है कि हमारा बच्चा पढ़-लिखकर हमारा सहारा बने। उसको सरकारी नौकरी मिले। लेकिन नौकरी तभी मिल सकती है, अगर हम सभी विभागों में विभिन्न पदों का सृजन करें। मेरी आपसे गुजारिश है कि जो हमारे बेरोजगार लोग हैं, उनको सरकारी क्षेत्र में अधिक-से-अधिक रोज़गार मिलने चाहिए। मैं प्राइवेट सैक्टर की बात करना चाहूंगा। हमारे नालागढ़ में

BBNDA बना हुआ है। वहां पर बहुत इंडस्ट्रीज़ हैं। वहां पर काफी औद्योगिकरण हुआ है। सरकार की तरफ से भी निर्देश दिए गए हैं कि 70 प्रतिशत् रोजगार हिमाचल प्रदेश के लोगों को दिया जाएगा। लेकिन अगर वहां पर चैक किया जाये, तो 30 प्रतिशत् से अधिक रोज़गार हिमाचल प्रदेश के लोगों को नहीं दिया गया है। मैं माननीय उद्योग मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो उद्योग 70 परसेंट रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं, उनके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं बताना चाहता हूं कि DDNDA में लगभग 2600 फैक्टरिज़ हैं। ई0एस0आई0 में 1,75,000 वर्कर्ज़ रजिस्टर्ड हैं और उनको रोज़गार मिला हुआ है। इसके अलावा 1,50,000 ऐसे लोग हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, लेकिन वे भी वहां पर नौकरी कर रहे हैं। इन उद्योगों में हिमाचली लोगों को बहुत कम रोज़गार मिला हुआ है। इस ओर सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यहां पर अभी कहा गया कि उद्योगों को अधिक तरजीह दी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि BBNDA में या हिमाचल प्रदेश में नये उद्योगों को आमंत्रित करना चाहिए। ताकि हमारे हिमाचल प्रदेश का रेवेन्यू बढ़ सकें।

आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने यहां पर किसानों के लिए सिंचाई की बात की है। लेकिन बड़े दुःख की बात है कि आज भी हमारे किसानों को

14.3.2018/1430/TCV/AG-2

पानी के लिए आसमान पर निर्भर रहना पड़ता है, उनको बारिश के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। हमारा किसान किसी अन्य राज्य से कम नहीं हैं। हमारे साथ में पंजाब लगता है, लेकिन अगर हम पंजाब के किसान की बात करें, तो वे हिमाचल प्रदेश के किसान-बागवानों से अधिक सुदृढ़ हैं। हमारे किसानों के लिए सिंचाई की योजनायें बननी चाहिए। अगर हमारे किसानों को सिंचाई की योजनायें बने, उनको पर्याप्त पानी मिले, तो मैं कह सकता हूं कि हमारा हिमाचल प्रदेश का किसान पूरे भारतवर्ष में प्रथम आ सकता है। इसके लिए हमें ज्यादा-से-ज्यादा सिंचाई के ट्यूबवैल लगाने पड़ेंगे। मेरे निर्वाचन क्षेत्र नालागढ़ में

बहुत पहले से सिंचाई के लिए ट्यूबवैल लगाये गये थे, लेकिन वे अभी भी बंद पड़े हुए हैं और उनमें ढ़क्कन लगे हुए हैं। उनको भी खोलने का प्रयास किया जाना चाहिए।

सरकार की तरफ से यहां पर पेयजल योजना के बारे में पूरा आश्वासन दिया गया है कि किसी को भी प्यासे नहीं मरने दिया जाएगा। अभी गर्मियां शुरू होने में थोड़ा समय हैं, लेकिन अभी भी पीने के पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। परन्तु उसके लिए हमें चाहिए कि जो पेयजल योजनाएं लम्बे समय से बनी हुई है या तो उन पेयजल योजनाओं को डेवैल्प किया जाये या उनकी जगह नई पीने के पानी की योजनायें बनाई जायें। प्रदेश में कुछ पेयजल स्कीमें प्राइवेट ठेकेदारों को भी दी हुई हैं। इनमें जब कोई मोटर खराब हो जाती है, तब कई-कई दिनों तक लोगों को पानी नहीं मिल पाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि जो भी सिंचाई एवं पेयजल योजनाएं हैं, वहां पर दो-दो मोटरें एक्सट्रा होनी चाहिए।

14-03-2018/1435/NS/AG/1

श्री लखविन्द्र सिंह राणा------जारी

प्राईवेट ठेकेदारों को हमारे पीने के पानी की स्कीमें दे रखी हैं। जब कोई मोटर या पम्प खराब हो जाता है तो कई दिनों तक लोगों को पानी नहीं मिलता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि जहां पेयजल योजनायें, सिंचाई की योजनायें हैं, वहां पर दो-दो एक्स्ट्रा मोटर्ज़ और पम्पस होने चाहिए ताकि एक मोटर या पम्प खराब होने की स्थिति में अविलम्ब लोगों को 12 घंटें के अंदर पानी मुहैया करवाया जा सके। मैं आपसे ऐसी गुज़ारिश करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इस माननीय सदन में कानून व्यवस्था की भी बात कही गई है कि कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है। हम बी0बी0एन0 में देखते हैं कि हर रोज़ चोरी, डकैती, कत्ल और बलात्कार की घटनायें दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। उसका मुख्य कारण यह है कि वहां पर पुलिस बल बहुत कम है। वहां पर पुलिस बल की संख्या लगभग 300 है और

वहां पर फैक्टरियों के स्टॉफ और वर्करों की संख्या लगभग 7 या आठ लाख है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वहां पर एक अतिरिक्त बटालियन दी जाये ताकि कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। नालागढ़ में इंडस्ट्रीज़ बहुत लगी हैं। लेकिन पोल्यूशन विभाग की तरफ से जो उद्योग वहां पर लगे हुए हैं, वे वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। जो उन्होंने वाटर ट्रीटमैंट प्लांट लगाना होता है, वे उसको न लगा कर अपनी फैक्टरी की चार दीवारी के अंदर बड़े-बड़े गड्डे बना कर या कुंआ खोद कर वेस्ट पानी को इसमें डाल देते हैं। यह पानी जब लोगों के स्रोतों में चला जाता है तो लोग बीमार होते हैं। जो फैक्टरियां इन नियमों को उल्लंघन कर रही हैं, इनके खिलाफ़ विभाग को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश की आमदनी को बढ़ाने के लिए मेरा एक सुझाव है। हमें हाईड्रो पॉवर की क्षमता का दोहन करना चाहिए। दूसरा सुझाव यह है कि हमें पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए। अगर हम अच्छे ढंग से यह काम कर लेते हैं तो हमें कर्ज़ लेने की आवश्यकता नहीं है और लोगों पर टैक्स लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। आपने "विधायक क्षेत्र विकास निधि" की राशि 1.10 करोड़ से बढ़ा करके 1.25 करोड़ की है, मैं उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। लेकिन यह राशि

14-03-2018/1435/NS/AG/2

1.50 करोड़ होनी चाहिए थी क्योंकि निर्वाचन क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 42 पंचायतें हैं। लेकिन फिर भी आपने जो यह राशि बढ़ायी है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं।

आपने वृद्धावस्था पैंशन धारकों की आयु सीमा 80 वर्ष से घटा करके 70 वर्ष की है, यह भी अच्छा निर्णय है। अध्यक्ष महोदय, बहुत से लोगों ने पैंशन के लिए आवेदन किया हुआ है। उन्हें जल्दी-से-जल्दी पैंशन मिलनी चाहिए। इन आवेदनों पर जल्दी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि उनको पैंशन का लाभ मिल सके। पंचायत के प्रधानों, उप प्रधानों, बी0डी0सी0 और जिला परिषद मैम्बरों का जो आपने मानदेय बढ़ाया है, यह भी सरकार का अच्छा निर्णय है। इससे हमारी पंचायतों का तंत्र मज़बूत होगा और हमारी पंचायतों को वित्तीय, न्यायिक और एग्जीक्यूटिव शक्तियां देने की भी आवश्यकता है ताकि छोटे-छोटे केस पंचायत के लैवल पर ही हल किये जा सकें। विधायकों की ऐच्छिक निधि आपने 5

लाख से 7 लाख की है। माननीय मुख्य मंत्री जी का यह अच्छा निर्णय है। क्योंकि इससे गरीबों और संस्थाओं के कल्याण के लिए लाभ मिलेगा। आपने मज़दूरों की जो दिहाड़ी बढ़ायी है, यह भी ठीक निर्णय है लेकिन यह दिहाड़ी उतनी नहीं बढ़ी है जितनी बढ़नी चाहिए थी। क्योंकि मज़दूर हमारा ऐसा वर्ग है जो कड़ी मेहनत करके अपने बच्चों का पालन-पोषण करता है।

अध्यक्षः माननीय सदस्य कृपया वाईंड अप करें।

श्री लखविन्द्र सिंह राणाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं कि मेरे नालागढ़ क्षेत्र में तीन सीमेंट प्लांट लगे हुए हैं। अम्बुजा, ए0सी0सी0 और जे0पी0 अल्ट्राटैक सीमेंट प्लांट लगे हुए हैं। बड़ी हैरानी की बात है कि हमारे क्षेत्र में सीमेंट बनता है और हमारे यहां महंगा है तथा पंजाब में सीमेंट सस्ता है। यहां पर उद्योग मंत्री जी नहीं बैठे हैं। इनको इस तरफ ध्यान देना चाहिए। ये प्लांट्स बहुत प्रदूषण दे रहे हैं और इन प्लांट्स में हमारे लोगों को रोज़गार भी कम है।

14.03.2018/1440/RKS/DC-1

श्री लखविन्द्र सिंह राणा... जारी

लेकिन मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय उद्योग मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इसकी ओर ध्यान दिया जाए। अभी जे.पी. से अल्ट्राटैक में वह उद्योग ट्रांसफर हुआ है। लेकिन हमें शंका है कि हमारे स्थानीय लोग जो वहां पर काम करते हैं, उनको हटाने का प्रयास किया जा रहा है। इस ओर भी विशेष ध्यान दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय, नालागढ़ में ट्रक ऑप्रेटर्ज़ की बहुत बड़ी युनियन है। जिसमें 8 हजार से अधिक ट्रक ऑप्रेटर्ज़ काम करते हैं। लगभग 16000 लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसके साथ जुड़े हुए हैं। पहले उन ट्रकों की पासिंग HRTC से होती थी और इस पासिंग को आर.एम. या डब्ल्यू.एम. करते थे। लेकिन अब यह अधिकार RTO ने छीन लिया है। हमारे स्थानीय लोगों को चाहे वे ट्रक मालिक हो या ट्रक ऑप्रेटर्ज़ हों, उन्हें बहुत दिक्कत आ रही है। (घंटी..) माननीय परिवहन मंत्री यहां पर उपस्थित नहीं है लेकिन मैं आपके

माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि यह पॉवर पुनः HRTC के RM या WM को दी जाए।

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 30 लाख रुपये की लागत से सामुदायिक भवन बनाने के बारे में यहां पर कहा गया । यह भी एक अच्छा निर्णय है। मार्किट की सुविधा के लिए Self Help Product द्वारा सामान तैयार करने के लिए इसी भवन में स्थान दिया जा सकता है। जैसे कोई चट्टनी, आचार, जुराबें या मफ़लर बनाता है तो उनको भी इस भवन में स्थान मिल सकता है। पांच लाख तक की राशि के टैंडर PWD के ई-पोर्टल के माध्यम से करने का निर्णय बहुत अच्छा निर्णय है। लेकिन इसमें निगरानी रखने की आवश्यकता है। हमने कई बार देखा है कि अधिकारी 5 लाख रुपये तक राशि पहुंचने ही नहीं देते हैं और वे 4 लाख रुपये के नीचे ही टैंडर कर देते हैं। किसी एक आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए वे काम आबंटित कर देते हैं। ई-पोर्टल से बचने के लिए जो ऐसा काम अधिकारी करते हैं उनकी और ध्यान देने की आवश्यकता है। यहां पर गौ-सदन की बात कही गई। यह एक बहुत अच्छा निर्णय है।

14.03.2018/1440/RKS/DC-2

अध्यक्षः माननीय सदस्य कृपया वाइंड-अप कीजिए।

श्री लखविन्द्र सिंह राणाः अध्यक्ष जी, मेरा कहना है कि जो गउएं सड़कों पर घुमती हैं उनको भी गौ-सदन में रखा जाए। सरकार को गौ-सदनों के लिए अधिक-से-अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए। पंचायतों को भी गौ-सदन बनाने के लिए बाध्य करना चाहिए ताकि गउएं गौ-सदन में रह सके।

इसी तरह हम HRTC की बात करते हैं। हमारे नालागढ़ डिपो में 105 बसें हैं जिनमें से 81 बसें ऑन रोड चलती हैं। इनमें 80 कंडक्टर्ज़ और 24 ड्राइवर्ज़ शोर्ट हैं। यह बहुत बड़ा एरिया है। इसमें दो विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र नालागढ़ और दून कवर होते हैं। इसके

अलावा इंडस्ट्रीज के वर्कर्ज़, उनकी लेबर और स्टॉफ के लोगों को भी यातायात की असुविधा होती है। इसके लिए हमें अधिक बसों की आवश्यकता है ताकि लोगों को यातायात की सुविधा प्राप्त हो सके। कई रोड पी.डब्ल्यू.डी. से पास हैं परन्तु उन रोडों पर भी बसें नहीं चलती हैं। गडौण- दरमाणा जहां पर बस चलनी थी, वह अभी नहीं चली है। इसके लिए मैंने माननीय मंत्री जी से आग्रह किया था। उन्होंने इसके लिए आदेश भी दिए थे लेकिन अभी तक आर.एम. ने उन्हें इम्प्लिमैंट नहीं किया।

अगर हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं तो इसके लिए 'गुड़िया हैल्प लाइन', 'होशियार सिंह हैल्प लाइन' शुरू की गई है। यह एक अच्छा निर्णय है। लेकिन फिर भी महिलाओं के साथ अत्याचार बंद नहीं हुए। दिन-प्रति-दिन महिलाओं के साथ अत्याचार की घटना हो रही है। मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है कि हमारे नालागढ़ उप-मंडल, बद्दी में जो पुलिस स्टेशन है वहां पर पुरुष को एस.एच.ओ. लगा दिया।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया आप आधे मिनट में समाप्त करें।

श्री लखविन्द्र सिंह राणाः अध्यक्ष महोदय, नालागढ़ शहर में 6000 से ज्यादा लोगों की संख्या है। वहां के लोगों को पीने के पानी की बड़ी दिक्कत आ रही है। मैं चाहता

14.03.2018/1440/RKS/DC-3

हूं कि उस ओर भी विशेष ध्यान दिया जाए। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में शिक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे स्कूल हैं जिनको अपग्रेड करना अति आवश्यक है। गवर्नमैंट हाई स्कूल, Sai Charog का दर्जा प्लस टू किया जाए। गवर्नमैंट मिडल स्कूल, रामपुर पसवांला को मैट्रिक किया जाए। गवर्नमैंट प्राइमरी स्कूल, सलैहंडा को मिडिल किया जाए। क्योंकि वहां पर 60% आबादी एस.सी. की पड़ती है।

14.03.2018/1445/बी0एस0/वाई0के-1

श्री लखविन्द्र सिंह राणा........... जारी

दो हमारे वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नडोर और वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रतवाड़ी है। वहां पर साईंस ब्लॉक की अति आवश्यकता है। इसी तरह हमारे नालागढ़ में बहुत एक्स सर्विस मैन रहते है वहां पर एक बीघा जमीन है वह एक्स सर्विव मैन के नाम है लेकिन अभी तक वहां सैनिक विश्राम गृह नहीं बना है। इसी तरह हमारे बी0डी0ओ0 कार्यालय वहां है। जो बी0डी0ओ0 कार्यालय नालागढ़ है वह तीन चुनाव क्षेत्रों को डील करता है। अर्की को भी करता है, दुन को भी करता है और नालागढ़ को भी करता है। इसलिए ज्यादा पंचायतें होने के कारण वहां पर एक अलग बी0डी0ओ0 ऑफिस होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, सिर्फ दो मिनट का समय दे दीजिए।

अध्यक्षः दो मिनट का नहीं आपको 25 मिनट 8 सैंकिड हो गए।

श्री लखविन्द्र सिंह राणाः अध्यक्ष महोदय, खनन माफिया की यहां बात हुई, हमारे नालागढ़ में भी जो खनन माखिया है वह बहुत सक्रिय है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो पुलों के नजदीक क्रशर स्थापित किए गए हैं। महादेव नदी के पास एक क्रशर को स्थापित करने की अनुमति दे दी गई। इनको भी चैक किया जाना चाहिए। यह किन नियमों के आधार पर स्थापित किए गए है। इसी तरह बी.बी.एन.डी. ए. में, क्योंकि हमारा नालागढ़ बी.बी.एन.डी.ए. में पड़ता है। बहुत सी सड़के बी.बी.एन.डी.ए.के माध्यम से पक्की होती है। लेकिन उन सड़कों की गुणवत्ता की हम बात करें तो सड़के बनती बाद में है उखड़ पहले जाती है। लेकिन उसके लिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं , एक हमारे राम शहर रोड़ के पास एक स्थान है वहां पर पार्क बनाया गया । जबकि विभाग को पता था कि जहां वह पार्क बना रहे हैं वह स्थान नेशन हाईवे में आ गया है। लेकिन वहां पर तीन घोड़े खड़े कर दिए गए।

अध्यक्षः माननीय सदस्य कृपया वाईंडअप करें। मैं अगले सदस्य को बुलाने जा रहा हूं।

14.03.2018/1445/बी0एस0/वाई0के-2

श्री लखविन्द्र सिंह राणाः मुझे लगता है कि बी.बी.एन.डी.ए. में जो कार्य हो रहे हैं करोड़ों रुपये का घपला हो रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। अध्यक्ष जी अब आप हमें मौका नहीं दे रहे हैं तो मैं यही पर वाईंडअप कर रहा हूं। आप तो हमारे पुराने साथी हैं। जो यहां पर बजट पेश किया गया है यह दिशाहीन है, निराशाजन है इसलिए मैं इसकी निंदा करता हूं।

14.03.2018/1445/बी0एस0/वाई0के-3

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री सुरेश कुमार कश्यप जी अब इस चर्चा में भाग लेंगे।

श्री सुरेश कुमार कश्यपः माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी ने 9 मार्च, 2018 को जो बजट पेश किया मैं भी उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। निश्चित रूप से यह बजट विकासोन्मुखि बजट है। दृष्टि पत्र को नीतिगत दस्तावेज बनाना, हिमाचल प्रदेश की विकास नीतियों की दिशा तय करेगा। जैसा कि यहां हमारे विपक्ष के साथी कह रहे थे कि 'new wine in old bottle', किसी ने कहा'old wine in new bottle' किसी ने कहा 'same wine in same bottle but label is changed'. जब आप मानते हैं कि सब कुछ वैसा ही है तो आप लोगों को इस बजट का समर्थन करने में तकलीफ क्यों है? आपको इस बजट का समर्थन करना चाहिए। भाई लखविन्द्र राणा जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने ज्यादातर इस बजट का समर्थन किया। इनकी मजबूरी है कि उधर बैठें हैं । इसलिए इसका समर्थन नहीं कर सके। मैं इनको बधाई देना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने जो घोषणाएं इस बजट की हैं उनका आपने समर्थन किया है और मन से समर्थन किया है। दुर्भाग्य रहा कि आपका नाम काट दिया गया, आपके कुछ साथी बीच में बोलने लग गए । राणा जी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं । आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है।

चाहे किसान है, बागवान है, युवा वर्ग है चाहे हमारे वृद्ध हैं, चाहे अधिकारी / कर्मचारी हैं। महिला वर्ग है, अनुसूचित जाति वह जनजाति वर्ग है सभी वर्गों के लिए इस बजट में कुछ न कुछ दिया गया है।

14.03.2018/1450/DT/HK-1

श्री सुरेश कुमार कश्यप ....जारीः

किसानों कि अगर हम बात करें और जैसा कि हमारे देश के प्रधान मंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का सपना है कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना है। उस दिशा में आदरणीय जय राम ठाकुर जी ने भी किसानों के लिए बिजली की दर को एक रूपये से घटाकर 75 पैसे पर युनिट किया। सौर ऊर्जा से सिंचाई योजनाएं चलें उसके लिए अगले 3 वर्षो के लिए दो सौ करोड़ रूपये व्यय करने का लक्ष्या रखा गया ताकि जो हमारी सिंचाई योजना हैं वे सौर ऊर्जा से चलें। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया गया ताकि जैविक खेती को बल मिले। उसके लिए प्राकृतिक खेती कुशल किसान योजना को लाया गया है। आज हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम बहुत ज्याद खाद और कीटनाशक का उपयोग कर रहे हैं। निश्चित रूप से यह हमारे जीवन के लिए काफी घातक है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से छोटी उम्र में ही बच्चों को किस प्रकार की बिमारियां लग जाती हैं। निश्चित रूप से यह बहुत ही सराहनीय कदम है कि जैविक खेती की और किसानों को ले जाया जा सके। जहां तक बन्दरों और बेसहारा पशुओं की बात है इसके लिए मुख्य मंत्री क्षेत्र संरक्षण योजना और साथ ही सोलर फैंसिंग जिसमें 85 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान किया गया है बहुत ही सराहनीय कदम है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक अनुरोध करना चाहूंगा कि हम सोलर फैंसिंग के लिए 85 प्रतिशत सब्सिडी दे रहे हैं। लेकिन किसानो को कांटेदार फैंसिंग के लिए भी प्रावधान किया जाए और उस में भी सब्सिडी भी दी जाए। अगर बागवानी की बात करे तो बागवानी क्षेत्र में एंटि हेलगन लगवाने कि लिए 60 प्रतिशत सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। फलोरिकल्चर को बढावा देने

के लिए हिमाचल पुष्प क्रांति योजना में 10 करोड़ रूपये का बजट रखा गया है। मेरा विधान सभा क्षेत्र है वहां फुलों की बहुत खेती होती है। किसानों को इसका लाभ मिलेगा। मधुमक्खी पालन की बात करें तो उस में 80 प्रतिशत सब्सिडी देने का प्रावधान रखा गया है ताकि जो

14.03.2018/1450/DT/HK-2

हमारे नौजवन साथी हैं या किसान भाई हैं उन्हें मधुमक्खी पालन का कार्य करना चाहिए और वे इसका लाभ उठा सके। इसी प्रकार बेसहारा पशुओं के संरक्षण के लिए, गउओं के संरक्षण के लिए, गौ सेवा सदन की स्थापन की गई है। एक बहुत ही अच्छा कार्य जो हमारे मदिरों में जो चढ़ावा आता है इसका 15 प्रतिशत इन गौ सदनों के रख-रखाव के लिए खर्च किया जाएगा। जब कि पिछली सरकार के समय में तो इसका उपयोग लगज़री गाड़ियों को खरीदने के किया जाता था। यह एक बहुत ही अच्छा काम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जय राम ठाकुर जी ने किया है। इसके अलावा चाहे पंचायती राज को सुदृढ़ करने की बात हो, मैं इस सदन को बताना चाहुंगा कि हमारी भाजपा कि पूर्व सरकार के समय में ही महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण अदरणीय धूमल जी के समय में दिया गया था। इस सरकार ने पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए, पंचायती राज से जुड़े सदस्यों के मानदेय में वृद्धि की है। मनरेगा के कार्य में सौ दिन के स्थान में एक सौ बीस दिन का कार्य करने के लिए मजदूरों को इसका लाभ दिया गया है। साथ में मजदुरों की दिहाड़ी को बढ़ा कर 225 रूपये कर दिया गया है। वृद्वावस्था पैंशन के लिए जो आयु 80 वर्ष होती थी उसको 70 वर्ष कर दिया गया। पूर्व भाजपा सरकार के समय में जिस प्रकार से हर विधान सभा क्षेत्र 10-10 लाख रूपये की लागत से अंबेदकर भवन बने थे उसी तर्ज पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री लोक भवन योजना के तहत हर विधान सभा क्षेत्र को 30-30 लाख रूपये सामुदायिक भवन बनाने के लिए और जो विधायक और सांसद एक से ज्यादा 2-3 सामुदायिक भवन बनाना चाहते हैं उसके लिए 15 लाख रूपये सरकार देगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए

यह भी एक बहुत सराहनीय कदम है। निश्चित रूप से शहरो में जो भी कोई बड़ा फंक्शन या शादी व्याह हो वहां पर व्यवस्था होती है। । लेकिन गांव में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होती है। यह बहुत अच्छा सराहनीय कदम इस सरकार ने उठाया है। सभी लोगों को इसका समर्थन करना चाहिए।

14.03.2018/1455/SLS-YK-1

श्री सुरेश कुमार कश्यप... जारी

विधायक निधि की जहां तक बात है उसको भी 1.10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.25 करोड़ रुपये करना और एच्छिक निधि को 7.00 लाख रुपया करना भी सराहनीय कदम हैं। ऐसी और बहुत-सी योजनाएं लाई गई हैं जो हमारे प्रदेश को आगे ले जाए। उनका बजट में प्रावधान किया गया है।

कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए और वन माफिया, शराब माफिया और भू-माफिया पर शिकंजा कसा जाए, इसकी भी सरकार द्वारा व्यवस्था की गई है। जैसी दशा हमने पिछले 5 सालों में देखी है, निश्चित रूप से उस समय हमारा प्रदेश कानून-व्यवस्था के मामले में पूरी तरह से विफल रहा। आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने गुड़िया हैल्प लाईन और होशियार हैल्प लाईन स्थापित की हैं जो सराहनीय कदम है।

महिलाओं के लिए हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश में उज्ज्वला योजना लागू की है जिसके तहत बी.पी.एल. परिवार की सभी महिलाओं को मुफ्त गैस कनैक्शन मिल रहे हैं। लेकिन प्रदेश के मुख्य मंत्री ने भी हिमाचल गृहणी सुविधा योजना के अंतर्गत सभी परिवारों को गैस कनैक्शन मिलें, ऐसी योजना लाई है ताकि कोई भी घर ऐसा न रहे जिसमें गैस कनैक्शन न हो। इससे महिलाओं को बालन इकट्ठा करने से भी छुटकारा मिलेगा। साथ ही इससे धुएं से होने वाली श्वास संबंधी बीमारियों से भी छुटकारा मिलेगा। निश्चित रूप से आदरणीय मुख्य मंत्री जी यह एक बहुत बढ़िया योजना लेकर आए हैं। सभी लोगों को इसका समर्थन करना चाहिए।

बेरोज़गारी भत्ते की बात को लेकर पिछली सरकार सत्ता में आई थी। उस समय सरकार ने युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा किया था। आपने उस समय घोषणा-पत्र में कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो आते ही सभी बेरोज़गारों को बेरोज़गारी भत्ता देंगे। लेकिन 5 वर्ष तक इनकी सरकार सोती रही और जाते-जाते इन्होंने आखिरी बजट में मात्र 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। पूरे 5 वर्ष में मात्र 21000 लोगों को इन्होंने बेरोज़गारी भत्ता दिया जबकि आज प्रदेश में लगभग 15 लाख युवा बेरोज़गार हैं।

14.03.2018/1455/SLS-YK-2

निश्चित रूप से यह युवाओं के साथ एक बहुत बड़ा छलावा हुआ था जिसका परिणाम यह हुआ कि आज हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। लेकिन मैं आदरणीय जय राम ठाकुर जी को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने युवाओं के लिए उद्योग लगाने के लिए 40 लाख रुपये तक के निवेश पर 25% सब्सिडी के साथ और युवतियों के लिए 30% सब्सिडी के साथ देने का प्रावधान किया है। उद्योग हेतु 40 लाख रुपये तक के ऋण पर 3 वर्ष के लिए केवल 5% ब्याज रखा गया है। सरकारी भूमि को पट्टे पर लेने पर केवल 1% दर पर उनको उद्योग लगाने के लिए भूमि मिलेगी। इसी प्रकार से कौशल विकास भत्ते को जारी रखा गया है। युवा अगर भूमि खरीद करना चाहते हैं तो उनके लिए स्टैंप ड्यूटि को 6% से घटाकर मात्र दिन 3% कर दिया गया है। इस तरह इस सरकार ने युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा कार्य किया है। निश्चित रूप से प्रदेश के युवाओं को, जो पिछली सरकार ने ठका था, उनके लिए बहुत अच्छी योजनाएं लाई गई हैं ताकि वह अपना कार्य कर सकें। इस बजट में माननीय मुख्य मंत्री ने इसका प्रावधान किया है। मैं इसके लिए इनको बधाई देना चाहूंगा और इसके लिए इनका धन्यवाद करना चाहूंगा।

जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। यहां पर अगर सही से पर्यटन का दोहन हो तो हमारे युवाओं को रोज़गार मिल सकता है और प्रदेश की आर्थिकी में भी सुधार हो सकता है। इस बजट में इसके लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मैं पिछले 2-3 वर्षों का बजट देख रहा था। उसमें हर बार बजट को बढ़ावा देने की बात की गई है लेकिन कहीं भी उसमें इस तरह से बजट का प्रावधान नहीं है। इन्होंने हर जगह कहीं साहसिक टूरिज्म तो कहीं रिलीजियस टूरिज्म कह कर, इस

प्रकार की घोषणाएं की हैं लेकिन पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके, उसके लिए किसी प्रकार के बजट का प्रावधान नहीं था। मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि हाई एंड टूरिस्ट, जो दूसरे देशों से हमारे यहां घूमने आता है, उन्हें हैलि-टैक्सी की सुविधा देने की भी बात की गई है। साथ ही उड़ान-2 के तहत हैलिपैड का निर्माण करने की योजना भी एक सराहनीय कदम है ताकि हमारे लोगों को लाभ हो और प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिल सके।

14/03/2018/1500/RG/YK/1

श्री सुरेश कुमार कश्यप-----जारी

हमारे प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। यदि मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करूं, तो वहां धार्मिक पर्यटन की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। हमारे यहां शिरगुल महादेव की जन्मस्थली है जिसको हम धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा दे सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे यहां भाभ्न का क्षेत्र है, जो प्रजोता काण्ड जो हुआ था, वहां के स्वतंत्रता सेनानी का वह क्षेत्र है, उसको भी हम पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा दे सकते हैं। इसी प्रकार हमारे यहां एक भूरेश्वर महादेव हैं। वहां एक बहुत सुन्दर मंदिर बना हुआ है और वह भी एक बहुत अच्छी जगह है। उसको भी हम धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा दे सकते हैं। इसके साथ-साथ यहां और भी पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र में एक सेज़गाच जगह है जहां पिछले दिनों हमारी सरकार के समय पैराग्लाइडिंग की संभावनाएं तलाशी गई थीं और वहां इसके लिए ट्रायल भी हुआ था। वहां पैराग्लाइडिंग की सुविधा प्रदान की जा सकती है। तो एक बहुत अच्छा कदम आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने इस ओर बढ़ाया है और आने वाले समय में निश्चित रूप से लोगों को इसका लाभ मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर मैं शिक्षा की बात करूं, तो शिक्षा के क्षेत्र में मैं आदरणीय शिक्षा मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा। गुणवत्ता वाली शिक्षा हमारे प्रदेश में बच्चों को मिले, उसके लिए इन्होंने कदम बढ़ाया हुआ है। जैसे हमारे यहां 'मुख्य मंत्री आदर्श विद्या केन्द्र' की स्थापना करना। जिन विधान सभा क्षेत्रों में नवोदय या एकलव्य विद्यालय नहीं हैं वहां आदर्श विद्या केन्द्र की स्थापना करना ताकि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल सके।

शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिदिन स्थानान्तरण की बहुत समस्या रहती है। तो शिक्षा में आदरणीय शिक्षा मंत्री जी एक ट्रांसफर पॉलिसी लेकर आने वाले हैं जैसा इस बजट में कहा गया है। यह एक बहुत ही सराहनीय कदम है। यही नहीं बल्कि हमारे प्रदेश में शिक्षकों की भी कई कैटागिरी बनाई गई हैं। जैसे पी.टी.ए., एस.एम.सी., विद्या उपासक इत्यादि और सभी शिक्षक चाहे जे.बी.टी., पैट, विद्या उपासक या एस.एम.सी. टीचर हों, एक ही अध्यापन का कार्य करते हैं। आदरणीय शिक्षा मंत्री जी ने एक ठोस नीति बनाने के लिए जो कहा है, निश्चित रूप से उसका फायदा आने वाले समय में मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर मैं पिछली सरकार की बात करूं, तो शिलाई से हमारे बहुत वरिष्ठ विधायक हैं, मैं उनका बहुत आदर करता हूं। वे कह रहे थे कि हम थोक के व्यापारी हैं। मैं भी मानता हूं कि ये थोक के व्यापारी हैं क्योंकि आज इस बारे में

14/03/2018/1500/RG/YK/2

हमारे कर्नल श्री इन्द्र सिंह जी का एक प्रश्न विधान सभा में लगा था जिसमें उन्होंने पूछा था कि गत् तीन वर्षों के दौरान कितने प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय व महाविद्यालय इस प्रदेश में खोले गए? इसके जवाब में आज कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश में पिछले तीन वर्षों में 93 नए राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 211 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को स्तरोन्नत करके राजकीय मध्यमिक विद्यालय बनाया गया, 354 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को स्तरोन्नत करके राजकीय उच्च विद्यालय बनाया गया, 285 राजकीय उच्च विद्यालयों को वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बनाया गया और 44 नए महाविद्यालय खोले गए। यदि मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करूं, तो वहां इस सरकार ने जाते-जाते पिछले 15 दिनों में दो कॉलेज खोल दिए, आठ सीनियर सैकण्डरी स्कूल, सात हाई स्कूल और 12 मिडिल स्कूल मेरे विधान सभा क्षेत्र में खुले हैं। अच्छी बात है। मैं इनका धन्यवाद करना चाहूंगा। थोक के व्यापारियों ने थोक में स्कूल तो खोल दिए, लेकिन उनमें शिक्षक देना भूल गए। जाते-जाते इन्होंने बिना बजट के, बिना इन्फ्रास्ट्रक्चर के केवल कोरे कागज पर अधिसूचना जारी कर दी और इसके लिए किसी प्रकार के बजट का प्रावधान नहीं किया। स्कूल खोल दिए, फट्टे लगा दिए, लेकिन स्कूलों में आज क्या हालत है? मैं अभी देख रहा था कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में --(घण्टी)---उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो शुरू किया है। तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, डिलमन है

जिसमें एक भी बच्चा नहीं है, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, मोहर में एक भी बच्चा नहीं है और वर्ष 2015 में दोनों स्कूलों का दर्जा बढ़ाया गया था। इसी प्रकार जिला सिरमौर में ही एक मिडिल स्कूल, शिहुबाग है वहां भी एक बच्चा नहीं है, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, झाजड़ में भी एक बच्चा नहीं है। स्कूल तो खोले गए, लेकिन जब इनमें अध्यापकों का प्रावधान ही नहीं किया गया, तो बच्चे यहां आकर क्या करेंगे?

14/03/2018/1505/MS/DC/1

श्री सुरेश कुमार कश्यप जारी----

शिक्षा के क्षेत्र में एक माननीय सदस्य ने थोक की बात कही है। उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि ये थोक के व्यापारी नहीं थे बल्कि थके हुए व्यापारी थे क्योंकि इन्होंने स्कूलों में शिक्षकों की व्यवस्था नहीं की। कितने ही प्राथमिक स्कूल ऐसे हैं जिनमें केवल एक-एक अध्यापक है और बहुत से स्कूल तो ऐसे हैं जिनमें एक भी अध्यापक नहीं है। कई स्कूलों में डैपुटेशन पर अध्यापक हैं। इसके साथ ही कभी अध्यापकों की जनगणना में ड्युटि लग जाती है तो कभी उनको डाक बनाने का काम दे देते हैं और साथ में मिड-डे-मील की भी व्यवस्था करनी होती है। स्कूल में अध्यापक 11.00 बजे आता है और 3.00 बजे चला जाता है। इस तरह से अध्यापक बच्चों को कब पढ़ाएंगे? जब प्राथमिक स्कूलों की यह हालत होगी तो हमारे बच्चों का भविष्य कैसे होगा, आप स्वयं इसका अंदाजा लगा सकते हैं। यानी इन्होंने पूरी तरह से इस प्रदेश में शिक्षा के हाल को बिगाड़ दिया। मैं आदरणीय शिक्षा मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा हालांकि अभी सरकार को बने हुए मात्र दो महीने का ही समय हुआ है और इसको पटरी पर लाने में समय लगेगा लेकिन फिर भी ऐसा प्रयास किया जाए कि शिक्षकों के जो खाली पद पड़े हैं उनको शीघ्रता से भर दिया जाए।

इस बजट में पूर्व सैनिकों की बात भी आई है। मैं भी एक पूर्व सैनिक हूं। हमें जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने वन-रैंक-वन-पैंशन का तोहफा दिया और प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में पूर्व सैनिकों के लिए जो वित्तीय लाभ पूर्व की सरकार ने बन्द कर दिए थे, उनको दुबारा से बहाल किया, यह बहुत ही सराहनीय कदम है। इसके अलावा जो पैरा-मिलिट्री के शहीद हैं पहले उनके परिवारजनों को सरकारी नौकरियों में रोज़गार उपलब्ध नहीं करवाया जाता था लेकिन इस बजट में

उसका प्रावधान किया गया है। मैं इसके लिए आदरणीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहूंगा और उनको बधाई भी देना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष जी, इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। पार्ट टाइम वॉटर कैरियर, मिड-डे मील वर्कर, एस0एम0सी0 टीचर, आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्कर हरेक के मानदेय में वृद्धि की गई है। इसके लिए मैं पुनः मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा।

14/03/2018/1505/MS/DC/2

जैसा मैंने पूर्व में भी कहा कि दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी को भी बढ़ा दिया और कर्मचारियों के लिए 1 जुलाई, 2017 से 4 प्रतिशत अंतरिम राहत की घोषणा की भी गई यानी हरेक वर्ग का ध्यान रखते हुए इस बजट को बनाया गया है। निश्चित रूप से आदरणीय जय राम जी ने जो यह बजट पेश किया है, इससे हिमाचल प्रदेश में हम राम राज्य की स्थापना करने की ओर अग्रसर होंगे। जिस प्रकार से यहां पर एक माननीय सदस्य जो सिरमौर से ही हैं, कह रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री कई बार हिमाचल में आए तो उन्होंने कौन सी घोषणाएं कर दीं? मैं उनको बताना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 69 नेशनल हाइवेज दिए। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी 6 नेशनल हाइवेज बन रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा काम हिमाचल प्रदेश के लिए हुआ है। एक समय ऐसा था जब हिमाचल प्रदेश में मात्र 11 नेशनल हाइवेज हुआ करते थे। आज उनकी संख्या 69 हो गई है। आप देखेंगे आने वाले समय में जब ये नेशनल हाइवेज बन जाएंगे तो किस प्रकार से हमारे प्रदेश का विकास होगा और विकास के नये आयाम स्थापित होंगे।

आज यहां सड़कों की क्या स्थिति है? शायद ही यहां कोई ऐसा सदस्य होगा जो सड़कों को लेकर चिन्तित नहीं होगा। जो भी काम पिछले पांच वर्षों में हुए उनकी टारिंग छः महीने के उपरान्त ही उखड़ गई। मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि क्वालिटी कन्ट्रोल को लेकर उन्होंने मुख्य मंत्री कार्यालय में एक कमेटी का गठन करने का आश्वासन दिया है। मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि इसमें जहां गुणवत्ता की ओर ध्यान दिया जाए वहीं हमारे रि-मैटलिंग और रि-टारिंग के लिए जो मापदण्ड हैं उनमें भी सुधार करने की आवश्यकता है। आज जो मापदण्ड हैं और आज जो हमारी सड़कों की स्थिति है

तथा जिस प्रकार से ट्रैफिक का लोड बढ़ा है, वह आज के समय में व्यवहारिक नहीं है। जो 20 एम0एम0 की रि-मैटलिंग और रि-टारिंग होती है उसको बढ़ाया जाना चाहिए ताकि जो सड़कें रि-टारिंग के बाद अगले तीन महीने में ही खराब हो जाती हैं उस प्रकार की स्थिति पैदा न हो। यह मेरा मुख्य मंत्री जी से आग्रह रहेगा।

उपाध्यक्ष जी, केन्द्र सरकार ने हमें जहां एम्ज दिया वहीं आई0आई0 एम0 की स्थापना हमारे जिला में ही हो रही है। इसके अलावा चम्बा का मेडिकल कॉलेज,

14.03.2018/1510/जेके/एचके/1

श्री सुरेश कुमार कश्यपः-----जारी------

चाहे सिरमौर में नाहन का मैडिकल कॉलेज है, हमीरपुर का मैडिकल कॉलेज है, उसके लिए बजट दिया है। "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना" में करोड़ों रूपए आ रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जिला सिरमौर में 9 योजनाएं "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना" में आई है, जिनमें से 6 मेरे विधान सभा क्षेत्र की हैं, और 8 करोड़ रूपए के लगभग सिंचाई योजनाओं के लिए मिला है। मैं, केन्द्र सरकार का इसके लिए धन्यवाद करना चाहूंगा। शिमला और धर्मशाला को स्मार्ट सिटी बनाया गया। बहुत सारी योजनाएं हैं, केन्द्र की वित्त पोषित योजना जिसमें 90:10 के तहत बजट मिलता है, क्योंकि पूर्व यू0पी0ए0 सरकार ने उसको बन्द कर दिया था, उसको हमारी सरकार ने दोबारा से बहाल किया है। निश्चित रूप से बहुत बड़ा कदम हमारी केन्द्र की सरकार ने हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए उठाया है। कुल मिला करके मेरा कहना यह है कि जो आदरणीय जय राम ठाकुर जी ने इस सदन में बजट पेश किया है, यह बहुत ही विकासोन्मुखी है । निश्चित रूप से हमारा प्रदेश विकास के मामले में आगे है क्योंकि यह अभी पहला बजट है। मात्र दो महीने हमारी सरकार को हुए हैं । इन्होंने हमारे प्रदेश को आने वाले समय के लिए जो दिशा दिखाई है वह और आगे ले जाएगी, ऐसी मुझे पूर्ण आशा है। यहां पर कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे कि आर0एस0एस0 का भय उनको सता रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में आर0एस0एस0 नहीं, भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं। जिस प्रकार से पूर्व के समय में टायर्ड और रिटायर्ड लोग सरकार चला रहे थे।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, मेरा आपसे निवेदन है कि आप वाइंड अप करें।

श्री सुरेश कुमार कश्यपः उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय जय राम ठाकुर जी के नेतृत्व में बहुत ही युवा सरकार हिमाचल प्रदेश में आसीन है और हिमाचल प्रदेश आने वाले समय में विकास की नई बुलन्दियां छुएगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। जो बजट इस सदन में प्रस्तुत किया गया है, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा उनको बहुत बधाई भी देना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

14.03.2018/1510/जेके/एचके/2

उपाध्यक्षः अब इस चर्चा में भाग लेने के लिए मैं श्री बलबीर सिंह वर्मा को आमंत्रित करता हूं।

श्री बलबीर सिंह वर्माः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री, आदरणीय श्री जय राम ठाकुर जी ने माननीय विधान सभा के सभा पटल पर 9 मार्च, 2018 को जो बजट अनुमान पेश किए हैं।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, प्लीज एक मिनट के लिए बैठें। इस तरफ दो ही लोग बोलने के लिए रह गए हैं, पवन काजल जी और सुन्दर सिंह ठाकुर जी हैं। इसमें नन्द लाल जी का नाम नहीं है। आप लिख करके दे दें। वास्तव में इस तरफ दो थे और उस ओर पांच थे। इसमें दो बचे थे। यहां से पांच है। इसीलिए थोड़ा बैलेंस हम बिठा रहे थे। माननीय सदस्य आप बोलें और उसके बाद आप अपने नाम दे दें।

श्री बलवीर सिंह वर्माः उपाध्यक्ष महोदय, 9 मार्च, 2018 को जो बजट अनुमान रखा है, मैं उसका पूरा समर्थन करता हूं और विपक्ष ने जो माननीय मुख्य मंत्री पर टिप्पणी की कि उन्होंने ये जो सफलता प्राप्त की है, ये सफलता किन्हीं और को मिलनी थी और उनको मिली है, परन्तु उन्होंने इसके पीछे यह नहीं देखा कि उनकी नीयत, नीति, मेहनत, ईमानदारी और वफ़ादारी इन सभी चीजों ने उनको उस जगह पर पहुंचाया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने सबका साथ, सबका विकास भावना के साथ यह बजट पेश किया है। इसमें सभी वर्ग जिन्होंने इस धरती पर आना है, नवज़ात शिशु के लिए भी और जिन्होंने इस धरती से जाना है, बुजुर्गों के लिए भी और जो बीच में युवा हैं, उन सभी

वर्ग के लिए इन्होंने ये बजट पेश किया है। यह बहुत ही सराहनीय बजट है। वृद्धावस्था पैंशन इन्होंने 80 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों को उनकी आयु सीमा को बिना किसी आय सीमा के 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष किया और 1 लाख 30 हजार के करीब हिमाचल प्रदेश के बुजुर्ग लोगों को इसका फायदा होने वाला है।

14.03.2018/1515/SS-AG/1

श्री बलबीर सिंह वर्मा क्रमागतः

उपाध्यक्ष महोदय, मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्रीय सरकार ने 28 अक्तूबर, 2015 को निर्णय लिया और सभी पहाड़ी राज्यों के लिए सभी मूल केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में 90:10 अनुपात से जो पैसा मिल रहा है इसमें हिमाचल प्रदेश की बहुत सारी योजनाओं में बहुत ज्यादा बजट आ रहा है। हिमाचल प्रदेश में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 2014 तक कुल 2200 करोड़ के करीब पैसा आया था और 1800 करोड़ के करीब अभी चार साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश को प्रधान मंत्री सड़क योजना में मिला है। मेरे चुनाव क्षेत्र में 45 पंचायतों की सड़कें प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना से बन रही हैं। अगर इस देश के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना न लाते तो आज भी मेरी 45 पंचायतें सड़कों से वंचित होतीं और किसी भी स्टेट में इतना फंड नहीं होता जिसमें कि करोड़ों रुपया सड़कों के लिए लगाया जा सके। मैं इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और पूर्व प्रधान मंत्री, आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का चौपाल की जनता की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। हिमाचल प्रदेश के लिए 69 नेशनल हाईवे आदरणीय मोदी जी की सरकार ने दिए। इस प्रदेश के अंदर उससे पहले सिर्फ चार ही नेशनल हाईवे थे। मैं इस मंच से हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री, जय राम ठाकुर जी का धन्यवाद करता हूं। वह जो 8 डी0पी0आरज़0 बन रही हैं, उसी में हमारे चौपाल क्षेत्र की डी0पी0आर0 बन रही है। उससे हमारे क्षेत्र को बहुत फायदा होने वाला है। कांग्रेस सरकार से कर्मचारियों एवं पैंशनर्ज़ को देय वेतन और पैंशन बकाया की देनदारियां भी वर्तमान सरकार ही दे रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश के अंदर मेरे चुनाव क्षेत्र की एक गुड़िया के साथ बहुत जघन्य अपराध हुआ था, उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने एक गुड़िया हैल्प लाइन भी बनाई और हिमाचल प्रदेश के अंदर ही एक होशियार सिंह हैल्प लाइन भी माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बनाई है, जिससे हिमाचल प्रदेश के अंदर कोई भी

ऐसे जघन्य अपराध नहीं कर सकेगा। वन माफिया, भू-माफिया, शराब माफिया और हर प्रकार के माफिया पर अंकुश लगाने के लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने एक बहुत बड़ी पहल की है। भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की सातवीं अर्थव्यवस्था के रूप में उभरी है।

14.03.2018/1515/SS-AG/2

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने 2018-19 के लिए 6300 करोड़ की वार्षिक योजना तैयार की है जोकि पिछले वर्ष की तुलना में 600 करोड़ रुपये ज्यादा है। इससे बैकवर्ड एरिया सब-प्लान और बहुत सारी योजनाओं को प्रदेश में फायदा मिलने वाला है। इस सरकार ने गौ-सेवा आयोग का गठन किया है। यह बहुत ही काबिले तारीफ है। गौ-सेवा को हमारे राष्ट्र में सबसे बड़ी सेवा के रूप में माना जाता है। इससे हमारी सड़कों में जो बहुत सारे पशु होते हैं उनको किसी एक स्थान पर इकट्ठा करके गौ-सेवा आयोग के गठन से बहुत फायदा होने वाला है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मनरेगा के अन्तर्गत गरीब परिवार के लोग दिहाड़ी करते हैं। सरकार ने इसको 100 दिन से बढ़ाकर 120 दिन किया है यह भी काबिले तारीफ है। स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने के लिए 25 हजार से 40 हजार रुपये की जो राशि बढ़ाई है यह भी काबिले तारीफ है। मुख्य मंत्री आवास योजना में 42 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित है और इसमें सामान्य श्रेणी के बी0पी0एल0 परिवार जोड़े गए हैं यह भी बहुत ही काबिले तारीफ है। 14वें वित्तायोग में जिला परिषद्, पंचायत समिति के लिए 45 करोड़ रुपये का बजट रखा है, यह भी बहुत ही काबिले तारीफ है।

14.03.2018/ 1520/केएस/डीसी/1

श्री बलबीर सिंह वर्मा जारी----

पंचायती राज प्रतिनिधियों का मानदेय भी बढ़ाया है। भारत सरकार ने शिमला को स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत चयनित किया है और धर्मशाला को 2110 करोड़ और शिमला को 2905 करोड़ का अनुमोदन केन्द्र सरकार से प्राप्त हो चुका है। यह भी काबिले तारीफ है।

उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने राज्य की सड़कों के रख-रखाव के लिए हिमाचल प्रदेश को 100 करोड़ की अतिरिक्त राशि रखी है। "मुख्य मंत्री सड़क योजना" के

अंतर्गत गांव और बस्तियों को सड़क से जोड़ने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने 50 करोड़ का बजट रखा है। "मुख्य मंत्री आदर्श विद्या केन्द्र योजना" प्रारम्भ की गई है जो कि बहुत ही काबिले तारीफ है। इसमें 10 आदर्श विद्यालय बनने हैं जिनमें सारी सुविधाएं निशुल्क होंगी । रहने की, खाने की, पढ़ने की निशुल्क सेवा इनमें होगी और ऐसी योजना हिमाचल प्रदेश के अंदर पहली बार हमारे आदरणीय यशस्वी मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी ने चलाई है इसमें दूर-दराज के क्षेत्र में गरीब परिवार के बच्चों को पढ़ने का मौका मिलेगा।

इसी तरह से "अखण्ड शिक्षा ज्योति, मेरे स्कूल से निकले मोती"योजना का शुभारम्भ भी किया गया है। खेल विकास के लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने सभी चुनाव क्षेत्रों में एक मैदान बनें, इसके लिए भी बजट का प्रावधान किया है और इसके लिए हर चुनाव क्षेत्र को 10 लाख रुपये मिलेंगें। वरिष्ठ नागरिक सुविधा केन्द्र भी माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इस प्रदेश में खोलने का प्रस्ताव रखा है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने समाज के सबसे निचले तबके यानि दिहाड़ीदार की दिहाड़ी भी बढ़ाई है । उनको 210 रु0 प्रतिदिन मिलते थे जिसे बढ़ाकर 225 रु0 किया है। "मुख्य मंत्री लोक भवन योजना" आरम्भ की है ओर प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 30 लाख रु0 की लागत से ये बनेंगें। दूर-दराज क्षेत्र के लोग, गरीब लोग शहरों में किसी बैंकट हॉल में शादी नहीं करवा सकते थे, अब हर चुनाव क्षेत्र में 30 लाख रु0 की लागत से

14.03.2018/ 1520/केएस/डीसी/2

एक लोक भवन केन्द्र बनेगा जिसमें सभी वर्ग के लोगों को सुविधा मिलेगी। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने यह भी घोषणा की है कि अगर जरूरत हो तो दो और तीन मुख्य मंत्री लोक भवन भी किसी चुनाव क्षेत्र में खोले जा सकते हैं। विधायक प्राथमिकता में 80 करोड़ से 90 करोड़ बढ़ाया है । अभी हाल ही में जो विधायक प्राथमिकता की मीटिंग हुई थी, उसमें माननीय मुख्य मंत्री ने 10 करोड़ रु0 बढ़ाएं हैं यह भी बहुत ही काबिले तारीफ है।

"जल से कृषि को बल" यह भी नई योजना माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने शुरू की है। इसी तरह से "प्राकृतिक खेती, खुशहाल किसान योजना" भी शुरू हुई है और एंटी हेल नैट के लिए बजट में पहले प्रावधान 2 करोड 27 लाख था अब साढ़े चार गुना बढ़ाकर 10 करोड़ रु0 किया है इससे सभी किसानों और बागवानों को जो आलोवृष्टि से नुक्सान होता था ,उससे बहुत फायदा होने वाला है।

"बागवानी सुरक्षा योजना " के अंतर्गत एंटी-हेलगन लगाने के लिए 60 प्रतिशत उपदान प्रदान करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने पहली बार योजना लाई है यह बहुत प्रशंसनीय है। इसमें सभी क्षेत्र के बागवानों और किसानों को फायदा मिलेगा।

"मुख्य मंत्री खेत संरक्षण योजना" सौर बाड़ को सामुहिक तौर पर लगाने पर 85 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा । इससे किसानों को बहुत फायदा होने वाला है।

"प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना" तथा "मौसम आधारित बीमा योजना "भी बहुत काबिले तारीफ है। हैंड पम्प के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपनी निजी भूमि पर भी हैंड पम्प लगाना चाहता है तो उसके लिए 75 प्रतिशत हिमाचल सरकार देगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा आपको अपने चौपाल चुनाव क्षेत्र के बारे में भी बताना चाहूंगा कि चौपाल चुनाव क्षेत्र में 28 साल बाद सत्ता के साथ का विधायक बना है।

14.3.2018/1525/av/DC/1

श्री बलबीर सिंह वर्मा------- जारी

उससे पहले सरकार कांग्रेस पार्टी की बनती थी और वहां से विधायक निर्दलीय चुनकर आते थे या फिर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती थी तो विधायक वहां से कांग्रेस पार्टी के चुनकर आते थे। वहां पर 28 साल के बाद सत्ता के साथ का विधायक आया है। (---व्यवधान---)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपनी चर्चा जारी रखें। ये लोग आपका टाइम कटवा रहे हैं, आप बोलते रहिए।

श्री बलबीर सिंह वर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, (---व्यवधान---)

उपाध्यक्ष : माननीय मुकेश जी और मेरा सभी सम्माननीय सदस्यों से निवेदन है कि अभी लगभग 7 लोगों को बोलना है इसलिए बीच में व्यवधान न डालें। (---व्यवधान---) माननीय सदस्य, आप अपनी बात जारी रखें।

श्री बलबीर सिंह वर्मा : उपाध्यक्ष जी, आदरणीय मुकेश जी यह तो बोल रहे हैं कि आज यू0पी0 से बी0जे0पी0 तीनों सीटें हार गई मगर यह नहीं बोल रहे हैं कि पूरे देश से कांग्रेस का सफाया भी हो रहा है।

उपाध्यक्ष : आप हिमाचल को देखो, हम केवल हिमाचल को देखते हैं।

श्री बलबीर सिंह वर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र में 28 किलोमीटर फोरैस्ट एरिया में बिजली की लाइन जाती है। वहां 66 के0वी0ए0 जिसका फाउंडेशन स्टोन वर्ष 2007 में रखा गया था उसका काम प्रगति पर है लेकिन जिस तरह से उसमें प्रगति होनी चाहिए थी वह पिछले पांच साल के कार्यकाल में नहीं हुई। इसके अतिरिक्त नेरवा में 22 के0वी0ए0, कुपवी में 33 के0वी0ए0 का भी काम चला हुआ है। मेरे चौपाल में कालेज की बिल्डिंग बनना बहुत ही अनिवार्य है। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में मेरी बहुत सारी ऐसी उठाऊ सिंचाई योजनाएं हैं जिनका काम 10-15 साल पहले शुरू हुआ था लेकिन वह अभी तक पूर्ण नहीं हुई है।

14.3.2018/1525/av/DC/2

मैं उसके लिए भी आग्रह करूंगा कि इनको कम्पलीट करने के लिए बजट का प्रावधान किया जाए। नेरवा सिविल होस्पिटल की बिल्डिंग अण्डर कनस्ट्रक्शन है। मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि मेरे चुनाव क्षेत्र में किसी भी होस्पिटल की बिल्डिंग सही तरीके से नहीं

बनी हुई थी। सारी पुरानी और 2-2, 3-3, 4-4 कमरों में होस्पिटल बने हुए थे। नेरवा होस्पिटल की बिल्डिंग बन रही है और चौपाल होस्पिटल की भी बन रही है तथा कुपवी के होस्पिटल के लिए हाल ही में टैंडर लगा है। पी0एच0सी0 जिन्हा, नौरा-बौरा, गुमा, देवत, बासाधार, पुलवाल इत्यादि पी0एच0सीज0 की बिल्डिंग्ज का भी निर्माण होना है। नेरवा में बस अड्डे के लिए स्थान का चयन भी हो गया है लेकिन उसके लिए बजट का प्रावधान होना है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि नेरवा के बस अड्डे के लिए बजट का प्रावधान होना बहुत जरूरी है। कुपवी में ब्लॉक के लिए जो भी औपचारिकताएं बची हैं वह भी पूरी होनी चाहिए ताकि कुपवी का ब्लॉक सुचारु रूप से चले। कुपवी में कालेज होना बहुत जरूरी है। पिछले कांग्रेस पार्टी की सरकार के कार्यकाल में बहुत सारे क्षेत्रों में ऐसे कालेज खुले हैं जहां जरुरत नहीं थी और जहां बच्चों की संख्या भी बहुत कम थी। मेरे कुपवी क्षेत्र में 14 पंचायतें हैं और 14 पंचायतों में से 12 पंचायतें बैकवर्ड हैं। नेरवा से कुपवी के लिए 72 किलोमीटर की दूरी है। अगर किसी को कालेज पढ़ने जाना हो तो 72 किलोमीटर की दूरी तय करके जाना पड़ता है। इसलिए कुपवी में कालेज होना बहुत जरूरी है क्योंकि कुपवी आज की डेट में हिमाचल प्रदेश में सबसे दूर-दराज व बैकवर्ड क्षेत्र में भी आता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आने वाले समय में कुपवी में कालेज होना बहुत ही जरूरी है। चौपाल में बहुत सारे स्कूल की बिल्डिंग्ज बननी चाहिए। स्कूल बिल्डिंग और इनफ्रास्ट्रक्चर की वहां पर बहुत ही दयनीय स्थिति है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो बजट पेश किया है यह बहुत ही काबिलेतारीफ है। यह हिमाचल प्रदेश के इतिहास में लिखा जायेगा कि वर्ष 2018 में आदरणीय श्री जय राम ठाकुर जी ने एक ऐसा बजट पेश किया था जिससे हिमाचल प्रदेश को एक नई दिशा मिली है और हिमाचल प्रदेश

14.3.2018/1525/av/DC/3

में बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों को छुआ है जो कि दूर-दराज के क्षेत्र हैं। जहां पर बहुत सारा विकास होना है और विकास की दृष्टि से इन्होंने कोई भी क्षेत्र/वर्ग नहीं छोड़ा है इसलिए मैं

इस बजट का पुरजोर समर्थन करता हूं और आदरणीय जय राम ठाकुर जी को आगे के लिए शुभकामनाएं देता हूं कि ये चार बार हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री बनें और हिमाचल प्रदेश की सेवा इसी तरह करते रहें। धन्यवाद।

14.3.2018/1530/TCV/HK-1

उपाध्यक्षः अब माननीय सदस्य श्री नन्द लाल जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री नन्द लालः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 2018-19 का बजट अनुमान इस माननीय सदन में रखा है और उस पर जो चर्चा हो रही है, मैं भी उसमें अपने आप को शामिल करता हूं। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय यहां नहीं है, मैं सबसे पहले उनको मुबारकबाद देना चाहूंगा। अच्छा होता वे यहां होते।

अध्यक्ष महोदय, काफी इलैबोरेट, 94 पेजों की स्पीच, उन्होंने पौने तीन घण्टे में यहां पड़ी, लेकिन उसमें कुछ नया नहीं लगा। उसमें पिछली वर्ष के जो बजट अनुमान थे almost on the same lines, सिर्फ फिगर्ज़ को नीचे-ऊपर करके थोड़ा डायरैक्शन चेंज किया गया I would say it jugglery of figures. उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई रोड़मैप नहीं था। लोगों ने इसकी काफी तारीफ की और बताया कि हॉर्टिकल्चर/एग्रीकल्चर में क्या होना है, 10 रुपये से 200 रुपये तक लोगों की तनख्वाहें बढ़ाई तो just to satisfy everybody, इस तरह की कोशिश की गई है। इस बजट में सबसे कमी रिसोर्स जनरेशन की पाई गई है। state like Himachal having quite meager resources and cannot function at its own. आपको केन्द्र सरकार से फाईनेंशियल असिस्टेंस लेनी ही पड़ेगी। यहां पर जैसे ही सरकार Form हुई, उसके बाद दो फैसलें लिए गये। पहला, ओल्ड एज़ पैंशन को 80 से 70 साल किया गया। यह एक बहुत अच्छा फैसला था। हम इनका धन्यवाद करना चाहेंगे।

ओल्ड एज़ पैंशन के लिए पूर्व माननीय मुख्य मंत्री राजा साहब का धन्यवाद करना होगा He started this. ---(व्यवधान)--- सुन लीजिए। If you have any query, you can ask me later. I am talking about Old Age Pension of 80 years.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा फैसला लिया गया, सरकारी कर्मचारियों को 3 परसेंट डी0ए0 दिया गया। वह भी अच्छी बात थी But it's an obligatory. उसमें हमको ज्यादा कुछ नहीं करना है, ज्यादा कुछ नहीं कहना है। मैंने जिस तरह से रिसोर्स जनरेशन की बात की है, उसी

14.3.2018/1530/TCV/HK-2

तरह से हिमाचल प्रदेश के अंदर बेरोज़गारों की भी एक बहुत बड़ी फौज हैं। उसके लिए there has to be some concrete policy. इस बजट अनुमान में कोई ऐसी कांक्रीट पॉलिसी का जिक्र नहीं है कि हमारे जो बेरोज़गार नौजवान है, इनके लिए कोई नीति बनायें। ताकि इनको रोज़गार के मौके मिल सकें। इन्होंने नई योजनाओं के नाम बहुत बदले हैं। Name is almost 28. इन्होंने 28 योजनायें नई चलाई हैं। उसमें भी कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है, जिससे कोई एम्पैक्ट होने वाला है। इस बज़ट में मंहगाई का कोई जिक्र नहीं है। ऐसा लगाता है कि बड़ा हर्डली इस बज़ट को तैयार किया गया है और माननीय मुख्य मंत्री महोदय को इस बजट को पढ़ना पड़ा। seriousness on the part of the democracy. ये आप देख ही रहे हैं कि बजट अनुमान पर चर्चा हो रही है and officials concerned to be here कल दोपहर को भी नहीं थे और आज भी नहीं है। you can imagine the seriousness of the subject.

14-03-2018/1535/NS/HK/1

श्री नंद लाल -----जारी।

उपाध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि Budget is a statement of Receipts and expenditure. अब इसमें देखना क्या होता है? As Finance Minister he has to see हमारे पास राजस्व प्राप्तियां कितनी हैं और उस पर एक्सपैंडीचर कितना है? As I said earlier कि हमें केंद्र सरकार पर निर्भर रहना ही पड़ता है। हमारे पास लिमिटिड रिसोर्सिज़ हैं। हमारे पास राजस्व प्राप्तियां कम हैं और एक्सपैंडीचर ज्यादा है। You cannot stop the development activities in a state because you don't have the funds. यह बात नहीं है। इसलिए हमें उन पर डिपैंड रहना ही पड़ता है।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर बड़ी चर्चा हो रही है कि लोन लिया गया और दिया गया तथा हमें लोन वाली सरकार मिली है। इसकी बड़ी पब्लिसिटी हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सी सरकार ऐसी है जिसने अपने बज़ट में डिवैल्पमैंट एक्टिविटीज़ के लिए या दूसरे काम के लिए लोन न लिया हो? ऐसा नहीं हो सकता है। हमारे जैसी स्टेट के लिए लोन लेना बड़ा लाज़मी है। उपाध्यक्ष महोदय, लोन का ऐसी भी नहीं है कि वहां से कोई खैरात बंट रही है और हम ले रहे हैं। सबसिडी और लोन या और दूसरी जो भी चीज़ें हैं there is kitty टैक्स ज़मा करने के बाद इसका सैंटर एंड स्टेट शेयर बनता है और जो शेयर बनता है, उसमें हम भी अपना शेयर लेते हैं। It is a legitimate right of a state. इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई खैरात बंट रही है। उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर चर्चा हो रही है कि एन0डी0ए0 की सरकार के समय में 90:10 की रेशो external aided projects की थी और उसमें मिला। मैं यह कहना चाहूंगा कि यू0पी0ए0 सरकार के समय में कम था। यह 14वें वित्तायोग की सिफारिश थी। जो यह डिस्पैरिटी है जैसे सर्व शिक्षा अभियान या दूसरे जितने भी external aided projects थे, उसमें 50:50 और 60:40 तथा 30:70 का इस तरह के शेयर थे। 14वें वित्तायोग की सिफारिश पर यह 90:10 का शेयर फिक्स हुआ है। यह भी कोई अहसान नहीं है। It is a recommendation of the Commission. यह जो formula है It is not only for Himachal, it is for all the hilly States.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब external aided projects के बारे में बात करना चाहूंगा। यह प्रोजेक्ट्स हमारे पास बहुत बड़ा रिलीफ हैं। इसमें पैसों का एक अच्छा volume आता है और जिस-जिस मद के लिए वह जाना है, उससे अच्छा काम होता है। माननीय मुख्य मंत्री

14-03-2018/1535/NS/HK/2

महोदय, आप अगर इसके अलावा कुछ इस तरह का स्पैशल पैकेज़ इस प्रदेश में लाते हैं और यह प्रदेश की डिवैल्पमैंट में लगता है तो हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे। पूरा प्रदेश आपका धन्यवाद करेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं लोन की बात कर रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि वर्ष 2007-12 में भाजपा सरकार के पूर्व मुख्य मंत्री प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी ने 27,598 करोड़ रुपये का लोन लिया था। उसके बाद ये बढ़ता गया और आज आप जिसका ज़िक्र कर रहे हैं, वह भी ऐसा लोन नहीं है कि गलत तरीके से लिया हो। there are certain norms. इसके भी नार्म्ज़ होते हैं और उसके हिसाब से आपको लोन मिलता है। अगर लोन

लिया है तो विकास में लगाया गया है। जैसे अभी माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अपने बज़ट भाषण में मंजूर किया है It would be backed with the borrowings. इसको हम भी लोन, debt और सबसिडी से लेंगे तथा जो भी करना होगा वह इस तरह से किया जायेगा। मैं यहां पर external aided projects पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा। हम यू0पी0ए0 सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। There are certain schemes. जैसे आपकी मनरेगा, सर्व शिक्ष अभियान और मिड डे मील योजनायें हैं these are the schemes started by UPA Government. आज माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने मनरेगा में 100 दिन के रोज़गार को 120 दिन का कर दिया है। हम इसके लिए इनका धन्यवाद करते हैं। But it is not simply a scheme, it's an Act. यह एक एक्ट है।

उपाध्यक्ष महोदय आप मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करने का समय देंगे।

14.03.2018/1540/RKS/YK-1

श्री नंद लाल... जारी

इस एक्ट के अंदर यदि आपको 115 दिनों के अंदर काम करने के लिए जॉब कार्ड नहीं मिलता है तो आपको एक unemployment allowance at the rate of 50% घर बैठे मिलेगा। अगर मनरेगा के तहत 3 किलोमीटर से बाहर आप काम करने के लिए जाते हैं तो 10% extra allowance will be given. अगर 4 महिलाएं बच्चों वाली हैं और वे काम करने के लिए जाती है तो पांचवीं महिला को she would be paid for वह बच्चों को देखने के लिए वहां पर है। See the scam UPA has given you. शिक्षा के मामले में भी मैं कहना चाहूंगा। क्या हम इन्फ्रास्ट्रक्चर्ज़ डिवैलप नहीं कर सकते हैं? You know, crores of rupees being pumped into the State.

इसी तरह से मिड-डे-मील स्कीम it was a unique scheme. . बारह के लोगों ने भी इसकी तारीफ की है। उन्होंने कहा कि (...व्यवधान...) आपको इसके बारे में हम बताएंगे। इस तरह external aided projects में हमें बहुत फायदा मिला। करीब 15,320 करोड़ रुपये का इसमें आउट ले है। दो और external aided projects आ रहे हैं। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह रहेगा कि इनको भी जल्द-से-जल्द इम्प्लिमैंट किया जाए। राजा

वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में जो पूर्व सरकार थी और यह जो लोन पाइल अप हुआ है see the kind of the development that State has a seen कितने सारे सब-डिवीजन बने। कितनी सारी सब-तहसीलें बनी। उसमें भी तो पैसा लगेगा। पी.डब्ल्यू.डी., आई.पी.एच. इनके अंदर कई डिवीजन बने उनमें भी पैसा लगता है। अगर आप शिक्षा की बात करें, शिक्षा में आप देखेंगे कितने सारे डिग्री कॉलेज बने। 44 डिग्री कॉलेजिज बने than number of schools been upgraded, number of the new schools been opened. इस तरह से जो शिक्षा का मामला है Education was the focus of the Government. मैं आपको कहूं when you talk about Right to Education जब Right to Education की बात करते हैं तो मुझे हक है, यदि मैं कहीं दूर-दराज गांव में रहता हूं तो हमें वहां पर पढ़ने के लिए स्कूल तो चाहिए। माननीय पूर्व मुख्य मंत्री जी की यह सोच रही है और हमें दूर-दराज के एरिया में भी स्कूल, कॉलेज उपलब्ध हुए। जैसे माननीय सदस्य हर्षवर्धन चौहान जी कह रहे थे कि उनके क्षेत्र के कॉलेजों में ज्यादातर लड़कियां पढ़ती हैं। जिन्हें हम पढ़ने के लिए बाहर नहीं भेज सकते थे। अब वे घर से ग्रेजुएट होकर निकल रही है। अब आप कहते हैं कि स्कूलों में अध्यापक नहीं है।

14.03.2018/1540/RKS/YK-2

आज तो खैर आप यह बोलेंगे क्योंकि अभी अढाई महीने की सरकार है। 5 महीने या 6 महीने के बाद this won't be the reply with them. स्कूल में टीचर क्यों नहीं होते with the expansion of institutions definitely कमियां आएंगी तो इसकी जो भर्ती प्रक्रिया है, यह एक निरंतर प्रोसैस है। यह लगातार विभागों में होती रहती है। 100 में से 100 टीचर you will not be get किसी भी स्टॉफ में 100 में से 100 आदमी नहीं मिलेंगे। अगर आपको 100 में से 100 आदमी मिल गए होते तो आपको मंत्री नहीं बनाना चाहिए था। इतने बड़े-बड़े मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाने की जरूरत नहीं थी। One simple clerk can do it. सौ आदमी उनकी ट्रांसफर करना, सैलरी बनाना this can be done by a simple clerk. इस तरह की कमी रहेगी, जब इस तरह के संस्थान बनेंगे। मैं आपको यह भी बताउंगा कि in your previous regime 157 schools were closed. रेशनेलाइजेशन के नाम पर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। जब हमारा शिक्षा का अधिकार है तो हमें स्कूल बंद नहीं करना चाहिए बल्कि चालू रखना चाहिए। हमें यह कोशिश करना चाहिए कि स्कूल के

लिए टीचर, इन्फ्रास्ट्रक्चर्ज़ की व्यवस्था की जाए। इसी तरह आप मैडिकल संस्थानों की बात कर रहे हैं। We have been graded-A.

हिमाचल प्रदेश हैल्थ सैक्टर में भी नम्बर वन है। प्राइमरी हैल्थ सैंटर भी सैंकड़ों में हैं। सी.एच.सी. 91, एच.एस.सी. 2088 हैं। मैडिकल कॉलेज नाहन, चम्बा और कहां-कहां नहीं है। 16 ESI's हैं। मुझे इसमें यह कहना है कि जैसे डॉक्टर्ज, नर्सिज़ की भर्ती हो रही है, वे सारी फिलअप हो जाएगी। We cannot deprive a particular sector, section of people in a remote area from the medical facilities.

14.03.2018/1545/बी0एस0/वाई0के-1

श्री नन्द लाल......... जारी

अगर गांव में किसी दूर-दराज के एरिया में हैल्थ सब सेंटर बनता है तो पोलियो ड्रॉप्स पिलाना वहां आसान हो जाएगा। अगर छोटी-मोटी बीमारी किसी को हो जाती है तो वहां 5-6 बिस्तरों वाली पी0एच0सी0 की व्यवस्था है तो उससे लोगों को सुविधा ही होगी, उन्हें खोलने से क्या नुकसान होगा? यह कहना कि हमारे यहां तो मैडिकल कालेज खोल दिया, हैल्थ सब सैंटर खोल दिए और पी.एच.सी. खोज दी, क्या यह गलत काम है? इसकी प्रशंसा होनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए जो वहां deficiency है, स्टाफ की कमी है वहां पर infrastructure की कमी है उसको पूरा करें in phased manner. हम यह नहीं कहते कि आप तीन महीने में पूरा कर लो। यह कार्य लगातार चलता है और systematic तरीके से होता है। इसी तरह से इस बजट में Budget expenditure is 41,440 crores. इसमें बजट बुक में डिटेल भी दी है। सैलरी, पेंशन, पेमैंटस, लोन पेमैंटस, अन्य पेमैंटस और मेटेंनस सब निकाल कर आपके पास 136531 करोड़ रुपये बचता है। तो इसको आप पूरा करने के लिए आपको लोन लेना पड़ेगा। कहीं ऐसा न हो इस डर के मारे आप कहीं लोन लेना बंद कर दो और विकास कार्य बंद नहो जाएं। वैसे तो अभी सरकार ने मुझे लगता है, दो महीने में एक हजार करोड़ का लोन लिया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट भाषण में दो-तीन जगह इसमें कुछ ऐसा लिखा है कि पूरे बजट को ही सख्त कर दिया है।

सख्त इसलिए किया है, if you see the Para-9 of Page 6 'the lack of prudence exhibited by the Government in managing the fiscal affairs'. यह जिक्र नहीं होता, यह कैसे हुआ। The other one is Para-5 or Page 3 'reckless unproductive expenditure without raising State Government resources'. मैं आपको बताऊं लास्ट ईयर का जो बजट अनुमान था उसमें जो resource generation की बात की fiscal deficit को ऊपर उठाने की बात की उसमें बहुत स्पष्ट कहा गया था। हम आपको बताएंगे यह जो fiscal deficit है यह जो हमारी जी.डी.पी. ग्रोथ है इसमें कई कारण है लेकिन सरकार ने उसे आगे किया। जो बजट बुक के अंदर भाषा इस्तेमाल की है वह इतनी हार्श है, अच्छा होता हमारे जो अधिकारी वर्ग है, ब्यूरोक्रेटस हैं उसको थोड़ा अच्छी भाषा में लिखते तो

14.03.2018/1545/बी0एस0/वाई0के-2

सुनने में भी अच्छा लगता।. अध्यक्ष महोदय, जैसा मैने कहा हम रिसोर्सिज जनरेशन के लिए agriculture production, industrial production and manufacturing sector इन तीन सैक्टरों को मजबूत करना है। इसके लिए जो बेस्ट पोसिबल है सरकार को कार्य करना चाहिए।

इसके अलावा एग्रिकल्चर सैक्टर एक बहुत बड़ा सैक्टर है । इस सैक्टर के अंदर 10 प्रतिशत टोटल जी.एस.डी.पी. comes from allied sector. इसी तरह से डायरेक्ट एम्पलायमैंट लेता है about 60% of the total workers in the State. इन सैक्टर्स में भी कोई अच्छी पालिसी लाएं। आपने कोशिश की है इसे अच्छा बनाने की। एग्रीकल्चर सैक्टर में मुझे इतना ही कहना है कि हमारे भी वहां सब्जी मण्डी का काम होना है। मुख्य मंत्री महोदय से आग्रह रहेगा कि वहां सब्जी मण्डी की सख्त जरूरत है उसकी ओर ध्यान दें। हल्की सी बात मैं और कहना चाहता हूं horticulture के बारे में बहुत जिक्र किया माननीय सदस्य श्री बलबीर जी ने और माननीय ब्रागटा जी ने भी इसका जिक्र किया। एंटी हेल गन के बारे में थोड़ा सा कहना चाहूंगा। आपने अच्छा किया कि एंटी हेल नेट पर आपने

सबसिडी को बढ़ाया। माननीय पूर्व मुख्य मंत्री जी ने भी उसको बढ़ाया था। एंटी हेल नेट जो है what I understand is a obsolete machine.

14.3.2018/1550/DT/AG-1

श्री नन्द लाल.... जारी

यह एक अम्बरेला इम्पेक्ट करती है within the radius of the five Kilometers. उसके बाहर क्या होगा? When you trigger it उसके बाहर की जो प्रोब्लम है They have already faced. People have already faced it in 2016. For God sake इसको अच्छी तरह से स्टडी किया जाये। इस फैक्टर को थोड़ा-सा समझा जाये। कुछ लोग इसको लगा भी रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह ऑप्सयूट मशीन है, इसको इस्तेमाल न किया जाये। इसको अच्छी तरह स्टडी किया जाये, इसका जो टैक्निकल ऐस्पैक्ट है, उसको समझा जाये। तभी इस पर गौर किया जाये। जहां तक नेट्स का सवाल है, Nets are available. Nets are the best. हेल से बचाने के लिए नेट का कोई मुकाबला नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पर्यटन के बारे में एक और बात करनी है। रोपवे ट्रॉली का जिक्र किया गया है। इस बजट के अंदर दो रोपवे ट्रॉलीज़ लगनी है। अगर आप पिछली साल का बजट अनुमान देखेंगे there is mention of five ropeway trolleys. जिसमें हमारा रामपुर की बशरकंड़ा-सराहन ट्रॉली का जिक्र भी था। माननीय मुख्य मंत्री महोदय से मेरा आग्रह रहेगा कि उसको भी इसमें इन्क्ल्यूड किया जाये। बशरकंडा-सराहन एक ऐसी जगह है when you reach on the top, for miles together it is a straight patch. इसको एक्सप्लोअर करने के लिए पूर्व मुख्य मंत्री ने इसको स्कीम में भी डाला था। मेरा आग्रह रहेगा कि इस बार इस रोपवे ट्रॉली का काम शुरू किया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात और कहनी है, जहां तक राशन की बात है, इस बजट बुक में मैंशन किया हुआ है कि तीन दाले, दूध, तेल, नमक आटा इत्यादि मिलेगा। There is a State subsidy scheme started in 2006. उसमें इस वक्त 220 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, ये माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बताया है। मैं इनको धन्यवाद दूंगा। लेकिन पिछले साल

के बजट में भी 220 करोड़ रुपये की एलोकेशन थी। I don't know. You know. इसमें कोई प्राईस राईज़ भी होगा, कुछ और भी सोचना पड़ेगा, कहीं ये राशि कम तो नहीं पड़ जायेगी?

14.3.2018/1550/DT/AG-2

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं एक आखिरी बात कहना चाहूंगा। ये जो 61 then 69 का बड़ा जिक्र हो रहा है। What I stand correctly कि इसकी डी0पी0आर0 बनाने के लिए when the case was sent to the Centre इसकी डी0पी0आर0 के लिए जो सैंक्शन बननी थी। think that was approximately Rs. 227/- which you never received. अब यह आ गया है, हम 2016 से इस एन0एच0 के बारे में सुन रहे हैं। अब जैसा आप बता रहे कि हम इसके लिए कंसल्टैंट अप्वाईंट कर रहे हैं और जल्दी ही इसको बनाया जा रहा है। हमारा आग्रह रहेगा कि इससे बड़ा फ़ायदा होने वाला है। ये जो नेशनल हाईवे का इश्यू है, इस पर ध्यान दिया जाये। इसमें जो कंसल्टैंट अप्वाईंट करना है, डी0पी0आर0 बननी है, इसका काम चालू करना है। इसका काम को थोड़ा स्पीडअप किया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मजबूर हूं कि इस बजट का समर्थन कर पाऊं because there is nothing new in it तो मैं इस बजट का समर्थन नहीं कर सकता। आपने मुझे समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

14.3.2018/1550/DT/AG-3

श्री सुन्दर सिंह ठाकुरः उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रतिष्ठित सदन में बोलने के लिए मैं पहली बार खड़ा हुआ हूं, ये मेरे लिए गौरव की बात है। सरकार को बने अभी दो माह ही हुए हैं। मैं इसी दौरान हुई बातों के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। मैं अगली-पिछली बातों पर नहीं जाऊंगा। हम इस सदन में नये आये हैं। यहां पर आकर एक नया अनुभव महसूस करना है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अपना पहला बजट रखा है। इस बार बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला है और युग परिवर्तन हुआ है। हमारे

अधिकतर विधायक पहली बार इस सदन में चुनकर आये हैं। मैं उन्हें भी बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि

14.03.2018/1555/SLS-AG-1

श्री सुन्दर सिंह ठाकुर... जारी

एक तिहाई नए लोग भी यहां पर आए हैं। जैसे पहले भी चर्चा हुई है कि जैसे हमारे मुख्य मंत्री बने हैं उसमें जो नए विधायक चुनकर आए हैं उनका और कुछ पुराने चेहरों का भी योगदान है। जो कुछ ऐसे घटनाक्रम बने, इसमें दोनों राणा जी का भी योगदान है और होशयार सिंह जी का भी योगदान है। कुछ मंत्रियों को हमारा भी योगदान मानना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से एक बात पूछना चाहूंगा। पिछले दो महीनों के अंदर ऐसी क्या मज़बूरी थी कि जब पहली ही मंत्रिमंडल की बैठक होती है, उस बैठक के लिए जो पहला मुद्दा लगता है वह रघुनाथ ट्रस्ट को समाप्त करने का मुद्दा होता है। एक ओर सुशासन की बात की जा रही है, एक तरफ यह बात की जा रही है कि इस प्रदेश में राम राज्य लाएंगे और दूसरी ओर यह मुद्दा लिया जाता है। पूर्व की सरकार में यह कोई 6 महीने के अंदर का फ़ैसला नहीं था, बल्कि 26 जुलाई 2016 से जब रघुनाथ मंदिर में बार-बार चोरियां होती रहीं, कई तरह के घटनाक्रम होते रहे, उनके दृष्टिगत पूर्व मुख्य मंत्री जी ने एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाया था कि उसे ट्रस्ट के अंडर लिया जाए और उसकी सुरक्षा तथा हिसाब-किताब का लेखा-जोखा रखा जाए। इस फ़ैसले को चुनौती दी गई। जो उसमें अपने आपको प्रभावित मानते थे, जो उस बात से सहमत नहीं थे, उन्होंने हाई कोर्ट में इस बात को चुनौती दी और हाई कोर्ट ने 31 अगस्त, 2017 को एक फ़ैसला दिया जिसमें उस अधिग्रहण को सही ठहराया। सरकार जो एक ट्रस्ट लेकर आई थी उसे हाईकोर्ट ने सही ठहराया। उसके बाद उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, यह नई सरकार बनी है। इसके सामने और भी कई मुद्दे थे which needed to be addressed. There were so many other issues but why this one. What was the pressure? हम सरकार से यह पूछना चाहते हैं कि माननीय हाई कोर्ट से जो आदेश हुए हैं क्या यह उसकी अवहेलना नहीं है, क्या यह कोर्ट के आदेशों की अवमानना नहीं है? मैं

अभी चर्चा सुन रहा था। बार-बार कहा जा रहा है कि हम माननीय हाई कोर्ट के आदेशों का सम्मान करते हैं, लेकिन क्या यह हाई कोर्ट की अवमानना नहीं है? ऐसी क्या अरजैंसी थी जबकि पहली बैठक के लिए और कई महत्वपूर्ण मामले थे? मुझे लगता है कि इसके पीछ कुछ ऐसे संगठन हैं जो कि उस परंपरा से जो बापू आशा राम या बाबा राम रहीम ने शुरू की है, हिमाचल में भी देवी-देवताओं के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं। इसमें

14.03.2018/1555/SLS-AG-2

उनको संरक्षण देने की बात हुई है। मैं तो एक ही बात कहूंगा कि जहां उच्च न्यायालय ने इस बात को नकारा है वहीं जनता ने भी इस बात को नकारा है। आज उसी बात का नतीजा है कि यहां पर बदलाव हुआ है। जनता ने भी उस बात पर मोहर लगाई है। लेकिन जल्दबाज़ी क्या थी? मैं कहना चाहूंगा कि जो इस तरह की विचारधारा है; हिमाचल में भी बाबा आशा राम और बाबा राम रहीम की विचारधारा को लाकर हिमाचल में भी देवनीति को राजनीति के साथ मिलाया जा रहा है।

इसके बाद एक प्रावधान और हुआ है। आपने कहा कि चढ़ावे के रूप में जो राशि आएगी उसमें से 15 प्रतिशत गौसदनों में लगाई जाएगी। ऐसे फंड को क्या वहां पर उस संस्थान में आपने फिर से लूट की छूट दे दी? वहां तो यह बात है कि 'न खाता न बही, जो बाप बेटा कहे वही सही'। बेटे को कारदार बनाया गया। वहां पर यह भी जांच का विषय है कि बैकडेट में ऐसा कैसे किया गया। कभी भी राज परिवार से कारदार नहीं होता था। पिछले दिनों में यह हुआ है और हम इस मामले को लेकर आगे भी लड़ाई लड़ते रहेंगे। जनता के बीच में हम गए हैं और हमने जनता के बीच की लड़ाई जीती है। इसलिए कृपा करके जगह-जगह नाटी डालने वाले ऐसे लोगों को, ऐसे बाबाओं को हिमाचल में संरक्षण देना बंद कीजिए। मैं आपके माध्यम से सरकार को यह बात कहना चाहूंगा।

14/03/2018/1600/RG/DC/1

श्री सुन्दर सिंह ठाकुर-----जारी

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुरोध करुंगा क्योंकि एक माननीय मंत्री जी मेरे जिले से हैं। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। हम और आप नौजवान हैं। हम 21वीं सदी की ओर बढ़ रहे हैं। एक ऐसी विचारधारा जो हिमाचल के लोगों को 18वीं सदी की ओर ले जाना चाहती है, हमें ऐसे लोगों को संरक्षण नहीं देना चाहिए। मैं पूर्व मुख्य मंत्री माननीय श्री वीरभद्र सिंह जी का स्वागत करता हूं जिन्होंने स्वयं अपने भीमाकाली मंदिर को ट्रस्ट के हवाले कर दिया है और आज वहां बहुत अच्छा संचालन चल रहा है। कुल्लू में बावजूद इसके कि बार-बार चोरियां हुईं, कोई हिसाब, कोई बही-खाता और कोई लेखा-जोखा वहां नहीं है। आज अगर आपने सारे ट्रस्ट खत्म करने हैं, तो पूरे हिमाचल में ट्रस्ट खत्म कर दीजिए। कुल्लू में ही क्यों?

उपाध्यक्ष महोदय, अभी यहां पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी बैठे थे। --(व्यवधान)---मैं एक बात कहना चाहूंगा और अपने पिछले महीनों की बात करना चाहूंगा। ---(व्यवधान)----

उपाध्यक्ष : कृपया बीच में व्यवधान न करें।

श्री सुन्दर सिंह ठाकुर : उपाध्यक्ष महोदय, आपने यहां मैडिकल कॉलेज की बात कही। पूर्व की कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों को भी अपने साथ जोड़ दिया, अच्छी बात है। क्योंकि आपने उनको आगे बढ़ाना था। मैं तो आगे की सोच के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। यह मेरा सौभाग्य है कि हम सारे नौजवान पीढ़ी के लोग यहां आए हैं जहां हमारे पास एक लिविंग लेजन्ड की तरह आदरणीय पूर्व मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी हैं। वैसे यहां नौजवान की भी टीम आई है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सुशासन को लेकर एक बात कहूंगा कि यहां अभी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे थे और इस समय हमारे माननीय वन मंत्री श्री गोविन्द सिंह ठाकुर जी यहां बैठे हैं। मैं यहां एक ही आदेश आपसे कुल्लू अस्पताल के लिए चाहता हूं कि वहां पिछले चार महीनों से एक भी प्रसूती विशेषज्ञ नहीं है। मैं पिछले चार महीनों की बात कर रहा हूं, उससे पहले की बात नहीं कर रहा हूं। यदि आप सुशासन देना चाहते हैं, तो अगले दो-चार दिनों में कृपा करके कुल्लू में प्रसूती विशेषज्ञ अवश्य उपलब्ध करवाएं। वहां त्राहि-त्राहि मची है। श्री मार्कण्डा जी भी मेरी बात की ओर ध्यान देंगे। क्योंकि वहां लाहौल के

14/03/2018/1600/RG/DC/2

लोग भी बहुत हैं। श्री जवाहर ठाकुर जी भी मेरी बात से सहमत होंगे और माननीय मुख्य मंत्री जी तो हमारा सहयोग करेंगे ही। क्योंकि उनका कम-से-कम एक-तिहाई विधान सभा का क्षेत्र कुल्लू के लिए जाता है। अब तो मंत्री महोदय ने थाची के लिए बस भी लगा दी है और वहां से सीधे बहुत से लोग कुल्लू आना चाहते हैं। इसलिए मेहरबानी करके तुरन्त वहां किसी प्रसूति विशेषज्ञ को लगाइए। मैं आपका सहयोग एक और बात के लिए भी चाहता हूं। मुख्य मंत्री से लेकर, मंत्री से लेकर हमारे विधायकगण तक ने सभी जिलों में मैडिकल कॉलेज की बात कही। लेकिन ऐसी क्या बात है कि कुल्लू जिले में अभी तक कोई मैडिकल कॉलेज की बात नहीं कही गई। कुल्लू जिले में लाहौल स्पीति, पांगी, द्रंग, बालीचौकी तहसील और जो हमारी फ्लोटिंग पापुलेशन है, पर्यटक आते हैं, प्रोजैक्ट्स इत्यादि भी बहुत हैं। इतना बड़ा प्रैशर कुल्लू जिले पर है और कुल्लू जिला ही एक बड़ा जिला बचा हुआ है जिसके ऊपर बहुत सारा प्रैशर है। मण्डी और लाहौल के लोग भी कुल्लू आना चाहते हैं। लेकिन जब सुविधा की बात आती है, तो हमारे समर्थन में ज्यादा लोग खड़े नहीं हो पाते। मैं चाहता हूं कि इस बात के लिए सभी का समर्थन हमें प्राप्त हो।

उपाध्यक्ष महोदय, पर्यटन के ऊपर यहां बहुत बातें कही गईं। हाई एण्ड टूरिज्म को लाने की बात कही गई। पिछले बहुत लम्बे अरसे से मैं स्वयं इस व्यवसाय से जुड़ा हूं। हम कॉमर्शियल राफ्टिंग को हिमाचल में लेकर आए थे, इसको हिमाचल टूरिज्म लेकर नहीं आया था। तब वर्ष 1993-94 में कौन सी सरकार थी, मुझे इसका उल्लेख करने की जरूरत नहीं है। उस समय कॉमर्शियल राफ्टिंग को हम हरियाणा टूरिज्म के माध्यम से कुल्लू के माहोल में लेकर आए थे। आज उसी राफ्टिंग से ऐडवेन्चर स्पोर्ट्स की वजह से हिमाचल को करोड़ो रुपयों का फायदा हो रहा है। अभी आप जाइए, ऑल वैदर, पूरे साल वहां राफ्टिंग हो रही है।

14/03/2018/1605/MS/DC/1

श्री सुन्दर सिंह ठाकुर जारी----

अब यह राफ्टिंग पूरी कुल्लू वैली में तो हो ही रही है बल्कि शिमला, मण्डी और कांगड़ा तक जगह-जगह राफ्टिंग का शौक लोगों में पैदा हो गया है। एक वक्त ऐसा था जब कुल्लू

में हरियाणा टूरिज्म के माध्यम से हमने राफ्टिंग शुरू की तो इधर-उधर जो ग्वाले और गांव की औरतें होती थीं, जो वहां पशु चरा रही होती थीं उनको लगता था कि ये गतिविधि केवल विदेशियों के लिए है। उपाध्यक्ष जी, मैं पहली बार सदन में बोल रहा हूं इसलिए थोड़ा सा वक्त और चाहूंगा।-(व्यवधान) -उपाध्यक्ष जी, मैं आपके इशारे में खो गया था, आप शायद कहीं दूसरी तरफ इशारा कर रहे थे। हालांकि आपके इशारे हमें काफी अच्छे लगते हैं और आप सदन का बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। मैं यहां पर पूर्व मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी को बधाई देना चाहता हूं कि जब 80 के दशक में कश्मीर में हालात बिगड़े हुए थे तो हिमाचल ने मौका लपका और उस वक्त टूरिज्म सीधे कश्मीर से ट्रांसफर होकर हिमाचल आ गया। यह बात वर्ष 1985-90 के बीच की है। उस दौरान जो टूरिज्म हिमाचल में आया उसके बाद इतनी ग्रोथ टूरिज्म में कभी नहीं हो पाई। वह तब हुआ जब उस समय के मुख्य मंत्री जी ने केन्द्र के सहयोग से हिमाचल में कैपिटल इन्वेस्टमैंट सब्सिडी को 25 प्रतिशत रखा। हम चाहते हैं कि ऐसी कोई बड़ी योजना फिर से हिमाचल में आनी चाहिए जोकि छोटे उद्यमी को प्रोत्साहन दे। अब आप कह रहे हैं कि हिमाचल में बड़े इन्वेस्टर्ज को लाना है। यहां पर गोविन्द जी भी बैठे हैं। उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी तक यह बात कहना चाहूंगा कि अगर "स्की विलेज" का प्रोजैक्ट हिमाचल प्रदेश में आ गया होता तो आज बड़े-बड़े और दर्जनों इन्वेस्टर्ज हिमाचल में लाइन में खड़े होते। उस समय के बाबाओं ने देवी-देवताओं के नाम पर उस "स्की विलेज" प्रोजैक्ट को रोका। उसके बाद उच्च न्यायालय ने भी वैध ठहराया कि देवी-देवताओं के नाम पर स्की विलेज को रोकना गलत है। उसके बाद भी स्की विलेज से उनका मन नहीं माना और उन्होंने कहा कि जिस प्रदेश में.., हमारे सभी पहाड़ों में देवी-देवता हैं। हम भी देवी-देवताओं को मानते हैं। हम भी प्रत्येक कार्य चाहे वह चुनाव लड़ना हो, नॉमिनेशन भरना हो या कारोबार करना हो, सभी काम देवी-देवताओं को पूजकर करते हैं। हमें कुल्लू में किसी का सर्टिफिकेट लेने

14/03/2018/1605/MS/DC/2

की जरूरत नहीं है कि वे देवी-देवताओं के ठेकेदार हैं तो हमें उनसे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। बात यह है कि उस वक्त स्की विलेज के प्रोजैक्ट को रोका गया। ऐसी ही ताकतें और यही लोग थे जो देवी-देवताओं को राजनीति से जोड़ते हैं। ये वही लोग थे

जिन्होंने वहां पर देवी-देवताओं की सभा करवाकर उस प्रोजैक्ट का विरोध किया था। मैं मुख्य मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि वे एक हल्फनामा दें, एक अपनी घोषणा करें कि हम आने वाले दिनों में ऐसी किसी भी ताकत के आगे नहीं झुकेंगे। अगर यह आश्वासन सरकार देती है तभी बड़े-बड़े इन्वेस्टर्ज हिमाचल में आएंगे वरना इन्वेस्टर्ज को तो लगता है कि डी0पी0आर0 बना दो, इन्वायरनमैंट क्लीयरेंस ले लो। अगर उनके घर जाकर आपने हाजिरी भर दी तब तो देवता खुश है। अगर प्रोजैक्ट लग रहे हैं और उनके क्रशरों से आप बजरी खरीद लें तब तो देवता खुश है लेकिन अगर आप उनके क्रशरों से बजरी न खरीदो तो देवता नाराज है। ये कौन सी सदी में हम आगे बढ़ रहे हैं?

यहां पर उड़ान की बात की गई। उड़ान-1 पूरी तरह विफल हो चुकी है। उड़ान-1 को शिमला से चलना था। भुन्तर का हवाई अड्डा भी उड़ान-1 में था। मैं जानता हूं कि उड़ान-1 की जिस दिन से घोषणा हुई उसके बाद तो भुन्तर को फ्लाइट ही बहुत कम चली। -(व्यवधान)- हमने नाम नहीं लिया। लेकिन आप (इन्द्र सिंह जी)उनके शुभ-चिन्तक लग रहे हैं।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया समाप्त कीजिए।

श्री सुन्दर सिंह ठाकुरः नाटी यहां भी डालते थे। वे नाटी पालमपुर में भी डालते थे और हमीरपुर में भी डालते थे।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, आप अपना विषय रखें। मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि इन्हें बीच में बाधित न करें क्योंकि माननीय सदस्य पहली बार बोल रहे हैं।

श्री सुन्दर सिंह ठाकुरः उड़ान-1 पूरी तरह से फेल हो चुकी है और आज उड़ान-2 की बात की जा रही है। उड़ान-2 में हैलीपेड्स को जोड़ने की बात कर रहे हैं जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार के पास अभी तक एक ही हैलीपैड है

14.03.2018/1610/जेके/एचके/1

श्री सुन्दर सिंह ठाकुरः-----जारी------

और सारे के सारे हेलिपैड आर्मी के पास है। क्या आपको आर्मी ने अलाऊ कर दिया है? क्या आपको आर्मी ने वह परमिशन दे दी है कि आप उन हेलिपैड को यूज़ कर सकते हैं? यह एक बहुत बड़ी बात है। आज हमें सिर्फ एक विश्वास इन्वैस्टर के दिल में पैदा करना है कि हिमाचल में किसी वज़ह से, किन्हीं कारणों से उनके प्रोजैक्ट्स को रोका नहीं जाएगा। बहुत बड़े-बड़े प्रोजैक्ट्स हिमाचल में आने को तैयार हैं। यहां पर रोप-वे की बात की गई। मैं स्वागत करता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने अपने गृह क्षेत्र में एक रोप-वे की बात की। मैं स्वागत करता हूं कि हमारे मंत्री, गोविन्द सिंह ठाकुर जी ने कुल्लू जा करके बिजली महादेव से आगे रोप-वे बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन एक बात आप मुझे बताएं कि जो रोप-वे सोलंग नाला में लगा हुआ है, हमारे पास ऐसी कौन सी मॉनिटरिंग एजैंसी है कि रोप-वे का किराया निर्धारण सरकार करेगी? हमने सोलंग नाला में लूट की छूट दे रखी है। 900 मीटर का सिर्फ वहां पर रोप-वे है। वहां पर 650/-रूपए प्रति पर्सन चार्ज होता है, जबकि औली में 14 किलो मीटर का रोप-वे है और 750/-रूपए लिए जाते हैं। ऐसी कौन सी बात है कि हिमाचल में हम लूट की छूट दे रहे हैं? बात यह नहीं है कि आपके वक्त उद्घाटन हुआ है या हमारे वक्त हुआ, बात यह है कि इसे कन्ट्रोल में रखा जाना चाहिए। यह किराया कितना होना चाहिए, इसके बारे में तर्कसंगत बातें होनी चाहिए।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य कृपया जल्दी वाइंड अप करें।

श्री सुन्दर सिंह ठाकुरः उपाध्यक्ष महोदय, बजट में और भी बातें हुई हैं। अभी तो काफी समय है, अभी तो शुरूआत ही हुई है। मैं चाहूंगा कि इसी प्रकार कुल्लू में खीर गंगा के पास एक ऐसा रोप वे बन सकता है जिसकी माननीय पूर्व मुख्य मंत्री, श्री वीरभद्र सिंह जी ने आज से काफी वक्त पहले घोषणा की है और कुल्लू एडमिनिस्ट्रेशन को भी सर्वे करने के लिए पत्र चला गया है। खीर गंगा एक ऐसा रोप-वे बनेगा जो ऑल वैदर होगा। वहां पर ग्लेशियर हैं और हमेशा स्नो प्वाइंट रहेगा। मनाली का प्रैशर भी कम होगा और खीर गंगा में हॉट वाटर सल्फर बाथ की सुविधा

14.03.2018/1610/जेके/एचके/2

भी है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि ऐसी योजनाओं के लिए, यहां पर हमारी ब्युरोक्रेसी भी बैठी है, हमारे नई सरकार के मुख्य मंत्री और मंत्री भी बैठे हैं। ये कहते हैं कि हम पर्यटन राज्य बनाना चाहते हैं। इस पर्यटन राज्य को अगर बनाना है, आज उत्तराखंड जो हमारा छोटा भाई था वह अब बड़ा भाई बन गया है। पर्यटन की दृष्टि से आज केरल, भूटान, सिक्किम और कश्मीर तो था ही लेकिन हम इन बातों में काफी पिछड़ रहे हैं। मैं चाहता हूं अगर हमें हकीकत में आना है तो हमें टास्क फोर्स बनानी पड़ेगी। सर्वेक्षण से कुछ नहीं होगा हमें एक्शन में आना पड़ेगा। हमें टास्क फोर्स बनानी पड़ेगी । मुख्य मंत्री जी ने पर्यटन मंत्रालय अपने पास रखा हुआ है। मैं जानता हूं कि वे युवा हैं, जुझारू हैं लेकिन इनके पास इतना समय कहां है कि वे टूरिज्म के लिए समय दें। मैं चाहूंगा कि एक टास्क फोर्स बनें। टास्ट फोर्स के साथ अपार सम्भावनाएं हैं। ऐसा नहीं है कि कुल्लू-मनाली तक फोकस है। कांगड़ा में भी जगह-जगह पर अपार सम्भावनाएं हैं। लाहुल-स्पिति में अपार सम्भावनाएं हैं। मण्डी में पूरे क्षेत्र में अपार सम्भावनाएं हैं। सब जगह है। हिमाचल में हमें सीमेंट इंडस्ट्रीज़ आदि ज्यादा नहीं लगानी है। हिमाचल को पर्यटन प्रदेश बनाना है। इन ट्रकों में जो माल-भाड़ा चल रहा है और जिस प्रकार से सीमेंट से प्रदूषण फैल रहा है, बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ और खनन की वजह से जो यहां हिमाचल में क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो हमें पर्यावरण के साथ मेल खाती इंडस्ट्री हमें यहां पर लानी होगी। आज हमारे जिले के साथ एक बहुत बड़ा प्रोजैक्ट था। केन्द्र की बात करते हैं। ब्यास का तटीयकरण करना चाहते थे, सोलंग नाला से लेकर औट तक। यह एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था 700-800 करोड़ रूपए का प्रोजैक्ट वहां पर बन करके तैयार हुआ।

14.03.2018/ 1615/केएस/एचके/1

श्री सुन्दर सिंह ठाकुर जारी---

अभी तक वह प्रोजैक्ट सेंक्शन नहीं हुआ। मैं धन्यवाद करता हूं क्योंकि यू.पी.ए. सरकार के समय में, आज कुल्लू के लिए जो नेशनल हाईवे कीरतपुर से लेकर नेरचौक, नेरचौक से ले कर मनाली तक है, यह श्री कमलनाथ जी की मेहरबानी है और उस वक्त यू.पी.ए. की सरकार थी, वह काम तेजी से चल रहा है और आज अगर रोहतांग टनल बनी है तो वह भी यू.पी.ए. सरकार के समय में एक मुश्त पैसा आया, तब बनी। ये जो तटीयकरण के प्रोजैक्ट्स हैं, इनके ऊपर हमें फिर से ध्यान देना चाहिए कि कहां पर अटके पड़े हैं। क्योंकि ब्यास का तटीयकरण होना है उसके साथ हमारी बहुत सारी लैंड रीक्लेम होगी जिसका हमें फायदा होगा और इस समय उपाध्यक्ष महोदय, हिमाचल में जो फोर लेन कटिंग हो रही है, यह अप्राकृतिक ढंग से हो रही है और आपने देखा कि अभी जो कालका-शिमला हाईवे है, उसमें अभी दो ही लेन काम में आ रही है। कुल्लू-मनाली में जो औट से आगे या पीछे कटिंग हो रही है, वहां हमारे दो-तीन साल खराब होंगें । वहां बेतरतीब ढंग से कटिंग चल रही है। पूरे के पूरे पहाड़ वहां पर गिराये जा रहे हैं।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया अब वाइंड अप करिए। अभी पांच और सदस्यों ने बोलना है।

श्री सुन्दर सिंह ठाकुरः उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि हमारी राज्य सरकार की तरफ से फोर लेन को मोनिटर करने के लिए एक कमेटी बने जो देखे कि किस प्रकार से काम हो रहा है ? आज नेरचौक से आगे तो काम हो रहा है लेकिन गढ़ामौड़ा से लेकर नेरचौक तक काम ठप्प है। इसको हमारी सरकार को केन्द्र सरकार से बार-बार उठाना चाहिए और पूछना चाहिए कि यह काम क्यों रुका है? जब पूरा पोर्शन बनेगा तभी हमारा काम होगा इसलिए मैं चाहूंगा कि एक कमेटी बने जो जितने फोर लेन के काम हो रहे हैं, उन्हें देखें। कल मुझे कुल्लू से सूचना आई है कि वहां जिस प्रकार से फोर लेन बनाया गया, दो वैलीज़ के बीच में रास्त अप्रूव हो रहा है । वहां पर सब्जी मण्डी को लोगों को आना होगा तो उन्हें फोर लेन की गाड़ियों

14.03.2018/ 1615/केएस/एचके/2

का इन्तज़ार करना पड़ेगा कि कब वो उन्हें रास्ता देंगें, कब वे एक गांव से दूसरे गांव में जाएंगें। अगर उन्हें शमशान की तरफ भी जाना होगा या सब्जी मण्डी भी जाना होगा तो उस फोर लेन को क्रॉस करना होगा। ऐसी जगह पर ओवर ब्रिज या फ्लाई ओवर बनाने की जरूरत है या अण्डर ग्राऊंड जो रास्ता बनाने की जरूरत है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो पावर पॉलिसी के ऊपर बात चली है, उसका पूरा दोहन करने की बहुत जरूरत है। हिमाचल में अभी बहुत संवाद करने की जरूरत है, इंडिपैंडेंट ड्वैल्पर्ज़ के साथ बैठकर बात करने की जरूरत है। फूड प्रोसैसिंग के ऊपर बहुत सारा काम करने की जरूरत है।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से यहां पर गौसदन खोलने की बात की गई और सरकारी तौर पर उसको फंडिंग करने की बात की गई है लेकिन जो संस्थाएं अपने आपको गौ के रक्षक मानती हैं, मैंने आज तक कोई भी ऐसी संस्था नहीं देखी है जो आगे बढ़कर आई है लेकिन सरकार ने यह कदम उठाया है तो हम इसका स्वागत करते हैं। यह बड़ा अच्छा कदम है। इसके लिए हाइड्रोपोनिक्स और ऐरोपोनिक्स जिसमें कि चारे का उत्पादन होता है, के लिए कोई बजट में खास प्रावधान नहीं रखा गया है। मैं चाहूंगा कि इसे बढ़ावा देने के लिए ताकि चारा ज्यादा से ज्यादा हो हाइड्रोपोनिक्स और ऐरोपोनिक्स के लिए भी बजट में पैसा रखा जाए।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य कृपया वाइंड अप करें। 25 मिनट हो गए हैं।

श्री सुन्दर सिंह ठाकुरः उपाध्यक्ष महोदय, बस समाप्त ही कर रहा हूं। अन्त में मैं धन्यवाद करना चाहूंगा पूर्व मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी की सरकार और उस वक्त के अध्यक्ष श्री बृज बिहारी लाल बुटेल जी का इन्होंने एक बड़ा अच्छा ई-विधान का प्रावधान इस माननीय सदन में किया है। इसको आगे बढ़ाते हुए मैं सरकार से अनुरोध करुंगा कि कृपया करके "माई कन्सीच्युएंसी एप" आप हमारी विधान सभा तक भी ले कर आएं ताकि हमें इसका फायदा मिले।

14.03.2018/ 1615/केएस/एचके/3

(अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

आखिर में मैं क्रिकेट की भाषा में इतना ही कहना चाहूंगा कि गेंदबाज जवान है, कंधों में दम है और उन्होंने बड़ी तेज गेंद फेंकी है । उसमें अच्छी गति है लेकिन दिशा कोई नहीं है। अपील की है अम्पायर ने जो पब्लिक है उन पर कोई असर नहीं हुआ है । वाइड बॉल है और ओवर स्टैपिंग भी हो गई है, थर्ड अम्पायर को जाने की जरूरत ही नहीं है और इस वजह से मैं इस दिशाहीन बजट का विरोध करता हूं। धन्यवाद।

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री किशोरी लाल जी।

14.3.2018/1620/av/DC/1

श्री किशोरी लाल : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2018-19 के लिए 9 मार्च, 2018 को माननीय जय राम ठाकुर जी ने जो बजट पेश किया है, मैं उस बजट के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को इस शानदार बजट पेश करने के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं क्योंकि इसमें प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। इस बजट में मजदूरों, किसानों-बागवानों, कर्मचारी वर्ग इत्यादि का विशेष ध्यान रखा गया है और यह एक ऐतिहासिक बजट है। जहां तक मेरे विपक्ष के मित्र कह रहे थे कि इस बजट में कोई दिशा नहीं है और विपक्ष के नेता माननीय मुकेश जी कह रहे थे कि बजट पहले भी यही अधिकारी बनाते थे। लेकिन पिछली कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में जो अधिकारी थे वे पांच वर्ष पहले रिटायर हो चुके थे और जो छोटे अधिकारी/कर्मचारी इस बजट को बनाते थे उनको इस बारे में कोई विशेष दिशा नहीं दी जाती थी। पिछली सरकार में जो अधिकारी/कर्मचारी रखे गये थे वे मात्र अपने स्वार्थ के लिए काम करते थे। आदरणीय मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी की सोच है कि प्रदेश के चहुमुखी विकास के

लिए काम किया जाए। हम जब गांव में जाते थे तो हमें बहुत सारे वृद्ध लोग मिलते थे जो कहते थे कि हमें भी पेंशन लगनी चाहिए। उस दृष्टि से माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में पेंशन की आयु सीमा 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष की है जिससे हमारे प्रदेश के 1.30 लाख लोगों को फायदा होगा। इसके अलावा दिहाड़ी 210 रुपये से बढ़ाकर 225 रुपये की गई है। मुख्य मंत्री लोक भवन बनाना, कौशल विकास भत्ता जिसके लिए सौ करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इसके अलावा मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र की जलोड़ी-जोत टनल का भी इसमें जिक्र किया गया है कि इस टनल का निर्माण बहुत जल्दी किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अटल वर्दी योजना जिसमें वर्दी के साथ पहली, तीसरी, छठी व नवीं कक्षा के लिए स्कूल बैग भी दिए जायेंगे। इसके अलावा हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना, हिमाचल सड़क सुधार योजना, प्राकृतिक खेती, खुशहाल किसान योजना, मुख्य मंत्री मधु विकास योजना,

14.3.2018/1620/av/DC/2

मुख्य मंत्री आशीर्वाद योजना इत्यादि बहुत सारी योजनाएं हैं जो हिमाचल प्रदेश में अभी हाल ही में बनी हमारी सरकार ने शुरू की हैं। प्रदेश में आने वाले समय में अधिकारियों द्वारा सूचना दी जायेगी कि हमारी सरकार किस प्रकार से कार्य कर रही है। यहां पर विपक्ष की ओर से भाई सुन्दर जी ने एक बात रखी है। उसमें कुल्लू में जो रघुनाथ मन्दिर के लिए ट्रस्ट बनाया गया है उसमें एक बहुत बड़ी राजनीति हुई है। उस ट्रस्ट को पहले वाली स्थिति में लाने के लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं।

जहां तक स्वास्थ्य क्षेत्र की बात है तो मैं यहां पर अपने आनी विधान सभा क्षेत्र की बात करता हूं। पिछली सरकार ने आनी में अक्तूबर, 2017 में पांच पी0एच0सीज0 खोली गई जिनका 10 अक्तूबर, 2017 को विधिवत् रूप से शिलान्यास किया जाता है तथा 14 अक्तूबर को अचार संहिता लगती है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जिसके बारे में मैंने यहां पर प्रश्न भी लगाया था, वहां पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में 250 पद हैं जिसमें से लगभग 80 पोस्टें

खाली पड़ी हैं। मेरा माननीय मुख्य मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि उन पदों को जल्दी-से-जल्दी भरा जाए।

14.3.2018/1625/TCV/YG-1

श्री किशोरी लाल..... जारी

इसके अलावा मेरे आनी विधान सभा क्षेत्र के, दलाश में पिछली सरकार के टाईम यानि 8 अक्तूबर को एक पॉलीटैक्निकल कॉलेज की नोटिफिकेशन हुई थी। लेकिन 14 अक्तूबर को आचार संहिता लगी गई थी। मैंने लोगों से वायदा किया था कि हम इस कॉलेज को चलाएंगे। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यन्यवाद करता हूं। दलाश क्षेत्र की जनता माननीय मुख्य मंत्री से मिलने के लिए आई थी और उन्होंने माननीय मुख्य मंत्री का इस कॉलेज को चलाने के लिए धन्यवाद भी किया। यहां पर विपक्ष के मित्र श्री मुकेश अग्निहोत्री जी दलाश की चर्चा कर रहे थे, चुनाव से प्रेरित होकर आचार संहिता से मात्र 10 दिन पहले इस कॉलेज की अधिसूचना जारी की गई थी। मेरे कांग्रेस के मित्र ने संघ के घेरे की बात की है। इनको संघ से बड़ा डर है। मैं इन मित्रों को बता देना चाहता हूं कि आज के समय में RSS दुनियां का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संघ है। ये यहां बार-बार कह रहे हैं कि संघ का बहुत बड़ा दबाव है। हमारे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वयंसेवी संघ के सदस्य हैं और हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर भी एक स्वयंसेवक हैं। मैं भी एक स्वयंसेवक हूं। ये कहते हैं कि वे स्वयंसेवक मुख्य मंत्री के दफ्तर में आते रहते हैं। मैं कांग्रेस के मित्रों को कहना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा तो दफ्तरों में ये कांग्रेस के लोग ही आते हैं। इसमें क्या कोई गुनाह हो गया, यदि हमारे आर0एस0एस0 के लोग इनके दफ्तर में आते हैं।

यहां पर पर्यटन की बात की गई है, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने पर्यटन के लिए जो संभावनायें तलाशी हैं, मैं उसके लिए इनका धन्यवाद करता हूं। यहां पर पर्यटन के लिए 50 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है और मेरे आनी विधान सभा क्षेत्र में कुछेक रमणीक

स्थान हैं जिनमें विशेष रूप से सेऊरीसर, टकरासी, पनेऊ,वस्ता, खनाग, दलाश, लटाड़ा, मर्गी, बागा सराहन हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण स्थान श्रीखण्ड महादेव है। अध्यक्ष जी के माध्यम से मेरा माननीय

14.3.2018/1625/TCV/YG-2

मुख्य मंत्री जी निवेदन रहेगा कि श्रीखण्ड महादेव यात्रा को भी श्रीवैष्णों देवी और अमर नाथ की तर्ज़ पर विकसित किया जाये। ताकि आने वाले समय में यहां पर बहुत बढ़िया विकास हो सकें। हमारे भाई माननीय मंत्री श्री गोविन्द ठाकुर जी तो यहां पर स्वयं भी आये हैं। हम चाहेंगे कि आने वाले समय में यहां पर रोपवे लगाया जाये ताकि इस क्षेत्र का विकास हो सकें और हम आगे बढ़ सकें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे आनी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत निरमण्ड में रामपुर विद्युत प्रोजैक्ट लगाया गया है। इस प्रोजैक्ट से मेरे चुनाव क्षेत्र की 7 पंचायतें प्रभावित होती है। उसमें रामपुर की दत्तनगर एक पंचायत आती है और अभी हाल ही में 2 वर्ष पहले मेरे निरमण्ड क्षेत्र का 25 करोड़ लाडा का पैसा था, जो मेरी 7 पंचायतों में खर्च होना था, वह डी0सी0, शिमला को दे दिया था। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, अभी 2 दिन पहले वह पैसा जो लाड़ा के तहत मेरी 7 पंचायतों में खर्च होना था, जमा हो गया है। पूर्व मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी बजुर्ग हैं, हम उनका बहुत आदर-सम्मान करते हैं। हमें उनसे बहुत उम्मीदें थी। लोग कहते थे कि बहुत विकास होगा। पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी और माननीय श्री वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्य मंत्री थे।

14-03-2018/1630/NS/AG/1

श्री किशोरी लाल-----जारी।

ये बहुत ही नेक इन्सान और मुख्य मंत्री रहे हैं। लेकिन इनके कार्यकर्ताओं की वज़ह से मेरे आनी क्षेत्र की हालत खराब है। जितना भी बज़ट में पैसा मिलता था, वह रामपुर में खर्च किया जाता था। मेरे क्षेत्र का पैसा भी रामपुर में लगाया जाता था। रामपुर के बस स्टैंड के लिए मेरे क्षेत्र में जो प्रोजेक्ट बना है, उससे लगभग 10 करोड़ रुपये की राशि रामपुर के

लिए खर्च की गई है। इस ढंग से हमारे क्षेत्र के साथ पिछली सरकार ने भेदभाव किया है। आज आनी विधान सभा क्षेत्र की ज़नता बहुत खुश है। पिछली बार कांग्रेस पार्टी के मुख्य मंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी थे और वे हमारे लैफ्ट हैंड के मुख्य मंत्री थे। आज प्रदेश में भाजपा की सरकार है और श्रद्धेय श्री जय राम ठाकुर जी मुख्य मंत्री हैं और इनका विधान सभा क्षेत्र बिल्कुल आनी के साथ लगता है तथा ये हमारे राइट हैंड के मुख्य मंत्री हैं। अभी हाल ही में आनी विधान सभा क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्री जी का 25 जनवरी, 2018 को एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है और यहां पर इन्होंने बहुत सारी घोषणायें की हैं। इन्होंने आनी क्षेत्र के लिए एच0आर0टी0सी0 का डिपो दिया है। लहूरी के बस स्टैंड के लिए लगभग 3 करोड़ रुपये राशि की व्यवस्था की गई है और आनी के स्टेडियम के लिए लगभग 80 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। मैं विशेष रूप से माननीय मुख्य मंत्री जी का और इनके साथ आए माननीय वन मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक शिक्षा की बात है तो हमारी वर्तमान सरकार ने बहुत ज्यादा बज़ट का प्रावधान किया है। स्कूल खोलना अच्छी बात है लेकिन यदि वहां पर स्टॉफ नहीं होगा तो उसका क्या फायदा है? पिछली सरकार ने आनी विधान सभा क्षेत्र में लगातार स्कूल खोले हैं और अपग्रेड किये हैं। माननीय पूर्व मुख्य मंत्री जी आते थे और कहते थे कि इस स्कूल को पांचवीं नहीं दंसवीं तक किया जाये। मेरे क्षेत्र में 250 पद स्कूलों में रिक्त पड़े हुए हैं। आज विपक्ष के मित्र इन स्कूलों को बंद करने की बात कर रहे हैं, तभी तो आपको जनता ने पार (विपक्ष) बिठाया है। बच्चों के साथ खिलवाड़ किया गया है। मेरे क्षेत्र में कई स्कूल तो ऐसे हैं, जिनमें 2 या 3 ही स्टूडेंट्स हैं, वे किसके साथ प्रार्थना करेंगे और किसके साथ अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे? आप याद कीजिये, जब वर्ष 2007 से 2012 तक भाजपा की सरकार थी तो हमारी सरकार ने कुछेक पैमाने

14-03-2018/1630/NS/AG/2

तय किये थे कि ये स्कूल किस ढंग से खोलने हैं? इसके लिए एक मापदंड तय किया गया था। आज स्कूल डेप्यूटेशन पर चल रहे हैं। स्कूलों की इस हालत के लिए पिछली सरकार जिम्मेदार है।

अध्यक्ष महोदय, मैं अब दुग्ध उत्पादन के बारे में बोलना चाहूंगा। आज मुझे बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि आनी विधान सभा क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश का पहला विधान सभा क्षेत्र

है जहां पर सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन होता है। 35 प्रतिशत दूध का उत्पादन यहां से होता है। मैं विशेष रूप से माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इस बार दुग्ध क्षेत्र के लिए बज़ट का प्रावधान रखा है। मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि मेरा आनी विधान सभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, जहां से दूध उत्पादन की हर महीने लगभग अढ़ाई व तीन करोड़ की इनकम होती है। इस दृष्टि से मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय के समक्ष आनी क्षेत्र में वेटरनरी डिस्पैंसरी खालेने की बात रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर रोज़गार की भी बात आई थी। मैं विपक्ष के मित्र भाईयों से कहना चाहता हूं कि वर्ष 2012 में चुनावों के दौरान आपने घोषणा-पत्र तैयार किया था और उसमें आपने बेरोज़गारी भत्ता देने की बात भी कही थी। बेरोज़गारी भत्ते के माध्यम से हमारे प्रदेश के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। आपने अपने अन्तिम तीन महीनों में कुछेक लोगों को उस समय बेरोज़गारी भत्ता दिया है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने "मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना" के तहत 18 से 35 वर्ष की आयु के युवाओं को उद्योग लगाने के लिए 30 प्रतिशत का प्रावधान रखा है। यदि कोई युवक अपना उद्योग लगाना चाहता है तो उसके लिए 40 लाख का ऋण 5 प्रतिशत ब्याज की दर पर दिया जायेगा। "मुख्यमंत्री युवा आजीविका योजना" के तहत युवाओं को व्यापार करने की सुविधा प्रदान की गई है।

14.03.2018/1635/RKS/ए.जी.-1

श्री किशोरी लाल... जारी

इसके अलावा आनी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए हमारा एक प्रयास रहेगा क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी हमारे घर के हैं और इनसे हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं। आनी में 50 बिस्तरीय अस्पताल है और वहां पर 100 बिस्तरों की सुविधा दी गई है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से इस हॉस्पिटल के स्टाफ के लिए भी आग्रह करना चाहूंगा। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी एक किसान के बेटे हैं। हिमाचल प्रदेश का चहुंमुखी विकास कैसे हो, उसी दृष्टि से बहुत सारी योजनाएं इस बजट बुक में दर्शाई गई है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो इस माननीय सदन में पौने 3 घंटे का बजट भाषण दिया, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद

करता हूं। जो बहुत सारी योजनाएं युवाओं, किसान-बागवानों के लिए लाई गई हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इस सदन को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि आदरणीय श्री जय राम ठाकुर जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगभग 20-25 वर्ष तक इस प्रदेश में रहेगी और इस प्रदेश को आगे ले जाने में इनका बहुत ज्यादा योगदान रहेगा। मैं ज्यादा न कहते हुए, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो यहां पर बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसका जोरदार समर्थन करता हूं। जय हिन्द। धन्यवाद।

14.03.2018/1635/RKS/ए.जी.-2

अध्यक्षः अब माननीय सदस्य, श्री जीत राम कटवाल जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री जीत राम कटवालः माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका और इस माननीय सदन का बहुत आभार प्रकट करता हूं। दोनों पक्षों के मित्रों ने बहुत सारी चर्चा यहां पर की, बहुत सारी बातें की। हिमाचल प्रदेश एक छोटा-सा प्रदेश है और मैनेजीऐबल भी है। भारत सरकार में हम जब कभी जाते हैं तो इस प्रदेश का नाम और प्रशासन का नाम बड़े आदर-सत्कार के साथ लिया जाता है। इसके साथ ही अगर कोई स्कीम, पाइलट स्कीम या कोई भी स्कीम भारत सरकार शुरू करना चाहती है तो हिमाचल प्रदेश को सबसे श्रेष्ठ नज़रों से देखा जाता है। जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी व हमारी विचारधारा 'सबका साथ, सबका विकास' पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जानी जाती हैं। यह माननीय सदन इस विकास की प्रक्रिया में समय-समय पर चिंता और चिंतन भी करता है। इस चिंतन में बहुत अच्छी बातें भी सामने आती हैं। क्रिटिसिज्म भी होता है परन्तु कुल मिलाकर इस प्रदेश को आगे ले जाने में यह सदन, आम जन-मानस और सब का सहयोग हमेशा मिलता रहा है। मैं कुछेक बातें तथ्यों पर कहूंगा। कहा गया कि-वर्ष 2012-13 में जब कांग्रेस की सरकार आई तो उस समय ऋण 27,598 करोड़ रुपये था।

14.03.2018/1640/बी0एस0/वाई0के-1

श्री जीत राम कटवाल ....जारी

और जब 2017 में कांग्रेस सरकार गई तो 18787 करोड़ रुपये ऋण की वृद्धि के साथ कुल ऋण 46385 करोड़ हुआ। इससे लगता है कि विकास भी उसी तरीके से होना चाहिए था, हुआ होगा? मेरे पूर्व कुछ मित्रों ने भी कहा और कुछ आंकड़े भी यहां कहे गए। Economic growth पर मैं पहले बोलना चाहूंगा। 2012-13 में 6.4 प्रतिशत Economic growth थी। 2013-14 में 7.1 प्रतिशत थी, 2014-15 में 7.5 प्रतिशत थी, 2015-16 में 8.1 प्रतिशत Economic growth थी, 2016-17 में 6.9 प्रतिशत Economic growth थी, 2017-18 में प्रीज़म्प्शन के साथ 6.3 Economic growth आंकी गई है। इस की अगर एवरेज निकाले तो यह 7.2 प्रतिशत ग्रोथ पिछले पांच वर्षों में हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2007-12 तक रही उसकी जो ग्रोथ है कुल-मिलाकर 8 प्रतिशत रही है । इसका मतलब यह हुआ कि पिछले पांच वर्षों में जो ग्रोथ होनी चाहिए थी और जितने अमाऊंट के ऋण Market borrowing या जो भी कहा गया कि सरकार चालाने को ऋण लेने की आवश्यकता होती है, स्वतः ही मैं ठीक मानता हूं, होती है और होती रहेगी परंतु जिस दर से ऋण लिए गए उस दर से उसकी ग्रोथ होनी चाहिए थीं। परंतु वह उलटा हुआ, .8 का जो डिक्लाइन इसमें आया है और इसके साथ ही जो Per Capita Income थी, वह 2007-12 में भारतीय जनता पार्टी के दौरान 1,03,500/- रुपये थी और अब जो Per Capita Income है, जो प्रति व्यक्ति आय आंकी गई है या जो Economic Survey ने जो फीगर्ज जारी की हैं, उसमें 1,58,562/- रुपये इंकम दर्शाई गई है और जो 1,03,500/- रुपये जो इंकम थी वह पिछली इंकम में 63.11 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती थी। आज अब जो इंकम आई है इसमें 46.69 प्रतिशत की वृद्धि है। यह भी दर्शाती है कि जो ग्रोथ हुई है वह Per Capita Income में पिछले पांच वर्षों में गिरावट आई है। यह आंकड़े सरकार के जो Economic review और जो आप लोगों से समक्ष रखा गया है उससे में उद्धृत कर रहा हूं।

14.03.2018/1640/बी0एस0/वाई0के-2

उसके बाद बात आई ग्रांट इन एड की यू.पी.ए. सरकार के दौरान कुछ स्कीमें 50 प्रतिशत में थीं कुछ स्कीमें 75 प्रतिशत में थीं और कुछ स्कीमें 65 प्रतिशत में थीं। स्पेशल केटगरी स्टेट्स को 90:10 के साथ 90 प्रतिशत भारत सरकार और 10 प्रतिशत राज्य सरकारें उस प्लान का खर्चा वहन करती थी। माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने हमें 90/10 की रेशों दी, वित्त आयोग की सिफारिशें हैं, लागू कौन सरकार करती है? उसके अनुसार पूरे-के-पूरे हिमाचल प्रदेश को 90:10 के रेशो में डाला यह भी केन्द्र सरकार की इस प्रदेश के प्रति, इस प्रदेश के विकास के प्रति "सबका साथ सबका विकास" उसके प्रति एक चिंता, दूरदर्शिता और श्रेष्ठता को दर्शाती है और जो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की है। जहां कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में रही विकास और Infrastructure development हमेशा ज्यादा हुआ है, यह रिकार्ड की बात है। इसको कोई भी आदमी कभी भी जान सकता है।

14.03.2018/1645/डी0टी0/DC-1

श्री जीत राम कटवाल ....जारी

सड़को के बारे में, पानी के बारे में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का जो इतिहास रहा है, वह जगजाहिर है। आदरणीय शांता कुमार जी पानी वाले मुख्य मंत्री के रूप में जाने जाते है। माननीय प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी सड़कों वाले मुख्य मंत्री के नाम से जाने जाते हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधान मंत्री ग्राम सड़के योजना शुरू कर एक नई शुरूआत की, जिसमें लगभग 3000/- करोड़ रुपये के खर्च से 2238 किलोमीटर सड़के प्रदेश में बनी है। आज हम सब यह देखते हैं और अपने विकास में केन्द्र की सहभागिता को समझ चुके हैं।

बात आई कि पुरानी शराब, नई शराब कई तरह के शेर बोले गये । अपना-अपना मत और वक्तव्य देना सदस्यों का अधिकार है। परंतु इतना जरूर कहूंगा कि पार्लियामेंट्री फार्म

ऑफ गवर्नमैंट लोगों के हितों के लिए और एक exclusive Government extensive as well as intensive development के लिए काम करने की अपेक्षा रखी जाती है। लोगों की छोटी से छोटी समस्या हो या कोई बड़ी योजना हो, लोगों को हम लोगों से अपेक्षाएं होती है और लोगों की अपेक्षाओं में खरा उतरने के लिए कोई भी सरकार भरपूर प्रयास करती है। वर्तमान सरकार ने भी पूरा प्रयास किया है और मैं अगले विवेचन से पहले यह कहना चाहूंगा कि माननीय जय राम ठाकुर जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें 28 नई योजनाएं शामिल कीं गई हैं। छोटे से छोटे ग्रुप को शामिल किया गया है। ये extensive, intensive and exclusive budget की निशानी है। इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों का ध्यान रखा गया, ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों का ध्यान रखा गया और ज्यादा से ज्यादा स्कीमें माइक्रो लेवल से शुरू की गई हैं। इसका मतलब यह है कि इस सरकार और माननीय मुख्य मंत्री महोदय को आम जन मानस के बारे में चिंतन है। उस चिंतन को पूरा करने के लिए यह बजट का दस्तावेज आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। पिछली कांग्रेस सरकार का बजट देखा 161 पैराज थे। हमारा बजट भी 158 पैराज हैं। लगभग एक बात तो स्पष्ट है कि अंतिम वर्ष का बजट जो सरकार का होता है उसमें सरकार का प्रयास होता है कि लोगों को कुछ दिया जाए। कुछ लोगों को प्रोजेक्ट किया

14.03.2018/1645/डी0टी0/DC-2

जाए ताकि उनका विश्वास जीत सकें। हमारी सरकार ने वह काम पहले वर्ष से ही शुरू कर दिया है। जो - जो शंकाएं मेरे कांग्रेस के मित्र जाहिर कर रहे है, उनके बारे में भी मैं कुछ कहना चाहूंगा। पैरा नम्बर 161 में लिखा हुआ है ' All departments will continue to undertake exercise to delegate and simplify procedures to reduce the requirement of the people to visit Government offices'.

14.03.2018/1650/SLS-HK-1

श्री जीत राम कटवाल... जारी

इसमें सरलीकरण की बात हुई है। हमारी सरकार ने बजट के पैरा नं. 14 (3) में भी कुछ ऐसा ही मिलता-जुलता लिखा हुआ है जो मैं उद्धृत करता हूं - 'हमारी सरकार राज्य के सभी अधिनियमों, नियमों तथा योजनाओं की उनके प्रभावों, प्रासंगिकता तथा सरलीकरण की कसौटी पर समीक्षा करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को सरकारी कार्यालयों में आने में कमी लाना होगा। प्रदेश के सभी विभाग इनके सरलीकरण के बारे में प्रस्ताव आगामी 6 महीनों में मंत्रिमंडल के समझ लाएंगे।'

धारा-118 की बात आई। माननीय मुख्य मंत्री ने मात्र यह कहा था कि इसके बारे में हम सलाह लेंगे और लोगों के सुझाव लेंग; अगर कुछ बनता है तो इसके सरलीकरण के लिए काम करेंगे। परंतु मैं कांग्रेस मित्रों का एक वीडियो टी.वी. पर देख रहा था जिसमें वह कह रहे थे कि हम हिमाचल प्रदेश को बिकने नहीं देंगे। यह सरलीकरण की बात थी, बेचने की नहीं थी। यह प्रोपोगैंडा की बात नहीं थी बल्कि सदन में माननीय मुख्य मंत्री ने स्पष्ट किया था कि यह सुझाव की बात है, आप भी सुझाव दें। सदन में रूल ही पास होता है। चाहे delegated legislation हो, सदन में ही उसको अप्रूव किया जाता है; चाहे एक्ट में अमैंडमैंट हो या किसी धारा में संशोधन की बात हो तो वह ऐसे चुपचाप बैठ कर किसी कमरे में नही होता। ये बातें भी एक जिम्मेवार तरीके को दर्शाती हैं। यह हमने सुझाव की बात की है और आम जनमानस के लिए सरलीकरण की बात की है। वह बात नहीं कि साढ़े चार साल बाद कुछ भी करने को दिन-रात एक करके कर दो। वैसा नहीं था। सरकार ने अपने प्रथम वर्ष के पहले महीने में यह अपनी इच्छा जाहिर की और जो बजट का डाक्युमैंट लाया, उसमें जो विशेषताएं दर्शाई वह शुरुआत में ही दर्शाई। ऐसा नहीं कि कोई चौथे साल किया या किसी दवाब में किया या किसी को प्रलोभन देने का कोई मसौदा बनाया हो।

जहां तक धारा-118 में संशोधन की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने मात्र एक संशोधन वर्ष 2002 में किया है जबकि कांग्रेस सरकार ने 1976, 1986,1996, 2005

14.03.2018/1650/SLS-HK-2

और 2006 में कुल 5 दफ़ा संशोधन किए हैं। वह संशोधन भी इस सदन में ही हुए होंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी को इस सुझाव के मामले में इतने जोश-ख़रोश के साथ मीडिया में लाया जाए तो इसकी प्रासंगिकता विपक्ष खुद समझे, यह मेरा मानना है।

रही बात विज़न की कि विज़न नहीं है, इंप्लायमैंट नहीं है, नवयुवकों और बेरोज़गारों के बारे में कोई चिंतन नहीं है। आप पैरा संख्या : 13 को देखें। उसमें मार्गदर्शक सिद्धांत दर्शाए गए हैं। वह विज़न ही होना चाहिए, अगर हम समझें। हम क्या करने वाले हैं, किन लोगों के बारे में इस प्रकार का चिंतन है, यह उन सिद्धांतों से स्पष्टतः ज़ाहिर होता है।

उसके अलावा जो यह कहा जाता है कि यह स्कीमें वही हैं, केवल नए नाम हैं, आप पहले देखिए कि अभी तक इसके बारे में या इन छोटी-छोटी स्कीमों में कोई एलोकेशन किसी समय पर हुई है? शायद नहीं। मैंने पिछले 5 बजट पढ़े हैं। आप इसको भी देखें।

जो इनवैस्टमैंट की बात है, मैं उस पर आ रहा हूं। मैं रोज़गार की बात भी करने जा रहा हूं। उस रोज़गार के साथ आपको यह भी स्पष्टतः समझने की बात है कि इरिगेशन में, एग्रिकल्चर में, हार्टिकल्चर में और फिसरीज़ क्षेत्र में एक इनवैस्टमैंट का प्रावधान किया है। इनवैस्टमैंट जहां होगा, स्वतः ही रोज़गार की संभावनाएं, रोज़गार के अवसर उसमें निकलेंगे।

जहां तक लीज की बात कही गई है, यह मछुआरों को फिस फार्म के लिए लीज की बात है, गौसदन को चलाने के लिए लीज की बात है, कोई बुरी बात नहीं। आज हरेक व्यक्ति सभी विधायकों को यही कहता है कि अवारा पशुओं से निजात दिलाई जाए और पशुओं को गौसदन में रखने का या फ़सलों को बचाने का प्रयास होना चाहिए।

14/03/2018/1655/RG/YK/1

श्री जीत राम कटवाल----जारी

सरकार से इसकी अपेक्षा है और अभी जो सरकार ने 'गौसेवा आयोग' की स्थापन की घोषणा की है, तो मैं आपको यह बात भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब किसी चीज के साथ 'आयोग' शब्द लग जाता है, तो वह Statutory Body बन जाती है। कोई बोर्ड होता था, तो बोर्ड ने क्या किया, क्या नहीं किया या आज की स्थिति में क्या करना चाहिए। इसलिए सरकार ने बड़ी दूरदर्शिता के साथ 'गौसेवा आयोग' की स्थापना की है। --(घण्टी)--- अध्यक्ष महोदय, उधर के लोगों ने 25 से 28 मिनट तक बोला है। कृपया मेरा निवेदन भी स्वीकार करें। इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि इन तथ्यों को भी न नकारें। हरेक वर्ग के लिए इस बजट में कुछ-न-कुछ दिया गया है। कर्मचारियों को 4% अतिरिक्त अंतरिम राहत दी गई है जो एक अच्छी बात है।

अध्यक्ष महोदय, ये लोग कहते हैं कि ये प्रोडयूसर एवं डायरैक्टर वही हैं, तो ऐसा नहीं है। यह इस तरफ हैं। वे प्ले बैक सिंगर हैं, प्रोडयूसर एवं डायरैक्टर तो कभी आप थे और आजकल हम हैं। तो प्ले बैक सिंगर या प्रोडयूसर एवं डायरैक्टर के अन्तर को समझने की बात है। दूसरी तरफ के जो मेरे मित्र हैं, वे भी इस बात को समझें। जो आप लोग करते थे, वह अगर हम कर रहे हैं, तो हमारी विचारधारा और घोषणा-पत्र एवं दृष्टि-पत्र के अनुसार हम आगे बढ़ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसमें 'मुख्य मंत्री आदर्श विद्या केन्द्र' का प्रावधान किया गया है। प्रैस वाले भाइयों के लिए आपातकालीन चिकित्सा हेतु 'हिमालच प्रदेश पत्रकार योजना' शुरू की गई है और इसमें बढ़ौत्तरी की गई है। पहले 66 मैडीसिन फ्री मिलती थीं, लेकिन इस सरकार ने 330 मैडिसिन देने का संकल्प किया है और इसको बजट में लाया गया है। इसके अलावा बच्चों के लिए एक नई किट देने की व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार ये सभी नई और इनोवेटिव स्कीम्ज हैं। इन सभी को आपको देखना चाहिए और राजनीतिक चश्मे से हटकर इस बजट का समर्थन करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, रोड इंप्रूवमेंट स्कीम लाई गई है, क्रॉस ड्रेनेज और मुख्य मंत्री कार्यालय के अधीन independent quality Check squad का गठन किया जाएगा। ये नई-नई इनोवेशन हैं। इसको भी इनको देखना चाहिए। यह एक व्यवस्था की बात है। यह 'उज्ज्वला' जैसी स्कीमें हैं। अब सभी पात्र परिवारों को गैस देने की बात की गई है। पहले

14/03/2018/1655/RG/YK/2

यह कुछ ही लोगों को मिलती थी। इसके अलावा 69 हाइवेज के लिए 50,000 करोड़ रुपये की राशि भारत सरकार ने स्वीकृत की है। स्वीकृत करने का मतलब यह था कि डी.पी.आर. बनती, परन्तु अभी रिकॉर्ड में यह आया कि आज दिन तक उसके लिए कंसलटेंट तक नियुक्त नहीं हुए। डेढ़ वर्ष इसकी घोषणा हुए हो चुके हैं। इनकी डी.पी.आर्ज. जातीं, उन पर काम शुरू होता और प्रदेश के लोग इनका फायदा उठाते और हम भी यहां आपका धन्यवाद करते।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री जीत राम कटवाल : अध्यक्ष महोदय, टूरिज्म और पॉवर में पहली बार निवेश की बात हुई है। छोटा निवेश ही सही, लेकिन टूरिज्म में 50 करोड़ रुपये है और पॉवर में भी पैसे देने की व्यवस्था है। इसके साथ ही आप लोग यह माने कि कम-से-कम प्रयास तो शुरू हुए और नए हैं। गतिविधियां वही रहेंगी, लोग वही होंगे और परिस्थितियां भी वैसी ही मिलेंगी। थोड़ा बहुत बदलने की क्षमता जिस सरकार में होगी, वह बदल देगी।
अध्यक्ष महोदय, 'बागवानी विकास परियोजना' एवं 'सौर सिंचाई योजना' भी शुरू की गई हैं और 'जल से कृषि को बल', इस तरह की योजनाएं शुरू की गई है। 'जीरो बजट प्राकृतिक कृषि', एक अच्छे प्रयास के रूप में सरकार आपके सामने लाई है। यह आम जनमानस के लिए बहुत फायदे की योजनाएं हैं। 'कृषि सम्पदा योजना' कुछ योजनाएं ऐसी हैं। पी.आर.आईज. और समाज के सभी वर्गों इनक्लूसिव ऐक्सटेन्सिव बजट के तहत हरेक वर्ग को इस बजट में राहत देने का प्रयास हुआ है। मैं ज्यादा न कहता हुआ इस बारे में सरकार के जो मन्सूबे है, वे प्रथम वर्ष के बजट में ही जाहिर हुए हैं और सरकार इन मंसूबों को आने वाले पांच सालों में पूरी दक्षता एवं निष्ठता के साथ इसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहेगी।

14/03/2018/1700/MS/DC/1

श्री जीत राम कटवाल जारी----
आप लोगों का सहयोग साथ रहे, उसके लिए भी हम आपसे अपेक्षा करते हैं। मैं ज्यादा न कहता हुआ, अपने चुनाव क्षेत्र की दो-तीन बातें पिछले पांच वर्षों की कहूंगा।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, एक मिनट बैठ जाइए क्योंकि सदन का समय बढ़ाना है। **अब इस मान्य सदन की बैठक आधे घण्टे (5 बजकर 30 मिनट तक) के लिए बढ़ाई जाती है।** माननीय कटवाल जी, बोलिए।

श्री जीत राम कटवालः अध्यक्ष जी, धन्यवाद। मेरा चुनाव क्षेत्र चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। भाखड़ा डैम के बारे में जब चर्चा हुई तो उस चर्चा में मैंने भी अपना पक्ष रखा था। मेरा चुनाव क्षेत्र चारों तरफ से पानी से घिरा होने के बावजूद भी वहां पानी की गम्भीरतम समस्या है। एक भी ब्रिज कोटधार क्षेत्र में आज दिन तक नहीं बना और बागछाल ब्रिज बनाने के लिए भी हमें उच्च न्यायालय जाना पड़ा। मुझे वर्तमान सरकार से अनुरोध करना है कि इस पर काम मुस्तैदी और शीघ्रता से करने के प्रयास जारी रखें। इसी तरह से वहां पांच स्कीमें सिंचाई की हैं जोकि नहीं चलीं। वे स्कीमें कई सालों से लटकी हुई हैं। उनके ऊपर भी काम करने के लिए मैं अनुरोध करूंगा। इसके अलावा चार पुलों के जो मसौदे हैं वे मैंने सरकार को विधायक प्राथमिकताओं में दर्शाए हैं। उनके बारे में भी सरकार गौर करे। एक मेरी पी0एच0सी0 ऋषिकेश है वहां पिछले पांच वर्षों से डॉक्टर नहीं है। मेरा अनुरोध रहेगा कि वहां डॉक्टर भेजे जाएं। हालांकि कहा तो यह गया कि वहां पद ही क्रिएट नहीं हैं परन्तु मेरा अध्यक्ष जी के माध्यम से सरकार से अनुरोध रहेगा कि उसके लिए न केवल प्रयास किए जाएं बल्कि उस मांग को पूरा करें ताकि 10 हजार की जनसंख्या को उससे राहत मिले। मैं ज्यादा न कहता हुआ इन्हीं शब्दों के साथ बजट का समर्थन तो करता ही हूं हालांकि मैंने शुरू में भी बजट का समर्थन किया है। अध्यक्ष जी, यहां पर कई माननीय सदस्यों ने शेर बोले और कइयों ने कुछ और कहा। मैं भी एक छोटा सा वाक्य कहना चाहता हूं।

जो तुमको हो पसन्द वह बात भी कहेंगे,
अगर तुम दिन को रात कहो तो हम रात नहीं कहेंगे।

धन्यवाद। जयहिन्द।

14/03/2018/1700/MS/DC/2

अध्यक्षः अब चर्चा में माननीय सदस्य श्री पवन काजल जी भाग लेंगे।

श्री पवन काजलः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो 9 मार्च, 2018 को इस मान्य सदन में अपना पहला बजट प्रस्तुत किया था, उस पर हो रही चर्चा में भाग लेने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले यहां पर चुने हुए सभी 68 माननीय सदस्यों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं शुरू में ही एक शेर सभी के लिए अर्ज करना चाहूंगा।

चमन में फूल खिलते रहें, कभी न हो कांटों का सामना,
जिन्दगी आपकी खुशियों से भरी रहे, यही है हमारी शुभकामना।

अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने यहां जो पहला बजट प्रस्तुत किया, उस पर हो रही चर्चा में भाग लेते हुए वहां से एक माननीय सदस्य ने कहा कि आपके पूर्व मुख्य मंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी ने भी टेबल थपथपाकर बजट का समर्थन किया। अध्यक्ष जी, वास्तव में ऐसा था कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने 9 मार्च, 2018 को जो बजट पढ़ा और माननीय पूर्व मुख्य मंत्री जी ने जो बजट 10 मार्च, 2017 को पढ़ा तो माननीय पूर्व मुख्य मंत्री जी जब इस बजट को पढ़ रहे थे तो उनका यह कहना था कि मैंने एक साल पहले जो बजट रखा था उसमें दो-चार बिन्दुओं को छोड़कर यह वही बजट है जो अब माननीय मुख्य मंत्री जी ने पेश किया है तो इसलिए वे टेबल थपथपा रहे थे।

अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले सभी माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि जो रोज़गार सृजन एवं निवेश को आकर्षित करने के लिए कांगड़ा में

14.03.2018/1705/जेके/वाईके/1

श्री पवन काजलः------जारी-------

लगभग 12 करोड़ रु0 के आई.टी. पार्क को बजट में लिया है, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि यह जो प्रोसैस है, यह पिछले दो सालों से हैं और एक साल पहले हमने इसके लिए जगह का चयन किया था। वह मेरे कांगड़ा विधान सभा क्षेत्र गग्गल में हैं। इसी तरह माननीय मुख्य मंत्री महोदय जी ने, जो बात सही है, हम उसका समर्थन करेंगें, अध्यक्ष

महोदय, जो "मुख्य मंत्री लोक भवन योजना" शुरू करने की मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है, इसका हम स्वागत करते हैं परन्तु इसमें 30 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है, वह कम है। अच्छा होता कि आप इसको 50 लाख रुपये करते तो हम समर्थन करते। इसी तरह जो विधायक निधि माननीय मुख्य मंत्री जी ने बढ़ाई , आपको याद होगा कि माननीय श्री वीरभद्र सिंह जी ने जब 2012 में सत्ता की कमान सम्भाली तो हम नए-नए चुनकर आए थे, हमें 50 लाख रुपया विधायक निधि का मिलता था। जब 2017 में हमने चुनाव लड़ा तो उस समय तक विधायक निधि 1 करोड़ 10 लाख रुपये तक थी। वैसे तो हम इसका समर्थन करते हैं परन्तु हम चाहेंगें कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसको इतना तंग दिली से सिर्फ 15 लाख रुपये बढ़ाया है, इसे और बढ़ाया जाए। मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि यह माननीय मुख्य मंत्री जी ने मेरे कहने से बढ़ाई है क्योंकि प्लानिंग की मीटिंग में मैंने मुख्य मंत्री जी से कहा था कि आप नए ऊर्जावान, नए डाइनामिक मुख्य मंत्री बने हैं, आप विधायक निधि और ऐच्छिक निधि के बारे में भी सोचना। बढ़ाई तो है इन्होंने परन्तु थोड़ी तंगदिली से बढ़ाई है। भविष्य में भी इसको बढ़ाने की कोशिश करना। इसी तरह माननीय अध्यक्ष जी, आज हम जितने भी माननीय सदन में 68 सदस्य हैं, मैं एक बात आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि आप जितना मर्जी इस बजट का समर्थन करते रहो या समर्थन न करते रहो परन्तु आने वाले समय में जो बन्दरों का उत्पात है, आवारा पशुओं का उत्पात है और ये जो 68 माननीय सदस्य यहां पर बैठे हैं इनको चिन्तन करने की जरूरत है। ये बजट की कापियां यहीं रह जाएगी। हम भी जब नये-नये यहां पर आए थे, जब 2012 में दलगत

14.03.2018/1705/जेके/ वाई**के /2**

राजनीति से ऊपर उठ कर मैं यहां पर आया था तो यहां पर कई सदस्य चार-चार बार जीते थे कोई, पांच बार जीता था और कोई छः बार जीते थे उस वक्त भी बन्दरों पर चर्चा होती थी, आवारा पशुओं पर बात होती थी। माननीय अध्यक्ष जी, इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी को मैं कहना चाहूंगा कि ये डायनामिक मुख्य मंत्री हैं, इसके लिए ऐसी नीति बनाई जाए, ऐसा प्लान बनाया जाए जिसमें एक्शन लिया जाए, नहीं तो लोग मार देंगे। यह

आपको ही नहीं मारेंगे, 2022 में आपको ही नहीं बल्कि इसका फर्क हमें भी पड़ेगा। आवारा पशुओं की वज़ह से आज जितने भी एक्सिडैंट हो रहे हैं, नेशनल हाई वेज में एक्सिडैंट हो रहे हैं, वे आवारा पशुओं की वज़ह से हो रहे हैं। किसान आज सब्जी लगा रहा है, अपनी खेती कर रहा है लेकिन उसको बन्दर खराब कर देते हैं, उसको आवारा पशु खराब कर देते हैं। इसके लिए एक ठोस नीति बनाने की बहुत जरूरत है। साल-दो साल में इसमें एक्शन लेने की जरूरत है। मैं इसका समर्थन करता हूं कि मधुपालकों के लिए बजट में 10 करोड़ का प्रावधान किया है, क्योंकि जो मेरा विधान सभा क्षेत्र है वहां पर लगभग 500 परिवार इस आजीविका से जुड़ा हुआ है। इसके लिए मैं ज़ोरदार समर्थन तब करता अगर इसमें ज्यादा पैसा रखा होता। चलो फिर भी कुछ हद तक हम इसका समर्थन करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, एक बात और मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा और सरकार के ध्यान में भी लाना चाहूंगा, आप लोग बुरा मत मानना।

14.3.2018/1710/av/AG/1

श्री पवन काजल जारी--------

मैं आदरणीय मोदी जी के ध्यान में भी लाना चाहूंगा कि वर्ष 2019 का जो चुनाव आ रहा है, आपने मनरेगा में काम करने वालों को खत्म कर दिया है। क्या आपको पता है, जबसे आपकी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है मनरेगा में न पैसा आ रहा है और न ही सीमैंट आ रहा है। यह ठीक है कि अभी प्रदेश में आपकी पार्टी की सरकार बनी है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब से केंद्र में आपकी पार्टी की सरकार बनी है तब से यहां पर मनरेगा के लिए जितना पैसा आता था उतना नहीं आ रहा है। केंद्र में यू0पी0ए0 सरकार के कार्यकाल में मनरेगा में सौ-सौ दिन लगते थे। अब जब आप अपने-अपने विधान सभा क्षेत्र में जाते हैं तो आपने कभी मनरेगा के बारे में पूछा वहां पर कभी 10 दिन लग रहे हैं तो कभी 12 दिन लग रहे हैं। आने वाले समय में आप मनरेगा के कारण डूब जायेंगे क्योंकि अब मनरेगा के अंतर्गत काम करने वाली माताओं, बहनों और बुजुर्गों को काम नहीं मिल रहा है। बजट में यह भी लिखा है कि हैण्ड-पम्प द्वारा पेयजल आपूर्ति के

लिए भाजपा सरकार वर्ष 1990 से कार्य कर रही है, यह बड़ी अच्छी बात है। आज तक 36901 हैण्ड-पम्प लगे हैं। इसके लिए 20 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है और यदि 1.60 रुपये में एक हैण्ड-पम्प लगे तो 1250 के लगभग हैण्ड-पम्प लगेंगे। मैं अध्यक्ष महोदय के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि कई निर्वाचन क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर हैण्ड-पम्प कामयाब नहीं होते हैं। हमारा कांगड़ा जिला केवलमात्र हैण्ड-पम्पों पर निर्भर है इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाए। ये जो 1250 हैण्ड-पम्प लगाने की बात की गई है तो इसको अगर विधान सभा क्षेत्रवार देखें तो लगभग 20-20 हैण्ड-पम्प लगेंगे। पेंशन की आयु सीमा को जो आपने 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष किया है मैं इसका भी समर्थन करता हूं। इसके लिए एक बात आपने ठीक की है कि इसमें जो 600 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है मैं इसके लिए आपके ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं कि

14.3.2018/1710/av/AG/2

पिछली सरकार के समय में पांच वर्षों में मेरे विधान सभा क्षेत्र में 8000 पेंशन लगी थी। मेरा यहां पर जीत कर दोबारा आने का कारण भी यही है इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि एक साल में जितने ज्यादा बुजुर्गों को पेंशन लगेगी वह ठीक रहेगा। बजट में कई तो पुराने बिन्दु हैं मैं इन पर नहीं जाना चाहता। इसके अतिरिक्त ऐच्छिक निधि बढ़ाने के लिए भी मैं बजट का समर्थन करता हूं। इसके अलावा यह कहा गया है कि प्रत्येक पंचायत में मोक्ष धाम चरणबद्ध तरीके से बनाये जायेंगे परंतु इसमें बजट नहीं रखा है। आपने इसके लिए घोषणा तो कर दी है मगर इसके लिए बजट नहीं रखा है। पर्यटन की दृष्टि से आपने धर्मशाला निर्वाचन क्षेत्र के लिए लिखा है कि त्रियुंड में रोप-वे बनायेंगे। यह अच्छी बात है और जितनी जल्दी हो सके रोप-वे बनाने चाहिए। आपको हिमाचल प्रदेश की अर्निंग को बढ़ाना चाहिए मगर यह पता नहीं कि यह सिर्फ कागजों में ही रह जायेगा। पिछली सरकार के समय में माननीय मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी ने हर चुनाव क्षेत्र के लिए 10-10 लाख रुपये की घोषणा की थी।

14.3.2018/1715/TCV/AG-1

श्री पवन काजल.... जारी

उसको तोड़-मरोड़ करके मुख्य मंत्री खेल संरक्षण योजना में 6.80 लाख रुपये कर दिया। लोगों को बेवकूफ बना दिया, कम-से-कम पिछला तो दे देते। माननीय अध्यक्ष जी उससे हमें भी फ़र्क पड़ा और आपको भी फ़र्क पड़ा। ---(व्यवधान)---क्या आपने 10-10 लाख रुपया मांगा था? आप विधान सभा में बोलते और वह मिलता। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह 10-10 लाख रुपया अभी भी मांगना है ।

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी नहीं बैठे हैं, मैं उनके ध्यान में कुछ बातें लाना चाहूंगा। हिमाचल प्रदेश पूरे देश में एक शान्तिपिग्र प्रदेश है। यह देव और वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। परन्तु आज प्रदेश में स्वास्थ्य की बहुत बुरी हालत है। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो सिविल हॉस्पिटल है, उनमें 8 सैंक्शन्ड पोस्टें हैं, उनमें में 3 फिलअप है और 5 वैकेंट हैं। ---(व्यवधान)--- श्री राकेश पठानिया जी मैं आपको बताना चाहूंगा, जो टांडा मैडिकल कॉलेज हैं, वह एक रिसर्च सेंटर है। क्या एक जुखाम या बुखार की दवाई लेने के लिए हम टांडा जायेंगे? मैं सरकार से यह चाहूंगा कि डाक्टरों के इन रिक्त पदों की पूर्ति की जाये। मैं आपको बताना चाहूंगा, कांगड़ा एक मात्र ऐसा सिविल हॉस्पिटल था, जिसकी ओ0पी0डी0 900 और 950 थी। आज की डेट में 250 और 300 के करीब रह गई हैं। मैं एक और बात बताना चाहूंगा, यह कांगड़ा हॉस्पिटल की बात नहीं है। ये ठीक है कि नई सरकार बनी है। हम स्वागत करते हैं कि जनता ने आपको चुना है। लेकिन क्या किसी भी विधान सभा क्षेत्र के, एक भी सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर के पूरे पद भरे हुए हैं; क्या वहां पर एक्स-रे मशीन धूल तो नहीं चाट रही है; क्या वहां पर अल्ट्रासाऊंड करने वाला कोई रेडियोलोजिस्ट है? अध्यक्ष महोदय, जो सरकार बनी है, उसमें यंग-यंग विधायक और मिनिस्टर आये हैं। ये भी भगवान की कृपा है, इसके लिए आप कुछ करिए। मैंने प्लानिंग की मीटिंग में भी कहा था कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने और जो वोटर थे, पता नहीं उनकी कब-कब मीटिंग हुई

कि किसको-किसको हराना है और किसको-किसको जीताना है। एक शान्तिप्रिय प्रदेश आगे बढ़ सके, इसके लिए हम सबको (68 सदस्यों)प्रयास करना पड़ेगा।

14.3.2018/1715/TCV/AG-2

माननीय अध्यक्ष जी, मैं ओ0बी0सी0 से संबंधित हूं, ये आप सब जानते हैं और कांगड़ा जिला में ओ0बी0सी0 जाति 56 परसेंट है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश में ओ0बी0सी0 जाति 25 परसेंट है। भारत के संविधान के 93वें संशोधंन में अनुच्छेद् 15 की धारा (5) के अंतर्गत केन्द्रीय शिक्षा संस्थानों में, अन्य राज्यों में ओ0बी0सी0 को 27 परसेंट आरक्षण दिया गया है। हम 27 परसेंट आरक्षण नहीं मांग रहे हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने एस0सी0 और एस0टी0 का जो बैकलॉग भरा था, मैंने प्रश्न भी किया था और माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसकी 9 अप्रैल, 2017 को नोटिफिकेशन भी की थी कि जिस तरह हमने एस0सी0 और एस0टी0 का बैकलॉग भरा है,

14-03-2018/1720/NS/YK/1

श्री पवन कुमार काजल ------जारी।

उसी तर्ज़ पर हम ओ0बी0सी0 का बैकलॉग भी भरेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि प्रदेश में इनको आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। यहां पर कई संस्थानों में आरक्षण दिया जा रहा है। कहीं पर 18 प्रतिशत और कहीं पर 12 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। (घण्टी) शिक्षा संस्थानों में 18 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। बी0एस0सी0 (नर्सिंग) में भी 18 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी आया है। मैं कहना चाहता हूं कि एम0बी0बी0एस0 में भी आरक्षण देते, एक या दो सीटें दी जाती जैसे बाकी क्षेत्रों में देते हैं। यहां भी बन्दरबांट हो रही है। आप अन्य शिक्षण संस्थानों में भी तो आरक्षण देते हैं। आयुर्वेदिक में दिया जा रहा है तो एम0बी0बी0एस0 और एग्रीकल्चर कॉलेज़ में देने से क्या फ़र्क पड़ता है? मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि आने

वाले कल को देखते हुए जिला कांगड़ा की 56 प्रतिशत आबादी ओ0बी0सी0 की है। आप वर्ष 2019 के लिए इसे ध्यान में रखें और आरक्षण के बारे में कुछ सोचें।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर पहली बार जब आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जीता था तो माननीय मुख्य मंत्री जी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ था। इन्होंने दो कॉलेज कांगड़ा विधान सभा क्षेत्र में खोले थे। आज मैं उन कॉलेजों की स्थिति आपको बताता हूं। एक कॉलेज में टोटल 600 स्टूडैंट्स पढ़ते हैं और उनमें से 85 प्रतिशत लड़कियां पढ़ती हैं। कई लड़कियां तो ऐसी हैं जो तीन साल तक घर में बैठी रहीं और कॉलेज खुलने के बाद पढ़ना शुरू किया। इन्होंने दूसरा कॉलेज मटौर में खोला और उसकी प्रथम वर्ष में स्टूडैंट्स की संख्या 450 है और वहां पर 90 प्रतिशत लड़कियां पढ़ती हैं। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने मेरे क्षेत्र में एक आई0टी0आई0 खोली है। आपका ट्रैंड तो ठीक है और आप बड़े स्मार्ट हैं तथा अच्छे वक्ता हैं, ऑर्गेनाइजेशन से निकले हैं, पर काम करना माननीय राजा वीरभद्र जी से भी सीख लो। आपको सीखना पड़ेगा। मैं यह कहना चाहूंगा कि इससे पहले भी आपकी सरकारें रही हैं और जो हमारे स्टूडैंट्स कॉलेज न खुलने की वजह से पढ़ नहीं सके, उसकी भरपाई कौन करेगा? यह चिन्ता

14-03-2018/1720/NS/YK/2

का विषय है। यहां पर सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री मौजूद नहीं हैं, लेकिन वे सुन रहे होंगे और मैं उनके ध्यान में लाना चाहूंगा कि कांगड़ा विधान सभा क्षेत्र की जितनी भी इरिगेशन की स्कीमें हैं, वे सारी फेल हैं, defunct हैं। दुर्भाग्यवश जब-जब ये स्कीमें बनी हैं, भारतीय ज़नता पार्टी के समय में बनी हैं। पिछले पांच सालों में माननीय मुख्य मंत्री वीरभद्र जी के आर्शीवाद से बड़ी मुश्किल से इन पानी की स्कीमों को चालू किया था। आज की डेट में कोई भी इरीगेशन स्कीम नहीं चल रही है। हमें इसके बारे में चिन्तन करना होगा। लाखों-करोंड़ों रुपये की पाइपें और मशीनों को देख करके लोग हंसते हैं और कहते हैं कि क्या ये सिर्फ़ बज़ट के लिए आती हैं? क्या ये ठेकेदारों को पैसा कमाने के लिए आती हैं या विभाग में कुछ गोलमाल करने के लिए आती हैं? जब हम वहां जाते हैं तो ज़नता हमसे पूछती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में जितनी भी defunct स्कीमें हैं, इनको

उखाड़ा जाये और इनकी पाईपें काम में लाई जायें। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से ही कह सकता हूं क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी और (***) तो चले गये हैं, फिर भी मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा।

अध्यक्षः माननीय सदस्य कृपया वाईंड अप करें।

श्री पवन कुमार काजलः सर, दो मिनट में बात खत्म करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, यहां पर अन्य माननीय सदस्यों और मैंने जो बज़ट पर चर्चा की, मैं अंत में एक बात कहना चाहूंगा कि जो 68 विधायक यहां पहुंचे हैं, हम सबको मिल करके ये सोचना चाहिए कि प्रदेश कैसे आगे बढ़े? अगर प्रदेश आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। हम सबको इस पर चिन्तन करना चाहिए। ये बज़ट बुक पढ़ करके किसी ने अच्छा-अच्छा बोल लिया और मुख्य मंत्री महोदय के चार कसीदे पढ़ लिये और चार तबादले कर लिए, ऐसा नहीं चलेगा। जो भी ठोस नीति, चाहे वह बन्दरों के बारे में हो या आवारा पशुओं के बारे में हो

(***) अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

14.03.2018/1725/RKS/ए.जी.-1

श्री पवन कुमार काजल... जारी

इसके लिए कोई ठोस नीति चाहे वे बंदरों के बारे में हो, आवारा पशुओं के बारे में हो, सिंचाई या किसी और के बारे में हो, वह बनानी पड़ेगी। अंत में मैं एक बात और कहना चाहूंगा। यह माननीय मुख्य मंत्री जी का पहला बजट था और इसे बड़ी सोच-समझकर तैयार किया गया है। लेकिन कुछ त्रुटियां रह जाती हैं और वे रह गई हैं। अतः मैं इस बजट का समर्थन नहीं कर सकता हूं। धन्यवाद।

अध्यक्षः माननीय सदस्य जी ने एक शब्द (***)का इस्तेमाल किया है। उस शब्द को विधान सभा की कार्यवाही से डिलीट किया जाए। आदरणीय मुकेश जी क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके संज्ञान में एक बात लाना चाहता हूं। बजट सैशन चल रहा है। नई-नई सरकार बनी है और इस सरकार का यह पहला बज़ट है।

माननीय मंत्रियों को ऐसा क्या काम है जोकि पूरा-पूरा दिन सदन से बाहर रहते हैं। इस माननीय सदन की कोई मर्यादा, गरिमा होती है। सभी मंत्री सदन से गायब हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने तो प्रदेश का संचालन करना है लेकिन सभी मंत्री सारा दिन सदन से गायब रहें, यह समझ से बाहर है।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, सारे मंत्री तो आप नहीं कह सकते। दो मंत्री यहां पर बैठे हुए हैं। बाकी मंत्री अभी (...व्यवधान...) ।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः सर, दो मंत्री बैठे हैं। जैसे मंत्रियों को पूल किया गया होता है कि ये मंत्री बैठ रहे हैं। दो मंत्री कल भी बैठे हुए थे और आज भी बैठे हुए हैं। लेकिन सारे मंत्री पूरा-पूरा दिन यहां से गायब रहें तो विधान सभा की क्या गरिमा रह गई? आपको आदरणीय ध्वाला जी, बरागटा जी, पठानिया जी और कर्नल साहब को मंत्री बना देना चाहिए था क्योंकि वे सारा दिन यहां पर बैठ रहते हैं। जो मंत्री बनाए हुए हैं वे तो यहां पर बैठ ही नहीं रहे हैं। इनको ऐसा क्या काम है? इस सदन से महत्वपूर्ण और क्या काम हो सकता है? यह बात समझ में नहीं आ रही है।

14.03.2018/1725/RKS/ए.जी.-2

अध्यक्षः माननीय कृषि मंत्री जी, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे?

कृषि मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री पवन कुमार काजल जी ने दो बातें कही हैं जोकि हमोर रिकॉर्ड में हैं। माननीय सदस्य पवन काजल जी ने आई.टी. पार्क, कांगड़ा की बात की है। मैं इनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि दो सालों से भारत सरकार का पत्र आता रहा है कि आई.टी. पार्क बनना चाहिए। वह आई.टी.पार्क, कांगड़ा में गगल एयरपोर्ट के आस-पास बनना है। उसके लिए अभी ज़मीन फाइनल नहीं हुई है। इसमें दो विधान सभा चुनाव क्षेत्र हैं। एक कांगड़ा और दूसरा शाहपुर। इसके लिए अभी ज़मीन चिन्ह्ति की गई है और उसमें कार्य कर रहे हैं। आपके समय में इसके लिए कुछ भी नहीं हुआ था। आपने जो जमीन देखी थी वह पूरी कवर नहीं हो रही थी। इसके लिए पूरी 21 बीघा जमीन चाहिए। दूसरा, माननीय सदस्य ने कहा कि पूर्व सरकार के समय एस.सी और एस.टी. का

बैकलॉग भरने के लिए कोई विशेष ड्राइव शुरू किया गया था। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस तरह का कोई ड्राइव शुरू नहीं किया गया था। 30 अक्तूबर, 2013 को आपकी सरकार ने एस.सी. और एस.टी. के प्रमोशन कोटे को बंद किया था। मैं आपको यह बताना चाहता था।

अध्यक्षः अभी एक और माननीय सदस्य बोलने वाले हैं इसलिए माननीय सदन का समय 20 मिनट के लिए और एक्सटैंड किया जाता है।

(माननीय सदन की बैठक सायं 5.45 बजे तक बढ़ाई गई।)

14.03.2018/1725/RKS/ए.जी.-3

अब माननीय सदस्य, श्री परमजीत सिंह चर्चा में भाग लेंगे।

श्री परमजीत सिंहः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहली बार इस सदन में निर्वाचित होकर आया हूं। आपने मुझे इस सदन में बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्षः माननीय सदस्य आप ज्यादा बोलिए।

श्री परमजीत सिंहः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो ऐतिहासिक व चमत्कारी बज़ट पेश किया है उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में हर वर्ग को बड़ी राहत देने की कोशिश की है। उसमें चाहे नौजवान हो या किसान-बागवान हो, सभी वर्गों को राहत दी गई है।

अध्यक्ष महोदय, मैं उस निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आया हूं जिसको हिमाचल प्रदेश की आर्थिक राजधानी के तौर पर भी जाना जाता है। उस विधान सभा चुनाव क्षेत्र में जितनी इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं, उनमें हिमाचल प्रदेश के हर जिले, हर तहसील, हर पंचायत से कोई-न-कोई नौजवान रोज़गार प्राप्त कर रहा है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद

करता हूं जिन्होंने उस इंडस्ट्री एरिया को बचाने के लिए विद्युत शुल्क में छूट दी है। जो छोटे उद्योग हैं उनका शुल्क 4% से घटाकर 2% किया है। मंझोले उद्योगों का 10% से घटाकर 7% किया है। आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने जो छोटे और मंझोले उद्योगों को 5 वर्ष तक विद्युत शुल्क में छूट दी है, उसके लिए मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने उद्यम को बढ़ावा देने और युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के लिए जो 'मुख्य मंत्री स्वाबलम्बन योजना' शुरू की है वह भी एक काबिले तारीफ है।

14.03.2018/1730/बी0एस0/वाई0के-1

श्री परमजीत सिंह............ जारी

इस योजना से हिमाचल के 18 से 35 वर्ष की आयु के युवाओं को अनेक सुविधाएं देने की घोषणाएं इस बजट में की हैं। दूसरा सेवा तथा व्यापार के क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं इसलिए इस क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए आदरणीय जय राम ठाकुर जी की सरकार ने एक "मुख्य मंत्री युवा आजीविका योजना" आरम्भ की है, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और उससे वह अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करेंगे और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान होगें। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने युवाओं के साथ एक भद्दा मजाक किया है। उन्होंने बेराजगारी भत्ता देने की बात की थी लेकिन बेराजगारों के साथ जो मजाक किया गया वह अंतिम तीन महीने में सिर्फ 21 हजार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया गया । अध्यक्ष महोदय, आरणीय जय राम ठाकुर जी की सरकार ने युवाओं को 30 लाख रुपये की राशि तक जो भूमि में मकान को छोड़ने के लिए 25 प्रतिशत सब्सिडी देने की बात कही है। इससे हमारे युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा और हमारे जो नौजवान हैं उनको रोजगार के अवसर प्रदान होंगे

अध्यक्ष महोदय, इस बजट में खेलों को बढ़ावा देने के लिए आदरणीय जय राम ठाकुर जी की सरकार ने "मुख्य मंत्री खेल योजना" शुरू की है जिसके तहत हर विधान

सभा क्षेत्र में खेल का मैदान बनाया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इससे दो फायदे होंगे एक तो हमारे युवा खेलों में भाग ले सकेंगे, दूसरा हमारे नौजवान नशे से बचेंगे। आरणीय अध्यक्ष महोदय, 14वें वित्त आयोग ने जिला परिषद, पंचायत समितियों के अनुदान को समाप्त कर दिया गया था। लेकिन आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने उनको 45 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट दे कर जो उनका मान-सम्मान किया है वह प्रशंसनीय है । जिससे हमारे जिला परिषद और पंचायत परिषद के सदस्य अपने क्षेत्र में विकास करवा सकेंगे। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं।

14.03.2018/1730/बी0एस0/वाई0के-2

अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र को विकसित करने के लिए अपार सम्भावनाएं हैं। इसके लिए भी इस बजट में आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने भरस्क प्रयास किए हैं। इसके लिए मैं आरणीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय हैल्थ के क्षेत्र में हमारे आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने एक महत्वकांशी योजना शुरू की है। जिसका नाम "राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना" है। जिसके अन्तर्गत Secondary and Tertiary Hospital में भर्ती के लिए प्रत्येक परिवार को पांच लाख तक की स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, आरणीय जय राम ठाकुर जी की सरकार ने "मुख्य मंत्री राज्य स्वास्थ्य योजना" के लाभार्थियों को भारत सरकार की तर्ज पर स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने की योजना शुरू की है, इसका भी मैं स्वागत करता हूं धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, आज तक कांग्रेस सरकार ने गौ सदन की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी का, जिन्होंने 17 करोड़ रुपये का गौ सदन के लिए प्रावधान किया है। अध्यक्ष महोदय, मजदूरों की दिहाड़ी 210 रुपये से बढ़ाकर 225 रुपये कर दी गई है। आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने विधायक निधि जो 1.10 लाख रुपये थी, पहले ही बजट में 1.25 लाख रुपये कर दी है। जो कि बहुत बड़ा कार्य हमारी सरकार ने विधायकों के लिए किए है। कुछ मेरे साथी इसे 2 करोड़ तक बढ़ाने की बात कर रहे थे मेरा मानना है कि आप फिक्र न करें 2 करोड़ भी हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, ऐच्छिक निधि को भी 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये की गई है इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आरणीय पूर्व मुख्य मंत्री जी का बहुत मान-सम्मान करता हूं लेकिन मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र में जो खनन हुआ है, जो पट्टिकाएं लगीं हैं उसका रिकार्ड शायद हिमाचल प्रदेश् में नहीं हो सकता। 12 तारीख को जिस दिन कोड ऑफ कंडक्ट लगना था, उससे पहले सरकार ने तीन पुलो का शिलान्यास कर दिया। जिनके लिए बजट का कोई प्रावधान ही नहीं था।

14-03-2018/1735/DT/YK/1

श्री परमजीत सिंह------जारी।

तीने पुलों का उद्घाटन कर दिया जो कि आधे-अधूरे पड़े हैं। तीन पंचायत घरों का उद्घाटन कर दिया है और वहां के प्रधान अब मेरे से पैसे मांग रहे हैं और मैं विधायक निधि से उनको पैसे दे रहा हूं। हमारे वहां के प्रतिनिधि इतनी जल्दबाज़ी में थे, पता नहीं उन्होंने कहां जाना था? मुझे इस बात का पता नहीं है। यह सब जल्दबाज़ी में किया गया है। अध्यक्ष महोदय, इतने उद्घाटन किये गये कि एक लाख का जो काम था, उसका उद्घाटन करने के लिए 25,000 रुपये की राशि खर्च कर दी गई। हर गली में और यहां तक कि शौचालयों के ऊपर भी उद्घाटन के पत्थर लगा दिये गये हैं। रसोई घर और शमशान घाट के ऊपर भी पत्थर लगा दिये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय, जैसे इस माननीय सदन के सदस्य राकेश पठानिया जी खनन से चिन्तित हो रहे थे और चक्की खड्ड की बात कर रहे थे, वैसे ही मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक खड्ड निकलती है और उसे सरसा नदी के नाम से जानते हैं। यह हरियाणा से हिमाचल प्रदेश की तरफ आती है और फिर पंजाब में इसका संगम होता है। लेकिन इस खड्ड की बड़ी बुरी दुर्दशा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से अपील करता हूं कि वहां पर एक कमेटी भेजिये और इस इलाके को बर्बाद होने से बचाईये। मेरा विधान सभा क्षेत्र पंजाब के साथ लगता है। मेरा क्षेत्र हरियाणा के साथ टच होता है, 50 मीटर की दूरी से हरियाणा टच हो जाता है। हिमाचल का सारा सोना खनन माफिया ने पंजाब और हरियाणा में पहुंचा दिया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक और रोचक बात बता रहा हूं। खनन माफिया के डोन जैंट्स बहुत सुने हैं लेकिन मेरे क्षेत्र में खनन माफिया की डोन एक औरत है। वह रात को एक-एक बजे तक खड़ी हो करके खनन करवाती है। मैं आपको एक और बात अपने क्षेत्र की इस माननीय सदन में बताना चाहता हूं। मेर विधान सभा क्षेत्र में Central Institute of Plastic Engineering and Technology का उद्घाटन करने के लिए केंद्रीय मंत्री माननीय अनंत कुमार जी और पूर्व मुख्य मंत्री वीरभद्र जी भी साथ आये थे।

14-03-2018/1735/DT/YK/2

वहां पर सवा सौ फुट के करीब एक पहाड़ी थी। जब चुनावों का दौर चला हुआ था तो खनन माफिया ने इस पहाड़ी का नामोनिशान ही मिटा दिया। सर, आप वहां पर कमेटी भेजिये और देखिऐ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय और मंत्री जी से अपील करता हूं कि अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया को बचाना चाहते हैं, इन खनन माफियों से बचाना चाहते हैं तो मेरे क्षेत्र को बचायें। मेरे क्षेत्र की बहुत बुरी हालत है। दस मीटर की दूरी से हरियाणा और 100 मीटर की दूरी से पंजाब शुरू हो जाता है। पंजाब से टिप्पर आते हैं और वहां से भर करके चले जाते हैं। हमारे लोगों को बज़री और रेत नहीं मिलती है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा नहीं बोलूगा, हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी ने जो बज़ट पेश किया है, इसका मैं जोरशोर से समर्थन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

अध्यक्षः अब इस माननीय सदन की बैठक वीरवार, 15 मार्च, 2018 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171004 **सुन्दर सिंह वर्मा**
दिनांकः 14 मार्च, 2018 **सचिव।**